two years back. Only a fortnight back, one lady passenger, Miss Zarina Dastur was travelling in the First Class compartment between Charni Road and Marine Lines and a goonda entered the compartment and tried to snatch away her golden chain. She successfully resisted bravely, caught hold of the goonda and with the help of other passengers handed him over to the Railway Police. Between Hirar and Boriwali, there are lonely stations, like, Meera Road, and Dahisar where this gang of goondas stay in hutments, keep a watch and forcibly enter the First Class compartment and assault the passengers in broad day-light and snatch away their valuables.

Repeated requests have been made to the Railway Minister to check these crimes. In my speech on the Railway Budget, I made a mention of it But I am sorry to find that the hon Minister, in his reply, did not say any thing about it. I would urge upon the Railway Minister to take urgent and drastic steps to curb the activities of the goondas on the suburban trains and firmly deal with them so that there are no more such incidents and the passengers feel a sense of security and safety on both these suburban lines.

SHRI VAYALAR RAVI (Chrayinkil) : Sir, I have also written to you about the same thing.

MR. SPEAKER : Only one Member was permitted.

SHRI VAYALAR RAVI : My concern is that we belong to the linguistic minority living in Maharashtra, in Bombay. I only add one sentence. She said, "I can identify the goonda." But the police did not come in time before her death.

The hon. Home Minister, the other day, assured the House that linguistic minorities will be protected in Maharashtra. But, unfortunately, it has not been done.

13 HRS.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : I am not allowing any one. I am not going to depart from the practice. I have already allowed one...

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Then toworrow, Sir?

MR. SPEAKER : You may try. But, I think, something else is coming up tomorrow.

Mr. Banerjee, please sit down. I have been allowing matters to be raised under Rule 377 which is a marginal thing between point of order and other motions But now every one has started claiming it as a matter of right. I am extremely sorry. In other Parliaments they never allow these things Here we have call-attention and many other things...

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) : Something else is allowed there, but here that is not allowed.

MR. SPEAKER : No where call-attention and other motions which we are allowing here are allowed.

13.03 HRS.

*DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75—*Contd.*

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY—*Contd.*

MR. SPEAKER : Dr. Laxminarain Pandeya to continue his speech.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक मंत्रालय की जिस प्रकार की नीति है उस के कारण औद्योगिक उत्पादन घटा है जिसे स्वयं मंत्री जो ने भी स्वीकार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 1973-74 का उपलब्ध कराया गया है उस के पृष्ठ 13 में लिखा गया है कि उद्योगों द्वारा अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया

* Moved with the recommendation of the President.

[डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय]

गया है। उस मे लिखा है : पिछले कुछ वर्षों मे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विषय मे बराबर यह अनुभव किया जाता रहा है कि बहुत उद्योगों में उन की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नही किया जाता उन की उत्पादन क्षमता का उपयोग भी हर साल कम होता जा रहा है। इस के उत्कृष्ट उदाहरण हैं—

इस्पात और उर्वरक और अभी हाल मे अल्मुनियम भी उसी श्रेणी मे आ गया है। तो इस्पात, अल्मूनियम और उर्वरक का उत्पादन घटा है। 20 तारीख के 'फाइनेंशियल ऐक्सप्रैस" मे भी इसी बात की ओर संकेत दिया गया है कि फर्टिलाइजर का उत्पादन जिस रूप मे होना चाहिये, जितनी आवश्यकता देश को आगामी खरीफ सीजन मे है उतना भी उपलब्ध नही करा पायेंगे। उस मे लिखा है :

"17% fall in fertiliser for kharif crops According to the estimates made by the Ministry the country needs a minimum of 15.43 lakh tonnes of nutrients for the 1974-75 kharif crops. Nitrogen (10.13 lakh tonnes) forms the bulk of it The requirement of phosphorus and potash is 3 33 and 1 97 lakh tonnes respectively"

13 04 hrs.

[Mr Deputy-Speaker *in the Chair.*]

इतनी आवश्यकता होगी लेकिन उत्पादन न होने से आवश्यकता की पूर्ति नही कर सकते। इसी कारण आज अनेक स्थानो पर उद्योगो की हालत खराब है। मंत्री जी ने एक भाषण में स्वीकार किया था कि हम जिन साधनो का जिस प्रकार से उपयोग करना चाहते है उन का उपयोग नही हो रहा है जिन स्त्रानों का दोहन होना था, नही हुआ। एक बार हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने अपने भाषण में जो "हिन्दुस्तान टाइम्स" के 17 अगस्त, 1973 के अंक में छपा है इस बात की ओर संकेत किया है कि उद्योगों ने अपनी क्षमता का उपयोग नही किया है और इसी कारण औद्योगिक उत्पादन में, जो चौथे प्लान पीरियड में उत्पादन हम ने आका था, उस को हम प्राप्त नही कर सके है। जैसा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। मिसाल के लिये कोटन को लीजिये जो उत्पादन हम ने चौथे प्लान पीरियड मे आका था उस के अनुसार जो प्राप्त कर सके है वह बहुत थोड़ा है। ठीक इसी प्रकार से स्टील के बारे मे जो विचार किया था उस मे भी पीछे रहे हैं। फर्टिलाइज का भी यही हाल रहा है और हम इस कमी के कारण हमारी आर्थिक स्थिति, पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। कागज की कमी आज भयकर है। कागज उद्योग पर उचित ध्यान दिया होना तो सभवत: यह स्थिति न होती।

जहा तक टैक्सटाइल इडस्ट्रीज का सवाल है उस के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण प्रगति नही हुई है। जैसा कई माननीय सदस्यो ने सकेत किया है कि जो कट्रोल्ड कपडा है उस की जितनी उपलब्धी जनता को करायी जानी चाहिये थी, प्रति व्यक्ति जितनी खपत होनी चाहिये, उस मे कमी इस बात का प्रमाण है कि जनता को उपलब्ध नही करा सके हैं। लेकिन उस के विपरीत आर्ट मिल्क और रेयान का उत्पादन बढा है। लेकिन मोटे कपडे का नहीं बढा। जो हमने अनुमानित किया था उससे विभिन्न उद्योगो के लिये स्टील, सीमेंट, अन्य उपकरण और बिजली वाछित-मात्रा मे उपलब्ध कराने मे सरकार असमर्थ रही है और इसी कारण कई उद्योग बिजली के अभाव मे बन्द हो रहे है। तो कई स्टील के अभाव मे आज के "टाइम्स आफ इंडिया" समाचार-पत्र मे आया है कि

"Power-less Haryana in for deep crisis Haryana is heading for utter industrial chaos if the Union Government does not come to its rescue with power supply from other States on an emergency basis."

यदि भारत सरकार ठीक से पावर की सप्लाई नहीं करती है तो फ़रीदाबाद और आसपास की इंडस्ट्रीयल यूनिट्स का उत्पादन गिरेगा और उस का असर कुल मिला कर हमारे उत्पादन पर भी पड़ेगा। मंत्री जी ने स्वयं अपने मंत्रालय की 1973-74 की रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आयी है, और आगे भी यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो गिरावट आ सकती है। और जो उन्होंने संकेत दिये हैं उन में इन्होंने प्रमुख रूप से बिजली की कमी को बताया है :

"1. Inadequate capacity of plants; 2. operational problems in industrial units (steel, fertilisers); 3. lack of maintenance (steel, fertilisers); 4. design deficiencies (steel, fertilisers); 5. shortfalls in investment (capital goods); 6. shortage of steel, non-ferrous metals (engineering industry); 7. shortages of power, coal and movement problems (all industries); 8. unsatisfactory industrial relations; 9. shortage of construction materials; 10. larger reliance on domestic equipment and technology."

कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय को उधर ध्यान देना चाहिए।

डिजाइन में डिफेक्ट की वजह से भी कई उद्योग ऐसे हैं जो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहें हैं। या किसी कारण से अगर चलाये जाते हैं तो बाद में जा कर डिजाइन डिफ़ेक्ट की वजह से कमी आ जाती है और उत्पादन जिस रूप में चाहते हैं वह नहीं होता है। स्टील इंडस्ट्रीज के अन्दर हम को अनुभव है कि बारबार उन की डिजाइन में डिफ़ेक्ट होने से, चाहे दुर्गापुर हो या रूरकेला हो, इन के उत्पादन के जो लक्ष्य हम ने निर्धारित किये थे उन को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। स्टील के उत्पादन में गिरावट का यह प्रमुख कारण रहा है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये।

इसी प्रकार से सीमेंट की हालत है। सीमेंट की मांग बढ़ रही है, लेकिन मंत्री महोदय ने माना है कि सीमेंट उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। अनेक क्षेत्रों में सीमेंट के लिये रा-मैटीरियल भरा पड़ा है लेकिन सीमेंट कोपोरेशन आफ़ इंडिया को जहां जहां फैक्ट्री लगाने के लाईसेंस दिये हैं वहां फ़ैक्ट्रीज लगने में विलम्ब हुआ है। उदाहरण के लिये में आप को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निमंच में सीमेंट फैक्ट्रीज हेतु लाइसेंस मिला। किन्तु अभी स्थान का ही चुनाव हो रहा है, जब कि मध्य प्रदेश के अनेकों स्थानों के बारे में चौथी योजना में विचार हुआ लेकिन आज तक सीमेंट कोरपोरेशन आफ़ इंडिया नीमच में भी सीमेंट की फैक्ट्री डालने में असमर्थ रही है। यह हमारी दोषपूर्ण नीति का परिणाम है। इसके कारण जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं है उनकी कमी अनुभव की जा रही है। सिमेंट की कमी दूर करने में मंत्रालय असमर्थ रहा है और इसी तरह से दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने में भी वह असमर्थ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से भी घाटा ही हो रहा है लाभ नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में आम धारणा यह है कि वे सार्वजानिक क्षेत्र के उद्योग नहीं बल्कि सरकारी उद्योग मात्र हैं और केवल सरकारी भाषा का ही वे अनुसरण करते हैं उनका दृष्टिकोण सार्वजनिक नहीं और ऐसा करने से उनमें हजारों करोड़ रुपये की जो पूंजी लगी हुई है उसके बावजूद भी उन में घाटा हो रहा है। सौ से अधिक यूनिट्स सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और अधिकांश उन में—ऐसे हैं जो अनुत्पादक हैं, जिन के बारे में कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपये का घाटा आज उनके अन्दर हो रहा है। उन में लाभ होना चाहिये, घाटा दूर होना चाहिये। उनका प्रबंध संचालन ठीक हो यह आवश्यक है।

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

दूसरी तरफ आप देखें कि एकाधिकार प्राप्त जो घराने है उन पर भी कोई नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। टाटाज हो या बिड़लाज हों उन के एसेट्स बढ़ते ही जा रहे है। उसके कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये था, प्रश्रय मिलना चाहिये था, नही मिला है। मैं समझता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो या निजी क्षेत्र के उद्योग हो इन दोनों मे भेद भाव करने की नीति को हमको छोड़ देना चाहिये इन दोनो मे पारस्परिक समन्वय की नीति होनी चाहिये। एक बार मंत्री महोदय ने ज्वायट सैक्टर की बात कही थी। ज्वायट सैक्टर का क्या स्वरूप होगा या सबुक्त उद्योगो का क्या स्वरूप होगा, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार का होगा, उनके अन्दर भागीदारी किस प्रकार की होगी, मजदूरो की भागीदारी किस प्रकार की होगी, जनता की या सरकार की किस प्रकार की होगी, सरकार उन मे कितने प्रतिशत शेयर लेना स्वीकार करेगी अथवा जनता को कितने प्रतिशत शेयर देना स्वीकार करेगी, इसका कुछ भी पता नही है, इस का कुछ भी स्पष्टीकरण नही किया गया है, कोई स्पष्ट चित्र हमारे सामने नही रखा गया है। इस कारण से ज्वायट सैक्टर की जो कल्पना है वह केवल अधूरी कल्पना मात्र बन कर ही रह गई है। ज्वायट सैक्टर हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, इन मे भेदभाव करने की नीति को छोड़ कर उद्योग के तथा उत्पादन के हित की बात को हमको सोचना होगा, देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से प्रबल और सुदृढ़ हम बना सकते है, इसको सामने रख कर सोचना होगा और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नेशनल सैक्टर के स्वरूप को विकसित कर कार्य करे। उद्योग किसी भी स्थान पर खड़े हों हमको देखना होगा कि उत्पादन में हम वृद्धि लाएं फिर चाहे वह शक्कर का उत्पादन हो, सिमेंट का हो, फर्टिलाइजर का हो। चाहे जिस किसी भी क्षेत्र के कारखाने हों अगर हम चाहते है कि उनके उत्पादन में वृद्धि हो तो उनकी जो पूंजी की आवश्यकता है, उनके वास्ते जिस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है कच्चे माल की आवश्यकता हो, उनको हमें उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना होगा।

हमारे यहां विदेशी पूंजी का प्रभुत्व बढ़ रहा है। आंकड़े इसको सिद्ध करते हैं। विदेशी कोलोबोरेशन से, विदेशी सहयोग से, विदेशी टैक्नालाजी से, विदेशी नो हऊ से हमारे यहां कारखाने बढे हैं। नो हऊ हम प्राप्त करें और उनके आधार पर कारखानो का विस्तार हो, इस से कोई दो राय नही हैं मतभेद नही हैं। लेकिन अगर विदेशी पूंजी बढ़ती है तो यह चिन्ता का विषय हो जाता है। जो आकडे उपलब्ध है उनके अनुसार लगभग 72 नए कारखानो में विदेशी पूंजी लगने वाली है, इसकी सरकार ने—अनुमति दी है। इससे विदेशी पूंजी का प्रभुत्व बढ़ेगा। पहले से भी यह बहुत बढा है। कालगेट को आप ले, हिन्दुस्तान लिवर को ले या इस प्रकार की दूसरी कम्पनियों को लें आपको पता लगेगा कि करोड़ों रुपये की नही अरबों रुपये की पूंजी उन्होने हमारे देश से अर्जित की है। आपको एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये कि विदेशी कम्पनियां जो पूंजी वे कमाती हैं उसका कितना प्रतिशत भाग बाहर भेज सकती हैं,—प्रतिशत तय कर दिया जाना चाहिये और उस प्रतिशत से अधिक मुनाफा उनको बाहर भेजने की इजाजत नही होनी चाहिये।

प्लानिंग कमीशन की एक्सपर्ट बाडी ने यह बताया है कि इम्पोर्ट में जो डिलेज होती है मशीनरी वगैरह की उसके कारण 335 करोड़ की हमको हानि हुई है। इसी तरह से जो हम ऐक्सपोर्ट करते हैं उन में भी अननेसिसरी डिलेज होती हैं। उनके कारण भी करोड़ों रुपये की हानि होती है। उसको बचाया जाना चाहिये आपको तय करना चाहिये कि किस प्रकार से इन डिलेज से बचा जा सकता है ताकि हमें हानि इस तरह से न उठानी पड़े।

यह हमारी कार्य प्रणाली का दोष है । इसे हम दूर करें।

जनवरी में स्टेट मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी । मंत्री महोदय उस में नहीं गए । लेकिन 23 जनवरी, को समाचार आया कि उस कान्फ्रेंस में यह घोषणा की गई कि हमें सिमट शक्कर आदि की देश के अन्दर खपत को कम करना चाहिये क्योंकि इनका निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं । मकान बनाने हों तो लोगों को सिमेंट मिलना चाहिये । शक्कर की लोगों को आवश्यकता है उनको शक्कर मिलनी चाहिए । यह भी जरूर है कि हमें विदेशी मुद्रा भी चाहिये । लेकिन विदेशी मुद्रा के नाम पर आप देश की जनता को भूखा नंगा नहीं रख सकते हैं बिना खाए के नहीं रख सकते हैं, इनकी जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति में उनको वंचित नहीं कर सकते हैं । यह कहा गया था कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों की खपत को हमें देश में घटाना होगा । यहां चाहे ये उपलब्ध न हों लेकिन हमको इनको बाहर जरूर भेजना होगा । इस प्रकार की औद्योगिक नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता । इसके लिए जरूरी है कि आप उत्पादन बढ़ाये । उत्पादन के अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा मान करें। निर्यात और आन्तरिक खपत में आपको सन्तुलन रखना होगा । औद्योगिक नीति में अभी तक इस प्रकार के सन्तुलन का अभाव रहा है। सन्तुलन नाम की कोई चीज अभी तक देखने को नहीं मिली है । इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । केवल आंतरिक खपत या निर्यात में ही संतुलन की आवश्यकता, नहीं है अपितु देश के औद्योगिक समग्र विकास में यह संतुलन हो ।

आप यह भी देखें कि देश के कुछ भाग विकसित होते जा रहे हैं, दूसरे पिछड़ते जा रहे हैं । वे विकसित नहीं हो रहें हैं । चारों तरफ से इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं । पिछड़े हुए इलाकों में जिस प्रकार से उद्योग लगने चाहिये नहीं लगे हैं । सरकार घोषणा तो करती रहती है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन उसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता है । मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले, बस्तर और सरगुजा में बाक्साइट काफी मात्रा में उपलब्ध है जिसमें एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है । एक कारखाना बालको के नाम से नेकोरवा में लगाया है । लेकिन उस में केवल एल्यूमीना बन रहा है । स्मलटज के अभाव में एल्यूमिनियम नहीं बन रहा है। स्मैलटर्ज भी साथ साथ लगाने चाहिये थे । ये नहीं लगे इस कारण से करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है । बस्तर में भी कारखाने लगाने की काफी गुंजाइश है । काल बेस्ड इंडस्ट्रीज वहां बन सकती हैं । लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं है । ऐसे ही दूसरे राज्य का उदाहरण लें तो राजस्थान में राक फास्फेट आयरन और आदि खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं किन्तु वहां इनके आधार कोई बड़े कारखाने नहीं बनाए गए हैं । जहां तक कारबा का सम्बन्ध है जिस गति से वहां काम हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि पांच वर्ष में भी वह बन कर तैयार हो जाएगा । कई उद्योगों की कैपेसिटी अनयुटिलाइज्ड पड़ी हुई है उसका प्रापर युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है । इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि कुछ मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां हो सकती हैं । लेकिन उनको भी आप दूर करें। आप टैक्सों पर टैक्स लगाते जा रहे हैं । ऐसा करके आपने जनता के जीवन को दूभर कर दिया है । उसके ऊपर आपने भारी टैक्सों का बोझ लाद दिया है । फिर भी अगर उत्पादन यथेष्ठ नहीं होता है तो इसका एक मात्र कारण नियोजन में दोष होना है । प्लानिंग हमारा दोषपूर्ण है । अनेक प्रोजैक्ट्स हैं, निर्माणाधीन हैं चाहे वे स्टील के हों, इरिगेशन के हों या दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स हों इस प्रकार के लगभग 64 प्रोजेक्ट्स हैं

[डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय]

जिन की कीमत आज या तो दुगुनी हो गई है या दुगुना खर्च पर उन पर होने की संभावना है। यह इस लिए हुआ है क्योंकि हमारा जो सारा आयोजन है वह ठीक नहीं। केवल विदेशों के आधार पर, विदेशी तकनीकी के आधार पर, विदेशी यांत्रिकी के आधार पर, विदेशी नौ हऊ के आधार पर हम नहीं चल सकते हैं, हम को स्वदेशी आधार पर सोचना और विचार करना होगा। हमारे देश में लोग हैं जो अपने नौ हऊ से बहुत अच्छा स्टील बना सकते हैं, दूसरे क्षेत्रों में बहुत अच्छे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, उत्पादन की दिशा में आगे आ सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान खड़े कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि हैवी इलैक्ट्रिकल्ज भोपाल में मशीनरी के किसी विशेष कम्पोनेंट की आवश्यकता पड़ी, उसको उपलब्ध कराने में रूस का अपना मत था ब्रिटेन का अपना मत था फेल हुआ लेकिन एक छोटे से इंजीनियर ने उसको तैयार कर दिखाया बाहर का नौ हऊ इस में असमर्थ रहा हमारे यहां के नौ हऊ वे इसको कर दिखाया। सरकार इस प्रकार के नौ हऊ को प्राप्त करे और इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दे। ऐसा सरकार नहीं करती है। मैं समझता हूं कि यह इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल डैमट्रक्शन डिपार्टमेंट है और इसी रूप में हमारे सामने आया है।

आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई हैं और बना रहे हैं। लेकिन ये कहां बन रही हैं? बम्बई के पास बन रही हैं, नागपुर के पास बन रही हैं, दिल्ली के पास बन रही हैं, फरीदाबाद में बन रही हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं उन्हीं के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रही हैं। छोटे शहरों के पास बनती हैं तो उनको रामैटीरियल नहीं मिलता है, बिजली सप्लाई नहीं की जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है। आप स्वयं जा कर देख सकते हैं कि वे शेड खाली पड़े हैं इनका वैज्ञानिक आधार पर विकास हो, कोआर्डिनेशन हो। रामाटिरियल की उनको आवश्यकता होती है तो पहले जिस जिले में वे होती हैं उस जिले के अधिकारी के पास जाना पड़ता है और जिला अधिकारी जब सन्तुष्ट हो जाता है तो वह उनके केस को उस प्रान्त की राजधानी को रिकमंड करता है और वहां अगर काम बन सकता है तो वहां बनता है और अगर नहीं बन सकता है तो दिल्ली और कलकत्ता उनको जाना पड़ता है इस प्रकार विभिन्न मामलों में कई स्थानों व कई मंत्रालयों के चक्कर काटना पड़ते हैं।

कोई इंटैग्रेटिड सिस्टम इस के लिए आप क्या लागू नहीं कर सकते हैं, कोई व्यावहारिक हल आप इसका नहीं निकाल सकते हैं? आप कोई लिमिट बांध सकते हैं कि इस लिमिट तक तत्काल उनको जिले में ही परमिट मिल जाए या लाइसेंस मिल जाए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि छोटे उद्योगों को चालने में उनको सुविधा होगी, वे चल भी सकते हैं।

इस तरह उन में काफी प्रगति हो सकती है, उन की काफी उन्नति हो सकती है।

कंट्रोल्ड आइटम्ज के बारे में चारों तरफ से शिकायत है कि वे लोगों को नहीं मिलती हैं। सरकार को उन के वितरण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। या जिन्हें मिलती है व उनकी काला बाजारी करते हैं। इस प्रक्रिया को ठीक करना चाहिये।

इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक वाणिज्यिक बैंक और स्टेट फिनांस कार्पोरेशन्ज की हालत यह है कि आप यद्यपि सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज को निरन्तर चक्कर काटने के बावजूद ऋण नहीं मिलता है।

विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बारे में बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच डाइफ़रेंशन होना चाहिए, कोई सीमा-रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। उदाहरण

के लिए कपडा मिले ऊंची किस्म का कपडा बनाये लेकिन टावल और चादर बनाने का काम हैंडलूम और पावरलूम के लिए सुरक्षित रखा जाये । टावल और चादर का उत्पादन किसी बडी कपडा मिल में नही होना चाहिए ।

इस बात की भी कोई आवश्यकता नही है कि हिन्दुस्तान लीवर साबुन और कासमेटिक्स का, या कालगेट टेल्कम पाउण्डर, या अन्य दैनिक उपभोग की वस्तु का निर्माण बडे पैमाने पर करे । इन वस्तुओ का उत्पादन छोटी-छोटी कोटेज इडस्ट्रीज में किया जाना चाहिए, जिस से हम काफी लोगो को रोजगार दे सकते हैं । हमारा सकल्प है कि हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारेगे । इस के लिए आवश्यक है कि गावो मे रोजगार के अवसर पैदा हो और रूरल इडस्ट्रिज का विकास हो । इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि विभिन्न वस्तुओ के उत्पादन के विषय मे सीमा-रेखा निर्धारित की जाये । परम्परागत व कुटीर उद्योगो के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना जरूरी है ।

आज लाइसेंसिज की सारी पावर केन्द्रीय सरकार के हाथ मे है । स्टेट्स छोटे उद्योगो के बारे मे भी लाइसेंस नही दे सकती हैं । इस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दौडना पडता है । इस लिए यह आवश्यक है कि लाइसेंसिंग पालिसी पर पुनर्विचार कर के लाइसेंसिंग की व्यवस्था का डीसेन्ट्रलाइजेशन किया जाये ।

एक तरफ सार्वजनिक उद्योग कोई अच्छी स्थिति में नही है और दूसरी तरफ निजी उद्योग चिन्तित और भयभीत है, क्योकि वे समझते हैं कि नेशनलाइजेशन की तलवार उन के सिर पर लटक रही है। अगर वे कोई पूजी लगाते है तो सरकार कभी भी हमारी पूजी पर हाथ डाल सकती है । निजी उद्योगो के भय को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार यह तय कर दे कि कि हम अमुक समय तक—फिर चाहे वह पांच बरस तक या दस बरस तक का समय हो—टैक्सटाइल, शूगर या किसी अन्य उद्योग का राष्ट्रीयकरण नही करेगे । इस से उन उद्योगो मे पूजी लगेगी, राटन मशीनरी के स्थान पर नई मशीनरी लगाई जायेगी और उत्पादन भी बढ सकेगा ।

कानज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओ की माग बढ़ती जा रही है, लेकिन आज वे लोगो को उपलब्ध नही है और अगर उपलब्ध होती भी है, तो महगे दामो पर । छोटी छोटी इडस्ट्रीज को उपभोक्ता वस्तुओ के निर्माण में जो सरकार की तरफ से योगदान देना चाहिए, वह नही मिल रहा है दूसरी तरफ विदेशी प्रभुत्व और विदेशी पूजी वाली कम्पनिया लक्सरी गुड्ज बना रही है । इनके उत्पादन मे 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस स्थिति मे उपभोक्ता वस्तुओ की कमी होती चली जा रही है । गत 6 मास में ही इनकी कीमते 13 प्रतिशत बढी है । हम देखते है कि विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनिया उपभोक्ता वस्तुओ के निर्माण के क्षेत्र मे अपने पाव फैलाती जा रही है। उन को नियत्रित करना चाहिए और विदेशी कम्पनियो का भारतीयकरण किया जाना चाहिए—उन की दो-तिहाई पूजी भारतीय होनी चाहिए ।

नेशनल स्माल-स्केल इडस्ट्रीज कार्पोरेशन मशीनो का आयात करती है । लेकिन जो मशीने अनेक वर्षो से मगाई हुई है, वे बेकार पडी हुई है । उनका उपयोग ठीक ढग से होना चाहिए । आज लाखो रुपये की आयातित मशीने कार्पोरेशन के पास बेकार पडी है ।

हमारे चमडा उद्योग, कायर उद्योग, ऊन उद्योग और अन्य उद्योगो की कोई खास अच्छी स्थिति नही है । उन की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए । औद्योगिक विकास मे ट्रासपोर्टेशन का बडा महत्व है उसका भी ताल मेल आप बिठा दे ।

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

आयात और निर्यात प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल बनाना चाहिए, जिस के आधार पर वास्तविक उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। मैं पुन. दुहराना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रभुत्व और एकाधिकार ठीक नहीं है, उसी तरह सरकार का प्रभुत्व बढ़ना भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। इसीलिए हमें राष्ट्रीय क्षेत्र को कम करना करनी चाहिए।

सभेर में मध्य प्रदेश के बारे में निवेदन करना चाहूंगा—मेरे क्षेत्र में ओपियम काफी मात्रा में पैदा होता है। इसलिए नीमच या मंदसौर में ओपियम बाई-प्राडक्ट्स के कई कारखाने लगाये जा सकते हैं। वहां एलकलायड फैक्टरी लगाई जा रही है, लेकिन पापी हल्क के आधार पर वहां कई कारखानों की स्थापना की जा सकती है। इसी मंदसौर जिले की जावर तहसील में आयरन ओर उपलब्ध है उसका उपयोग होना चाहिये। । मध्य प्रदेश में मरगुजा और बस्तर में बाक्साइट काफी मात्रा में मिलता है। इस लिए वहां पर एक ओर एल्युमिना प्लांट लगाया जा सकता है। खरगोन, रतलाम, आदि जिलों में लाइम-स्टोन काफी मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए मध्य प्रदेश में और सीमेंट फैक्टरियां लगाई जा सकती हैं। नीमच की सीमेंट फैक्टरी के बारे में काफी विलम्ब हुआ है। उसे जल्दी लगाया जाये।

मध्य प्रदेश में पानी, बिजली और रा मैटीरियल है, वहां कोयला, तांबा, मैंगनीज, बाक्साइट, लाइमस्टोन और बांस के घने जंगल हैं। लेकिन औद्योगिक दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ है। इसलिए देश के औद्योगिक मानचित्र में उस को स्थान देने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। आज हमारे देश में औद्योगिक विकास असंतुलित ढंग से हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि सब राज्यों में समान रूप से औद्योगिक विकास हो, इस को दृष्टि में रखते हुए हम एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का पालन करें और वर्तमान नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करें। तभी हमारी औद्योगिक प्रगति का वास्तविक स्वरूप सामने आयेगा, हम औद्योगिक दृष्टि से आगे होंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have a request from the Whip of the Congress Party to allot ten minutes each to each Member from the Congress Party I shall co-operate with him and ring the bell at the proper time

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Some Members are absent. So, their time may be given to the others

MR DEPUTY-SPEAKER: The list is a very long one It is his party's arrangement, and I am only co-operating I am giving them only the party's time

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, नीतियां कितनी भी अच्छी हों, जब तक निष्ठा और ईमानदारी से उनका पालन नहीं किया जाता है, तब तक वे नीतियां केवल किताबों में रहती हैं। 1956 का इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन भी है, लाइसेंसिंग पालिसी भी है और एम० आर० टी० पी० एक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जो नीति है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होता है?

17-4-73 को एक सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि टाटा के प्राफिट्स 1969-70 में 32 78 करोड़ रुपये थे और 1970-71 में वे बढ़ कर 53.57 करोड़ रुपये हो गये। इसी तरह बिड़ला के प्राफिट्स 1969-70 में 51.60 करोड़ रुपये थे, जब कि 1970-71 में वे बढ़ कर 61 58 करोड़ रुपये हो गये। इससे साबित होता है कि हिन्दुस्तान में पूंजीवाद

बढ़ रहा है । हम कानसेनट्रेशन आफ़ इकानोमिक पावर नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह बढ़ रहा है । इस बात का भय है कि कहीं ये पूंजीपति राजनीति पर हावी न हो जायें और राजनीति उन की चेरी न बन जाये । इस से लोकतन्त्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है । हम लोकतांत्रिक समाजवाद लाना चाहते हैं । उस में पूंजीवाद का खात्मा होना जरूरी है । लेकिन सरकार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ?

"The Commission, which was represented by a retired judge of the Calcutta High Court, used three main arguments to show that IDBI had in fact shown undue favour to the Birlas."

The time at my disposal is short; otherwise, I can read more from the article to show how favour has been shown. This is the report of the commission appointed by Government themselves.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM) : The commission has not submitted its report. This is unfair.

SHRI M. C. DAGA : I am reading from the *Economic and Political Weekly* from an article entitled 'Public Money for Private Enterprise'. It is dated the 12th January, 1974. If the hon. Minister would read the whole article, he will see the arguments which have been advanced.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It may be an article, but it is not the Commission's report. The report has not yet been submitted.

SHRI M. C. DAGA : It appears under the heading 'Sarkar Commission'.

इनवेस्टमेंट कैसे होता है ? 1968-69 में 85 करोड़ रुपये, 1969-70 में 111 करोड़ रुपये, 1970-71 में 133 करोड़ रुपये और 1971-72 में 162 करोड़ रुपये । इसका मतलब यह है कि पूंजीपतियों को बराबर पूंजी मिल रही है । कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि उन को पूंजी क्यों मिल रही है । हर एक जानता है कि पूंजीपतियों को डिसबर्समेंट होता है ।

सरकार का कहना है कि रिजनल इमबैलेंस नहीं होना चाहिए । एस्टीमेट्स कमेटी की 1972 की रिपोर्ट में कहा गया है—मेरा खयाल है कि यह मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को पढ़ती होगी :

"The Committee regret to note that barring four or five States, other States do not attach that much priority to small-scale industries as they deserve".

This means that other States have neglected this. I do not want to go through the whole report. But this observation would be found at page 12 of the Thirty-Fifth Report of the Estimates Committee (Fifth Lok Sabha).

आप की कमेटी की रिपोर्ट इस बात को साबित करती है । आप का जो इम्बैलेंस है स्टेट्स में उस की बात मैं आप को बता रहा हूं :

"Advances made by the commercial banks also indicate that Rajasthan share is 1 per cent as against 30 per cent advances given in Maharashtra, 19 per cent in West Bengal, 11 per cent in Tamil Nadu and 6 per cent in Gujarat. *Per capita* investment by these banks in Rajasthan is only Rs. 18.2 as against Rs. 69.4 for the country as a whole and Rs. 231.6 in Maharashtra, Rs. 136.7 in West Bengal..."

See how Rajasthan has been neglected.

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore) : All of Rajasthan is now in Calcutta, West Bengal.

SHRI M. C. DAGA: This is the argument being advance. I am pointing out how our State is being neglected.

यह राजस्थान के इम्बैलेंस की बात मैं ने आप के सामने रखी। आप खुद मानेंगे इस बात को। वह कह रहे हैं .—

"The Committee are concerned to note that many of the small scale industries are working on outmoded technology and many of the small scale service institutes in the States are not well equipped to give guidance in modern lines of industry".

आप का सारा जो स्टेट्स का काम है मेरी समझ में नहीं आता है कि आप सारा कसंट्रेशन सेंटर में क्यों कर के रखना चाहते हैं। स्टेट्स पर कुछ जिम्मेदारी डालिए। स्टेट्स के अंदर लोग अगर अपने अपने यहां की इंडस्ट्री को नहीं देखते हैं, अधिकारी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या लाभ है ? आप ने सारी पावर सेंट्रलाइज कर के रखी है। एक तरफ तो आप डीकंट्रोल करना चाहते हैं दूसरी तरफ सारी पावर को सेंट्रलाइज कर रखा है। आप के विभागों में क्या होता है कि सारा पावर आपने पास सेंट्रलाइज कर के रखते हैं। आज पावर लोगों को अवेलेबल नहीं है, पावर की शार्टेज है, रा मैटीरियल की शार्टेज है। कौन उस की जिम्मेदारी लेगा ?

मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं। अब नौकरशाही आप की लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं, उस के लिए डैडीकेटेड लाइफ उस की नहीं। उसका एटीट्यूट, उस का बिहेवियर, उस का काम करने का तरीका सब उस के विपरीत है। मैं पूछता हूं आप ने आज तक किसी अधिकारी का, किसी स्टेट के इंडस्ट्रीज आफिसर का एक्सप्लेनेशन काल किया ? आखिर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और सब कुछ करने के बाद भी, क्या कोई उस की जिम्मेदारी लेता है ? सारी मशीनरी आप की किस प्रकार से डील करती है उस का एक उदाहरण मैं देता हूं एक अप्लीकेशन 23-3-73 को दी गई। वह एकोनामिक ऐडवाइजर के पास जून 73 में गई।

Sanction of the Economic Adviser was received in DETD in August, 1973. Allocation letter by DGTD was issued on 3-9-73 to CCI & E Licences and release order was issued by CCI & E on 1-12-73. Material sale orders issued by MMTC, New Delhi, on 25-1-74 against which no material yet arrived

यानी एक बात है।

In 1973, he had applied. It is now 1974 But he has not got the raw material This is a procedure which is laid down. Applications should be disposed of within a short time.

आप सारी अप्लीकेशन को डिस्पोज आफ कीजिए विदिन ए वेरी शार्ट पीरिअड एक आदमी 1973 में आप को कहता है कि मैं रा-मैटीरियल चाहता हूं और 1974 तक उस को रा-मैटीरियल नहीं मिलता है तो यह क्या तरीका है काम करने का। एक अप्लीकेशन जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है काम कुछ नहीं होता।

I want raw materials This is one instance which I have quoted I can give you in writing.

आखिर आज किस प्रकार से आप के आफिसर्स डील करते हैं। कोई गवर्नमेंट हो, उस का डाइरेक्टर यह समझता है कि यह मेरी रेस्पांसिबिलिटी नहीं है। पावर नहीं मिलती, रा मैटीरियल नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता और कोई उस की जिम्मेदारी नहीं लेता। आखिर किसी की रेस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए।

अब मैं एक बात कहना चाहता हू कि आप के लेबर का क्या हाल है वह देखिए । आप के जो अपने सेक्टर्स है उस में क्या हाल है ।

'The third five year Plan has observed that for the peaceful revo lution of the economic system on a democratic basis, it is essential that workers' participation in the management should be accepted as a fundamental principle and urgent need"

Has it been implemented or not

यह थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर दिया हुआ हुआ है । आखिर वर्कर्स का आप पार्टिसिपेशन चाहते है या नही ? अगर नही चाहते है तो कहिए कि हम नही चाहते । लेकिन चाहते है तो आप के खुद के सैक्टर्स मे वह नही है । तो कैसे आप समझते है कि यह होगा ? आप कहते है कि इस मे लेबर के अन्दर इसेंटिव पैदा होगा । यह आप का टेक्नोलाजिकल डिपार्टमेंट है

The number of Indian scientists abroad who registered themselves with the CSIR during the third Plan was about 6,900 A detailed breakdown of the limited available data is provided in Table 3 7 to show the seriousness of the Brain Drain' problem in the Indian context'

What is the sense ?

अगर साइंस और टैक्नोलाजी मे सारा ब्रेन ड्रेन होता हो, सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर बाहर चले जाते हो आप के देश मे कोई रिसर्च न होता हो और केवल खर्चा ही खर्चा होता तो ह्वाट इज दी सेंस ?

Here is the Report of the Public Accounts Committee

'The Committee had an occasion to review certain aspects of the working of the NRDC and the CSIR in 1969-70 and from the information made available to the Committee with regard to the working of the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, the Committee finds that during 14 years of its existence, the institute incurred an expenditure of Rs 6 92 crores, out of which about Rs 3 87 crores was of a recurring nature"

You will kindly go through this report and find out what the technical institutions are doing

MR DEPUTY-SPEAKER That is a good sentence to conclude with

SHRI M C DAGA I am finishing It says that the expenditure incurred on pay and allowances on the staff during the year 1971-72 was Rs 43 87 lakhs, and for non-academic staff it was Rs 27 lakhs

आप का एक्सपेंडीचर बढता जाता है और इधर आप का ब्रेन ड्रेन हो रहा हो । आपके साइंटिस्ट्स काम नही कर रहे है, आप के इंस्टीट्यूशंस वर्क नही कर रहे है। (व्यवधान) मैं एक मिनट मे समाप्त कर दूगा ।

आप ने मेहरबानी कर के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस के अन्दर जोधपुर को ले लिया, सिरोही का ले लिया जालौर का ले लिया लेकिन बीच मे पाली को छोड दिया । पाली मे हाथ से काम करने वाले हैंड प्रोसेस मे काम करने वाले लोग है । वह हाथ से काम करते है फिर भी उन के ऊपर ड्यूटी लगती है । वह पावर काम मे नही लाते सारा काम हाथ से करते है । पन्द्रह सौ रुपये की उन की मशीन और 3 हजार रुपये उस के ऊपर कम्पाउन्ड एक्साइज ड्यूटी लगाते है किस प्रकार से वह आगे बढ सकते है । शार्ट टाइम मे इतना ही कह कर मे समाप्त करता हू ?

SHRI K S CHAVDA (Patan) Mr Deputy Speaker Sir within the 10 minutes at my disposal I would like to deal with only the foreign sector vis a vis the Indian sector in relation to the industrial development that is taking place in our country

[Shri K. S. Chavda]

Sir, at the outset, I would like to make it clear that I am not against foreign firms as such. But, at the same time, I do feel that the foreign firms should not exploit the Indian Industries. In the initial stages of industrial development in our country, we took the help of foreign firms, and as industries in India developed, we should have reduced our dependence on foreign firms. But, this is on the increase and Government is giving encouragement to foreign firms to grow bigger and bigger at the cost of Indian industries.

Take for example, Pfizer limited. Their initial equity was Rs. 2 lakhs and at present, their equity is Rs. 5.6 crores. The assets built up by the Company from out of their profits are worth Rs. 52 crores The amount repatriated directly to America, in the year 1970, was Rs. 63.13 lakhs; in the year 1971, it was Rs. 68.20 lakhs and in the year 1972, it was Rs. 68.21 lakhs. I would like to give another example of Glaxo Laboratories. Their initial equity was Rs. 1.5 lakhs and their present equity is Rs. 7.5 crores. Their assets are now worth Rs. 65 crores. Further, they have repatriated large amounts from out of their profits made in this country. Another example is that of Firestone. They have increased their assets from Rs. 20.000 to Rs. 55 crores I do not want to take the time of the House by giving more examples. But, I would certainly ask Shri C. Subramaniam, Minister of Industrial Development, through you, Sir, to explain to this house and through this House, to the whole country, as to why production of cigarettes worth Rs. 160 crores out of a total production worth Rs. 300 crores per annum, in our country, has been entrusted to foreign firms by the Government; secondly, why the production of coca cola has been entrusted to foreign firms, when enough syrups and sharbats are available in our country, produced by the small scale sector? Sir, it is highly scandalous that foreign firms. as admitted by the Government, have exceeded their licensed capacity and thereby contravened the conditions in regard to licensing, namely, capacity specified in the licences. Such firms have made themselves liable to action under the provisions of the Industries Development and Regulation Act, 1951. But, no action has been taken by the Government for reasons best known to them. But my information is, the question of taking penal action against foreign firms which have indulged in unauthorised production in this country was considered in a halting and half-hearted manner in a number of ministries and put up to the concerned Cabinet Sub-committee for decision. The Committee did take some decisions, but they have not been implemented. The firms guilty of unauthorised production have got pulls and pressures in various ministries and Departments of Government and with the connivance and collusion of officers, they can manage to see that Government decisions taken at the highest level are either indefinitely postponed or not implemented at all. Therefore, certain points arise out of these: 1. How long did each firm indulge in unauthorised production? 2. Were periodical production returns sent to the DGTD and if so, what action did DGTD take in this matter? 3. Did DGTD sanction imported raw materials on the basis of unauthorised production and if so, under what authority? 4. Has the unauthorised production compelled the Indian sector to curtail their production or prevent them from applying for Industrial licence? 5. How much profits have been made by these firms from unauthorised production and to what extent the profits have been repatriated and what assets have been built out of these profits by them in our country? The firms have been allowed to indulge in unauthorised production with impunity on the ground that it is the intention of the Government to allow the production and had these firms not over-produced, Government would have been compelled to import such items involving expenditure on foreign ex-

change. If this argument is to be admitted, it strikes at the root of licensing of industries. My advice to Government is, in that case the licensing of industries should be scrapped altogether. Why should the Government give the impression that rules and regulations are meant only for the Indian sector and foreign firms with their huge resources and influence can contravene the laws of the land with impunity?

I would like to make a few suggestions for the consideration of the Government. 1. The licensing committee has done a good job in disposing of 3540 cases in 1973 as compared with 2252 cases in 1972. My suggestion is there is need for continuous vigilance to see that foreign firms do not get an upper hand over Indian firms under the guise of export promotion, liquidation of equity etc. 2. While Government has delicensed medium-scale industries whose investment is upto Rs. 1 crore, this is not beneficial because the conditions of registration and delicence are the same. Therefore, there should be completed delicensing for medium-scale industries. 3. Diversification should be allowed to Indian firms with minor balancing equipment and imported raw materials to the tune of at least 40% of the licensed capacity for conversion of obsolete items into new articles. 4. In spite of the improved procedure of licensing of industries, the Indian entrepreneur, whose applications are rejected, should be allowed to be heard by the full Licensing Committee. 5. The reports of the Bureau of Industrial Costs and Prices should be considered to be equal in importance to the reports of the Tariff Commission. Out of the five reports submitted by the BICP in 1973 not a single report has yet been implemented. 6. For the development of the 230 backward districts what is required to be done is that there should be an Open General Licensing system for Indian entrepreneurs only. 7. For the proper financing of industries in backward districts the restrictions put upon lending by commercial institutions should be lifted as financial institutions have failed to meet the requirements. 8. Non-S.I.A. applications pending before Government, which amount to roughly 4,000, should be disposed of within a reasonable time limit. 9. Firestone, M/s. Abot Anglo French and other foreign firms, which have a multi-national character, had initially very small investments but today they have grown to be giants and have come in the way of Indian industry. They ought to be cut down to size, if Indian industry is to grow and proper. 10. All COB licences to foreign firms, based on wrong information and diversification etc. be revoked immediately. Lastly, all permission letters which are proved illegal and which have no backing of any Act must be scrapped immediately, in the interest of the Indian Sector.

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) उपाध्यक्ष जी, इस बहस में हिस्सा लेने में मैं सिर्फ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर, खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज, सेरिकल्चर और क्वायर पर अपनी बहस को महदूद रखूंगा। कब्ल इसके कि मैं इस बहस के सिलसिले में कुछ कहूं, मैं उन आनरेबिल मेम्बर्स का जिन्होंने खुशी।सयत के साथ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सिलसिले में, क्वायर इंडस्ट्री और सेरिकल्चर इंडस्ट्री के सिलसिले में, खादी ग्रामोद्योग के सिलसिले में अपने सुझाव दिए हैं और अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के मामले को हमें तीन जावियो से देखना चाहिए। तीन ऐंगिल्स से मैं उस पर कुछ थोडी बहुत रोशनी डालना चाहता हूं और यह कोशिश भी करूंगा कि इस सिलसिले में हमारे आनरेबिल मेम्बर्स ने जो कुछ बातें कही हैं उन बातों का कुछ जवाब भी हो जाये। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के सिलसिले में एक ऐंगिल तो यह है कि हमारी दिक्कतें क्या हैं।

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

वह दिक्कतें जो स्माल स्केल एन्टरप्रिन्योर्स को पेश आती है और साथ ही स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के काम में लगे हुए लोगों की जो दिक्कतें हैं, वह दिक्कतें क्या हैं। इसका दूसरा पॉइंट यह है कि इन सारी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद जो हमारे सामने हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर में हमारी क्या पर्फारमेन्स रही है, हमारे क्या रिजल्ट्स रहे हैं और क्या हमारे अचीवमेन्ट्स रहे हैं। इसका तीसरा पॉइंट यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के सिलसिले में, खादी ग्रामोद्योग के डेवलपमेन्ट के सिलसिले में आगे के हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं और किस हद तक हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया और जैसा हमारे आनरेबिल मेम्बर्स ने भी कहा, हमारी बहुत सी कठिनाइयां और दिक्कतें हैं और अभी हाल ही में हमारे कुछ फाइनेंशिल और एकौनामिक कॉन्स्ट्रेन्टस आ गए हैं जिनकी वजह से उन दिक्कतों और परेशानियों में इजाफा हुआ है। खास तौर से कुछ आनरेबिल मेम्बर्स ने रा-मैटीरियल की तरफ तवज्जह दिलाई है कि रा-मैटीरियल दिक्कत ऐसी बुनियादी दिक्कत है जिसके बगैर इंडस्ट्रीज का चलना मुमकिन नहीं है। रा-मैटीरियल के सिलसिले में यह शुबहा नहीं है कि दिक्कत है, परेशानी है और उस परेशानी को हल करने के लिए बहुत बड़ी हद तक, कुछ इम्पोर्टेड रा-मैटीरियल के सिलसिले में पालिसी को लिबरलाइज किया गया है और इंडिजीनस रा-मैटीरियल के सिलसिले में भी जो स्केयर्स रा-मैटीरियल हैं—खुसूसियत के साथ आयरन ऐंड स्टील और दूसरे नान फेरस मटिल्स-उनमें भी पहले मुकाबले में स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर को निस्बतन मैं उन आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन यह एक वाकया है कि उसको पहले के मुकाबले में ज्यादा एलोकेशन मिल रहा है लेकिन इससे उस परेशानी और मुसीबतों का हल निकलने वाला नहीं है।

एक बात यहां पर कही गई, एक सवाल के जवाब में भी यह बात यहां पर आ चुकी है कि रा-मैटीरियल के सिलसिले में स्माल स्केल सेक्टर और लार्ज स्केल सेक्टर के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। हम ने तो खुले दिल और सफाई के साथ पहले भी कहा है कि लार्ज स्केल सेक्टर और स्माल स्केल सेक्टर में रा-मैटीरियल देने के सिलसिले में स्माल स्केल सेक्टर को जिन बुनियादों पर हम देते हैं वह मुख्तलिफ है लार्ज स्केल से और उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कोई एक सही तस्वीर नहीं है, हम को यह नहीं मालूम है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कितना रा-मैटीरियल चाहिए, कौन सा रा-मैटीरियल किस मात्रा में चाहिए। इसी लिए भट्ट कमेटी ने जहां बहुत सी वैल्युएबिल सजेशन्स दिए हैं स्माल स्केल सेक्टर को प्रमोट करने के सिलसिले में वहां पर एक सिफारिश यह भी की है कि स्माल स्केल—इंडस्ट्रियल यूनिट्स का बड़े पैमाने पर सारे मुल्क में सेन्सस होना चाहिए। हमारे एक आनरेबिल मेम्बर ने कटमोशन मूव करते हुए एस्टीमेट्स कमेटी की 35वीं रिपोर्ट की तरफ तवज्जह दिलाई थी जिसमें इस तरफ इशारा किया गया है कि सबसे बड़ी ड्राबैक जो है वह यह है कि कोई सेन्सस नहीं है, कोई डाटा नहीं है जिसकी वजह से स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा हैंडीकैप्ड है। इसलिए एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट की लाइट में और भट्ट कमेटी की रिपोर्ट की लाइट में भी इस बात को बहुत टाप प्रायर्टी दी गई कि हमारे सामने सही तसवीर पूरी तौर पर होनी चाहिए और इसीलिए सेन्सस के काम को शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हमारे पास एक मुकम्मिल तसवीर स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर की आ जायेगी कि कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितना उनके लिए

रा-मैटीरियल चाहिए, किन किन स्टैट्स मे चाहिए, कहा कहा वह लोकेटेड हैं। हम उम्मीद करते है इस डाटा के कलेक्ट होने के बाद हमारी वह दिक्कते बहुत बडी हद तक दूर हो जायेगी। और फिर हम बालचन्द्रन कमेटी की उस रिपोर्ट को, जिस का हवाला अक्सर यहा दिया जाता है, हम उसूली तौर पर उस को मान चुके है लेकिन उस के इमप्लीमेंटेशन मे डाटा न होने से, बगैर सैन्सस के मुमकिन नही है, हमारे लिये दिक्कत है और हम समझते है कि सैन्सस का काम पूरा होने के बाद शायद उस कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तौर पर इमप्लीमेन्ट करने के काबिल हो जायेगे उस हद तक जो उस की रिकमन्डेशनस है उन को बडी हद तक पूरा करने की हालत मे हो जायेगे।

14 hrs.

उपाध्यक्ष महादय, रा-मैटीरियल के अलावा और जो दूसरी दिक्कते है उन मे बहुत सी ऐसी है जिन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मै स्वीकार करता हू कि वह दिक्कते है पावर की कमी, इनफ्रास्ट्रक्चर का न होना, और मुख्तलिफ किस्म की दिक्कते है जिन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे पावर की शार्टेज है, जो हमारे मुल्क मे ही नही, बल्कि पूरी दुनिया मे है, उसकी लाइट मे हम फक्र के साथ कह सकते है कि हम फिर भी अपनी जगह पर मजबूती के साथ कदम जमाये खडे है। यह कम श्रेय की बात नही है। इसलिये मै उस सिलसिले मे ज्यादा नही कहना चाहता।

जो हमारी परफौरमेंस और अचीवमेंट्स रहे है चौथे प्लान मे उन के मुताबिक कुछ दो, चार बाते अर्ज करना चाहता हू। हमारी यूनिट्स जो रजिस्टर्ड थी 1998 मे उन की तादाद थी 1.71 लाख, लेकिन 1973 मे उन की तादाद बढ कर 4 05 लाख हो गई। ऐमप्लायमेंट की दृष्टि से 1968 मे 29.6 लाख लोग काम करते थे जिनकी तादाद बढ कर 1973 मे 45 लाख हो गई। इनवेस्टमेंट की दृष्टि से 620 करोड़ के फिक्सड असेट्स थे जो बढ कर 1973 मे 814 करोड हो गये। प्रोडक्शन स्माल स्केल में किस हद तक बढा है इस को भी जरा देखा जाय। 1968 मै 3 207 लाख रु० का प्रोडक्शन था जो 1973 मे बढकर 6,249 लाख रु० तक पहुच गया। ऐक्सपोर्ट 1970 मे 93 17 करोड रु० था वह बढ कर 132 03 करोड स्माल स्केल सैक्टर प्रोडक्ट्स का हो गया। ऐनसिलियरीज के डेवलपमेंट के आकडो का जरा मुलाहिजा फरमाया जाय। लार्ज स्केल सैक्टर की ऐसिलियरीज की तादाद 1969-70 मे 2,008 थी जो 1971-72 मे बढ कर 7,606 हो गई। इन फिगर्स को पेश करके मेरा यह मशा नही है कि इन पर बहुत फख्र किया जा सकता है। हर गिज नही। मै महसूस करता हू कि बहुत बडी हद तक स्माल स्केल इडस्ट्रिज सैक्टर को डेवलप किया जाना चाहिये था जो कि नही हो सका। लेकिन अगर यह फिगर्स कुछ थोडा बहुत इशारा करती है तो यह कि हम स्टेगनेन्ट नही रहे है, और जैसा कि माननीय मदस्यो ने कहा कि स्माल स्केल सैक्टर मे हम स्टेगनेन्ट रहे है तो इन फिगर्स मे स्टेगनेशन जाहिर नही किया जा सकता।

यह सही है कि स्माल स्केल सैक्टर लार्ज स्केल सैक्टर के मुकाबले मे इस मुल्क की इकोनामी और ऐमप्लायमेंट की दृष्टि से सब से ज्यादा महत्वपूर्ण सैक्टर है। लार्ज स्केल सैक्टर हमारे मुल्क की दौलत को बढाने और इजाफा करने का एक कारण बन सकता है। लेकिन हमारे मुल्क की दूसरी सब से बडी प्रोबलम अनऐमप्लायमेंट की है उस का हल करने का सबसे बढा जरिया स्माल स्केल सैक्टर है। कमपरीजन के लिये यह बात कही जा सकती है कि अगर हम किन्ही दो स्टेट्स को ले, एक जगह पर लार्ज स्केल इडस्ट्रीज काफी डेवलप हुई हो और दूसरी स्टेट जहा

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

पर लार्ज स्केल सैक्टर इंडस्ट्रीज कार्म्पेरेटिबली कम डेवलप हुई हो, स्माल स्केल सैक्टर इडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हुई हो तो मालूम किया जा सकता है आसानी से कि वह स्टेट जहां पर लार्ज स्केल इडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है वह पिछडी हुई है बनिस्पत उस स्टेट के जहां पर स्मल स्केल सैक्टर इडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हुई है। वहा पर ऐमप्लायमेंट ज्यादा पैदा हुआ है, और ज्यादा खुशहाली आयी है।

इस लिये मैं कहना चाहता हू कि हम लोग इस बात से कोई बहुत ज्यादा मुतमइन नही है और इस सैक्टर को ज्यादा तेजी से बढाना चाहते है। लेकिन हमारी लिमिटेशन्स है और जो तवज्जह इस सदन के माननीय सदस्यो ने स्माल स्केल सैक्टर की तरफ दिखायी है उस के भरोसे पर मैं फख्र के साथ कह सकता हू कि स्माल स्केल इडस्ट्रियल सैक्टर के बढने को कोई नही रोक सकेगा, और यह तरक्की करेगा।

उपाध्यक्ष जी बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हमारी बहुत बडी प्रौबलम है। बैकवर्ड एरियाज और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे मे बहुत से मैम्बरान ने तशवीश का इजहार किया है कि बैकवर्ड एरियाज को डिक्लेयर करने मे कोई डिस्ट्रिमिनेशन किया गया है। लेकिन बैकवर्ड एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट के कसलटेशन से प्लानिंग कमीशन मुकर्रर करता है। उस के कुछ नौर्म्स है। मैं इन्कार नही करता हो सकता है कि कुछ डिजर्विंग जिले जो वाकई बैक्वर्ड हो, छूट गये हो। लेकिन बैकवर्ड जिलो को तय करना प्लानिंग कमीशन का काम है जो वह स्टेट गवर्नमेंट से कसल्ट कर के करता है। अलबता यह हमारा काम है कि जब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो जाय तो हमारी सारी तवज्जह उस के डेवलपमेंट की तरफ लग जानी चाहिये। मैं कोई लम्बे चौडे दावे नहीं करना चाहता, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का डेवलपमेंट कोई बहुत आसान काम नहीं है। आखिर वजह तलाश करनी पडेगी, सब से पहले हम को उन डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज के बैकवर्ड होने की पिछडे रह जाने की वजह क्या है, यह देखना होगा। जब मुल्क की इकोनोमी डिवेलेप कर रही है, इडस्ट्रीज बढ रही हैं तो कुछ एरियाज रह जाए, बैकवर्ड एरियाज डिवेलेप न कर पाए तो उसकी वजह हमें तलाश करनी पडेगी और उस वजह को तलाश किए बगैर उस तरफ हमे जितनी एटेंशन पे करनी चाहिये नही कर सकते हैं। इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरे प्रापर एटरप्रेन्योरशिप का न होना है, तीसरे टेक्नीकल नो हऊ का न होना है और इसी तरह के दूसरे और भी बहुत से फैक्टर्ज हैं---

श्री मूल चन्द डागा . नौकरशाही को पहले ठीक करो।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इन चीजो को पहले कर ले उसके बाद उसको भी कर लेंगे। ये बुनियादी चीजें हैं। बहुत आसान नहीं है। इसी वास्ते हमारी सारी तवज्जह बैकवर्ड एरियाज के डिवेलेपमेंट की तरफ है और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्ज हमने प्रापोज किए हैं ताकि एटरप्रेन्योर्ज वहां जाकर उन तमाम इंसेंटिव्ज की वजह से इडस्ट्रीज लगाए और वहा का इडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट हो।

इडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट का जहा तक ताल्लुक है, स्माल स्केल इडस्ट्रियल सैक्टर एक नए मोड पर आ गया है। जो अब तक हमारा एप्रोच स्माल स्केल इडस्ट्रिज के डिवेलेपमेंट का रहा है और अब नए पाच साला प्लान मे जा हैं, दोनो मे बहुत फर्क है। नए प्लान मे हम हकीकी जोर स्माल स्केल इडस्ट्रीज के असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर लगाना चाहते है और यह बात कह देना चाहते हैं कि यह असिस्टेंस इंटैग्रेटिड असिस्टेंस हो। मिनिस्टर इचार्ज की हैसियत से मुझे मुख्तलिफ सूबों में जाने का मौका मिला है और मैंने पाया है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डिवेलेपमेंट के सिलसिले में एक बहुत बडी बाधा यह भी है कि

इंटैग्रेटिड असिस्टेंस हम एंटरप्रेन्योर्ज को नही दे पा रहे है और डिफ़ेंट जो इंस्टीट्यूशज लगी हुई है स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोमोट करने के सिलसिले मे इनके बीच कोआर्डिनेशन की कमी है। हमारा जोर अब इस बात पर है कि हम स्माल स्केल एंटरप्रेन्योर को इंटेग्रेटिड असिस्टेंस दे मैनेजमेंट कंसलटेंसी और ट्रेनिंग के सिलसिले में, क्रेडिट एवेलेबिलिटी के सिलसिले मे, टैकनीकल सर्विस और फेसिलिटीज के सिलसिले मे और डोमैस्टिक और एक्सपोर्ट मार्किट की पोसिबिलिटीज को मालूम करने के सिलसिले मे। यह फिफ्थ प्लान का हमारा एक सीधा एप्रोच है। साथ साथ जो डिफ़ेंट इंस्टीट्यूशज और आर्गेनाइजेशज स्माल स्केल इंडस्ट्रियल सैक्टर में लगी हुई हैं उनके बीच हम कोआर्डिनेशन चाहते हैं ताकि सब मिल कर डिवेलेपमेंट के काम को आगे बढ़ाने मे एक साथ आगे चल सकें।

एक और एप्रोच पाचवें प्लान में हमारा इस सिलसिले मे है। अब तक जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के डिवेलेपमेंट का तरीका रहा है वह यह रहा है कि हम न कोई टैक्नो-इकोनामिक सर्वे पहले से किसी बैक्वर्ड एरिया का नहीं करवाया, वहा पर लोकली अवेलेबल रा-मैटीरियल या इंडिजिनस रा-मैटीरियल जो है उसकी तरफ हमारी तवज्जह नही गई और स्केयर्स रा-मैटीरियल इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स को रजिस्टर करके हमने समझा कि हम इस तरह से इन इंडस्ट्रीज को सैट-अप करके इनको बढ़ावा दे सकते है। मेरी राय है कि स्माल इंडस्ट्रियल सैक्टर मे जो लोकली रा-मैटिरीयल अवेलेबल है---

श्री राजदेव सिह (जौनपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा है कि बैकवर्ड एरियाज मे रा-मैटीरियल लोकली अवेलेबल है या नही इसकी जाच नही कराई गई। मै इसको साफ कर देना चाहता हू कि बैकवर्ड एरियाज के लिए एक पटेल स्टेडी टीम एप्वाईंट हुई थी और उसने बताया था कि कौन-कौन सा रा-मैटीरियल कहा-कहां है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह मै नही कहना चाहता कि नही हुआ है। मै अर्ज यह करना चाहता हू कि आज हमारा जो मेन थ्रस्ट है जो जोर हम दे रहे है पाचवे प्लान में वह दे रहे हैं लोकली अवेलेबल रा-मैटीरियल के ऊपर, उसके एक्स्पलायटेशन के ऊपर इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट के लिए।

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI (Tehri Garhwal) Based on the locally available raw materials, I want to know, whether you would establish the industries here or you would export them outside

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हमारी मजबूरी यह है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को किसी खास जगह डाल कर वहा उनका उगा नही सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्ज हमको पैदा करने होगे मुख्तलिफ तौर पर। अंत्रेनेनल नहीं है तो पूरा हिन्दुस्तान एक मुल्क है और अगर बाहर के एंटरप्रेन्योर आ कर वहा के लोकल रा-मैटीरियल्ज का एक्स्प्लायट करके इंडस्ट्री सैट अप करना चाहते है तो वे करेगे। अगर आप यह चाहते हैं कि हम उगाए एंटरप्रेन्योर्ज को तो यह हमारे बस की बात नहीं है।

पाचवे प्लान मे हम एन०एम०आई० सी की नई ब्रांचिज—खोलना चाहते है और स्पैशलाइज्ड सर्विस या प्रिजर्वेशन करना चाहते है और फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एसिलरी डिवेलेपमेंट के लिए दो हजार नए यूनिट्स इलैक्ट्रानिक्स के लिए खोलना चाहते हैं। यह हमारा नए प्लान मे एक मेन ट्रस्ट है।

एन० एम० आई० सी० के बारे मे शिकायत हुई है। यह एक ऐसा कारपोरेशन है जो बडी वैल्युएबल खिदमत अजाम दे रहा है। यह ठीक है कि उसके वर्किंग मे दिक्कतें और परेशानिया महसूस की गई जिसकी वजह से एक कमेटी एप्वाइंट हुई और उस कमेटी की रिकोमेंडेशज मिनिस्ट्री के जेरे गौर है और उनकी

[श्री जियाउर्रहमान अनसारी]

रोशनी मे हम कुछ उसका स्ट्रीम लाइनिंग करना चाहते हैं, उसके वर्किंग का, उसके तरीको का और मेनली नैशनल स्माल स्केल इडस्ट्रीज का जहा तक हायर परचेज का ताल्लुक है हम चाहते है कि स्टेटस के लिए रिफाइनेंस इस्टीट्यूशन के तौर पर काम करे। इसको हम स्टेजिज मे करेगे। फर्स्टस्टेज मे एक लाख तक रिफाइनेंस इस्टीट्यूशन के तौर पर हम चाहते है कि एन० एस० आई० सी० वर्क करे। एक लाख से ऊपर हायर परचेज मशीनरी के लिए वह खुद करेगी। लेकिन सैकड स्टेज मे हम सारा काम स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये से, या स्टेट्स के इस्टी-ट्यूशन्ज के जरिये से कराना चाहते है। हम वन मैन कमेटी के इस प्रोपोजल को कनसिडर कर रहे है कि एन० एस० आई० सी० रीफाइने-सिंग इस्टीट्यूशन के तौर पर वर्क करे।

कुछ खादी एण्ड विल्लेज इडस्ट्रीज कमीशन की एक्टिविटीज का भी तजकिरा आया। इस कमीशन की एक्टिविटीज कोई महज समअती, औद्योगिक, एक्टिविटीज नही है, बल्कि उस के साथ हमारा सोशल अपलिफ्ट का प्रोग्राम और एक फिलासफी जुडी हुई है कि किस तरह आम लोग घर मे थोडा बहुत काम कर के मुल्क की जरूरतो को पूरा कर सकते है, गावो की लोकल जरूरतो को पूरा कर सकते है। इस सिलसिले में खादी एण्ड ग्रामोद्योग कमीशन ने काफी काम किया है। यह सही है कि जब खादी एण्ड ग्रामोद्योग कमीशन उस काम को मुख्तलिफ इस्टीट्यूशन के जरिये से करेगा—वह एक बडा डीसेंट्रलाइज्ड सैक्टर है—, तो उस मे कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स होंगे, उसमें मै इन्कार नही करता हू। इस बात की मुसलसल कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन डिफेक्ट्स को दूर किया जाये।

जहा तक उस में प्रोडक्शन बढ़ाने और माडर्नाइजेशन लाने का सवाल है, हम खादी के सिलसिले मे ट्रेडीशनल चर्खे से अम्बर चर्खे तक और अम्बर चर्खे से न्यू माडल चर्खे पर आए है, जिससे खादी का प्रोडक्शन भी बढेगा और उस मे जो लेबर लगे हुए है, उन की वेजिज मे भी इजाफा होगा। लोक वस्त्र का एक नया प्रोग्राम भी हमारे जेरे गौर है। खादी एण्ड ग्रामोद्योग कमीशन ने प्रोग्राम बनाया है कि मामूली इन्सान जो कपडा इस्तेमाल करता है, उस को किस तरह खादी के जरिये से बनाया जा सके, ताकि वह सस्ता बने और लोग उस को ले सके। उसमे स्पिनिंग सेक्टर मे कुछ हद तक पावर इस्तेमाल कर के सस्ता और अच्छा कपडा बनाने का एक प्रोग्राम अडर कनसिडरेशन है।

कायर इडस्ट्री के सिलसिले मे कुछ मेम्बरो ने बहुत ही तशवीश का इजहार किया है मैके-नाइजेशन के बारे मे। इस लिये मै अपना यह फरीजा समझता हू कि कायर इडस्ट्री को मैके-नाइज करने के सिलसिले मे गवर्नमेंट के रुख को सफाई के साथ अर्ज कर दू। गवर्नमेंट कायर इडस्ट्री को इस अदाज से और उस हद तक मैकेनाइज करने के हरगिज-हरगिज हक मे नही है कि उससे अनएम्पलायमेंट की प्रोबलम पैदा हो जाय। गवर्नमेंट का कतई तौर पर यह रुख है कि वह इस हक मे नही कि अनएम्प-लायमेंट की प्रोबलम क्रियेट हो। केरल मे 283 लोकली फैब्रिकेटिड मशीन्ज, जिन के लिये लाइसेंस की जरूरत नही थी, रेटिंग सैक्टर मे चलने लगी थी और उससे काफी अनएम्प-लायमेन्ट पैदा हुआ था। गवर्नमेंट आफ केरल ने सही वक्त पर कदम उठा कर उन 283 मशीन्ज को, जिन्होने काफी लोगो को आउट आफ एम्पलायमेंट कर दिया था, डी० आई० आर० के तहत बैन कर दिया।

हम इस तरह के मैकेनाइजेशन के हक मे नही है, जो अनएम्पलायमेंट लाने वाला है, जो लोगो की रोजी छीन ले और उन को नंगा और भूखा कर दे। लेकिन अगर ऐसा माडर्-नाइजेशन हो, या इस हद तक माडर्नाइजेशन हो, जिस से हमारी एम्पलायमेंट पर

कम असर पड़े, लेकिन हम एक्सपोर्ट की अच्छी मार्केट हासिल कर सकें, तो हम हमेशा उस के हक में रहे है। इसलिये इस सिलसिले मे गवर्नमेंट की काशस मैकेनाइजेशन की पालिसी है।

1961 मे गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर मे कायर इंडस्ट्री की एक तिहाई प्राडक्ट्स को मैकेनाइज किया जाये। तभी से तीन मैकेनाइज्ड युनिट्स मैनुफक्चरिंग सेक्टर मे लगे थे,—एक पब्लिक सैक्टर मे कायर बोर्ड के अदर और दो प्राईवेट सेक्टर मे। इस के अलावा मैनुफैक्चिरिंग सैक्टर मे या स्पिनिंग सैक्टर मे कोई फरदर मैकेनाइजेशन नही हुआ है।

एक आनरेबल मेम्बर ने सिरीकल्चर के बारे मे कहा है। मैं इस तफसील मे नही जाना चाहता कि किस तरह से सिल्क बोर्ड ने, और मुख्तलिफ जगहो पर हमारे जो सिरीकल्चर रिसर्च स्टेशन हैं, उन्हाने किस तरह सिरीकल्चर इंडस्ट्री को डेवेलप किया है। मैं आप के माध्यम से आल-इंडिया सिल्क बोर्ड को मुबारकबाद देना चाहता हु और उस मे काम करने वाले रिसर्च आफिसर्ज और डायरेक्टर्ज को भी मुबारकबाद देना चाहता हू कि हमने किस तरह से—मैंने खुद अपनी आँखो से कर्नाटक स्टेट मे देखा है—मल्टी-वोल्टीन मे बाई-वोल्टीन की तरफ स्विच ओवर किया है, और किस तरह से वहाँ किसान ज्यादा से ज्यादा सिल्क पैदा करने की तरफ बढ रहा है।

सिल्क इंडस्ट्रीज के सिलसिले मे एक और महत्व पूर्ण कदम जेरे-गौर है। अभी तक हमारा ज्यादा जोर सिर्फ मलवरी सीड पर रहा है। एक नया प्रोग्राम हमारे अंडर कनसिडरेशन है कि सब-हिमालयन रिजन में, आसाम से ले कर काश्मीर तक, जो ओक पैदा होता है, उस से किस तरह ओक टसर डेवेलेप किया जाय और अगर उस के लिये जरूरी समझा जाय, तो, एक ओक टसर डेवेलपमेंट कार्पोरेशन को वजूद मे लाया जाय। दुनिया मे हिंदुस्तान के सिल्क की माँग को देखते हुए हम किस तरह इस इंडस्ट्री को डेवेलप कर के फारेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, उस पर भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये।

वक्त की कमी का एहसास करते हुए, जो बहुत सी बाते मै विस्तार के साथ कहना चाहता था, मुझे अफसोस है कि मै नही कह सका। मै माफी चाहता हू उन आनरेबल मेम्बरान से, जिन की कोई बात वक्त की कमी की वजह से छूट गई हो। उन्होंने इस सैक्टर पर जो इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट का निस्वनन एक वीकर सैक्टर है, जो तवज्जुह की है, उस के लिये मैं उन का शुक्रिया अदा करता हू। मे हर वक्त उन से गाइडेंस लेना चाहता हू और उन की एसिस्टेंस के लिये और उन के खयालात को हासिल करने के लिये उन की तरफ देखना चाहता हू।

ادیوگک وکاس منترالیہ مس

ا‌ب مسری (سری ضیاالرحمان انصاری) :

ا‌پادھیکھشں جی ، اس بحث مس حصہ لینے مس مس صرف سمال سکیل انڈسٹریز سیکٹر ، کھادی اینڈ ویلج انڈسٹریز ، سریکلچر اور کوائر پر اپنی بحث کو محدود رکھونگا - قبل اس کے کہ مس اس بحث کے سلسلے مس کچھ کہوں ، مس ان آنریبل ممبرز کا جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ سمال سکیل انڈسٹریز کے سلسلے مس کوائر انڈسٹری اور سریکلچر انڈسٹری کے سلسلے مس ، کھادی گرام ادیوگ کے بارے مس اپنے سجھاؤ دئے ہیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے - اس کے لئے مس

[شری ضیا الرحمان انصاری]
انکا بہت بہت سکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ۔

انڈسٹریل ڈویلمنٹ کے ماملے کو ہمیں تین زاویوں سے دیکھنا چاہئیے۔ تین انگلز سے میں اس پر کچھ تھوڑی بہت روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ کوشش بھی کرونگا کہ اس سلسلے میں ہمارے آنریبل ممبرز نے جو کچھ باتیں کہی ہیں ان باتوں کا کچھ جواب بھی ہو جائے۔ سمال سکیل انڈسٹریز کے ڈویلپمنٹ کے سلسلے میں ایک اینگل یہ ہے کہ ہماری دقتیں کیا ہیں۔ وہ دقتیں جو سمال سکیل انٹرپرینورز کو پیش آتی ہیں اور ساتھ ہی سمال سکیل انڈسٹریز کے پروموٹرس کے کام میں لگے ہوئے لوگوں کی جو دقتیں ہیں وہ دقتیں کیا ہیں۔ اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان ساری دقتوں اور پریشانیوں کے باوجود جو ہمارے سامنے ہیں ۔ سمال سکیل انڈسٹریز سیکٹر میں ہماری کیا پرفورمینس رہی ہے۔ ہمارے کیا رزلٹ رہے ہیں اور کیا ہمارے اچیومینٹ رہے ہیں۔ اس کا تیسرا اینگل یہ ہے کہ سمال سکیل انڈسٹریل سیکٹر ڈویلپ کرنے کے سلسلے میں، کھادی گرام ادیوگ کے ڈویلپمنٹ کے سلسلے میں آگے کے ہمارے پروگرامز کیا ہیں اور کس حد تک ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔

جیسا میں نے پہلے عرض کیا اور جیسا ہمارے آنریبل ممبرز نے بھی کہا، ہماری بہت سی کٹھنائیاں اور دقتیں ہیں اور ابھی حال ہی میں ہمارے کچھ فائنینسل اور اکانومک کانسٹریٹنس آگئے ہیں جن کی وجہ سے ان دقتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور سے کچھ آنریبل ممبرز نے را میٹیریل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ رامٹیریل کی دقت ایسی بنیادی دقت ہے جس کے بغیر انڈسٹریز کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ را مٹیریل کے سلسلے میں یہ سمجھ نہیں ہے کہ دقت ہے، پریشانی ہے اور اس پریشانی کو حل کرنے کے لئے بہت بڑی حد تک، کچھ اسورڈ را میٹریل کے سلسلے میں پالیسی کو لبرلائز کیا گیا ہے۔ اور انڈیجینس را مٹیریل کے سلسلے میں بھی جو سکسیرس را مٹیریل ہے ان میں بھی پہلے کے مقابلے میں سمال سکیل انڈسٹریل سیکٹر کو پیسنٹ ۔۔۔میں ان آنکڑوں میں جانا نہیں چاہتا ۔۔ واقعہ ہے کہ اس کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ایلوکیشن مل رہا ہے لیکن اس سے اس پریشانی اور مصیبتوں کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔

ایک بات یہاں پر کہی گئی ہے، ایک سوال کے جواب میں بھی یہ بات یہاں پر آچکی ہے کہ را میٹریل کے سلسلے میں سمال سکیل سیکٹر اور لارج سکیل سیکٹر کے بیچ میں کچھ

رپورٹ کی لائٹ میں بھی اس بات کو بہت ٹاپ پرایوریٹی دی گئی ہے کہ ہمارے سامنے صحیح تصویر پوری طور پر ہونی چاہئے اور اسی لئے سینسیس کے کام کو شروع کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سال کے آخیر تک ہمارے پاس ایک مکمل تصویر سمال سکیل انڈسٹریل سیکٹر کی آ جائیگی کہ کتنی انڈسٹریز ہیں۔ کتنا ان کے لئے را میٹیریل چاہئے۔ کن کن سٹیٹس میں چاہئے۔ کہاں کہاں وہ لوکیٹڈ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اس ڈاٹا کے کولیکٹ ہونے کے بعد ہماری وہ دقتیں بہت بڑی حد تک دور ہو جائینگی۔ اور پھر ہم بالچندر کمیٹی کی اس رپورٹ کو جس کا حوالہ اکثر یہاں دیا جاتا ہے۔ ہم اصولی طور پر اس کو مان چکے ہیں لیکن اس کے امپلی منیٹیشن میں ڈاٹا نہ ہونے کے بغیر سنیسیس کے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لئے دقتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینسیس کا کام پورا ہونے کے بعد شاید اس کمیٹی کی رپورٹ کو پوری طور پر امپلی‌مینٹ کرنے کے قابل ہو جائینگے اس حد تک جو اس کی سفارشیں ہیں ان کو بڑی حد تک پورا کرنے کی حالت میں ہو جائینگے۔

اپادھیکش مہودئے۔ را میٹیریل کے علاوہ اور جو دوسری دقتیں ہیں ان میں بہت سی ایسی ہیں جن پر قابو ڈسکریمینیشن ہے۔ ہم نے تو کھلے دل اور صفائی کے ساتھ پہلے بھی کہا ہے کہ لارج سکیل سیکٹر اور سمال سکیل سیکٹر میں را میٹیریل کے دینے کے سلسلے میں سمال سکیل سیکٹر کو جن کی بنیادوں پر ہم دیتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ لارج سکیل سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سمال سکیل انڈسٹریل یونٹس کی کوئی ایک صحیح تصویر نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سمال سکیل انڈسٹریل یونٹس کو کتنا را میٹریل چاہئے، کون سا را میٹریل کس مانرا میں چاہئے۔ اس لئے بھٹ کمیٹی نے جہاں بہت سے ویلیو ایبل سجیشن دئے ہیں سمال سکیل سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں وہاں پر ایک سفارش یہ بھی کی ہے کہ سمال سکیل انڈسٹریل یونٹس کا بڑے پیمانے پر ملک میں سینسیس ہونا چاہئے۔ ہمارے ایک آنریبل ممبر نے کٹ موشن موو کرتے ہوئے ایسٹیمیٹس کمیٹی کی پنتیسویں رپورٹ کی طرف توجہ دلائی تھی جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے بڑی ڈرابیک جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سنیسیس نہیں ہے، کوئی ڈاٹا نہیں ہے جسکی وجہ سے سمال سیکٹر انڈسٹریل سیکٹر بہت زیادہ ہینڈیکیڈ ہے۔ اس لئے ایسٹیمیٹس کمیٹی کی رپورٹ کی لائٹ میں بھٹ کمیٹی کی

کر ۶,۲۴۹ لاکھ روپئے تک پہنچ گیا - ایکسپورٹ ۱۹۷۰ میں ۹۳۰۷ کروڑ روپئے تھا وہ بڑھ کر ۱۳۲۰۵۳ کروڑ سمال سکیل سیکٹر پروڈکشن کا ہو گیا - اینسی لیریز کے ڈویلپمینٹ کے آنکڑوں کا ذرا ملا خطہ فرمایا جائے - لارج سکیل سیکٹر کی آینی لیریز کی تعداد ۱۹۶۹-۷۰ میں ۲,۰۰۸ تھی جو ۱۹۷۱-۷۲ میں بڑھ کر ۷,۶۰۶ ہو گئی - ان فگرس کو پیش کرکے میرا یہ منشا نہیں ہے کہ ان پر بہت فخر کیا جا سکتا ہے - ہر گز نہیں - میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑی حد تک سمال سکیل انڈسٹریز کو ڈویلپ کیا جانا چاہئے تھا جو کہ نہیں ہو سکا - لیکن اگر یہ فگرس کچھ تھوڑا بہت اشارہ کرتی ہیں تو یہ کہ ہم سٹیگنٹ نہیں رہے ہیں اور جیسا کہ مانئیہ ممبروں نے کہا کہ سمال سکیل سیکٹر میں ہم سٹیگنٹ رہے ہیں تو ان فگرس سے سٹیگنیشن ظاہر نہیں کیا جا سکتا -

یہ صحیح ہے کہ سمال سکیل سیکٹر لارج سکیل سیکٹر کے مقابلے میں اس ملک کی اکانامی اور ایمپلائیمینٹ کی درشٹی سے سب سے زیادہ مہتوپورن سیکٹر ہے - لارج سکیل سیکٹر ہمارے ملک کی دولت کو بڑھانے اور اضافہ کرنے کا ایک کارن بن کر سکتا ہے - لیکن ہمارے ملک کی دوسری سب سے بڑی پرابلم ان ایمپلائیمینٹ کی ہے اس

[شری ضیا الرحمان انصاری]

پانے کی کوشش جا رہی ہے - لیکن میں سویکار کرتا ہوں کہ وہ دقتیں ہیں پاور کی انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، اور مختلف قسم کی دقتیں ہیں جن پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے - لیکن جیسے پاور کی شارٹیج ہے، جو ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، اس کی لائٹ میں ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پھر بھی اپنی جگہ پر مظبوطی کے ساتھ قدم جمائے کھڑے ہیں - یہ کیا تعریف کی بات نہیں ہے - اس لئے میں اس سلسلے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا -

جو ہماری ہرفار رمینس اور اچیومینٹس رہے ہیں چوتھی پلان میں ان کے مطابق کچھ دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں - ہماری یونٹس جو رجسٹرڈ تھیں ۱۹۶۸ میں ان کی تعداد نہی ۱۰۷۱ لاکھ، لیکن ۱۹۷۳ میں ان کی تعداد بڑھ کر ۴۰۰۵ لاکھ ہو گئی - ایمپلائیمینٹ کی نگاہ سے ۱۹۶۸ میں ۲۹۰۶ لاکھ لوگ کام کرتے تھے جن کی تعداد بڑھ کر ۱۹۷۳ میں ۴۵ لاکھ ہو گئی - انویسٹیٹ کی درشٹی سے ۶۲۰ کروڑ کے فکسڈ ایسٹس تھے جو بڑھ کر ۱۹۷۳ میں ۸۱۴ کروڑ ہو گئے - پروڈکشن سمال سکیل میں کس حد تک بڑھا ہے اسکو بھی ذرا دیکھا جائے - ۱۹۶۸ میں ۳,۲۰۷ لاکھ روپئے کا پروڈکشن تھا جو ۱۹۷۳ میں بڑھ

ہے ۔ بیکورڈ ایریاز اور بیکورڈ ڈسٹرکٹس کے بارے میں بہت سے ممبران نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بیکورڈ ایریاز کو ڈکلیر کرنے میں کوئی ڈسکریمینیشن کیا گیا ہے ۔ لیکن بیکورڈ ایریاز اور دسٹرکٹس کو سٹیٹ گورنمنٹ کے کنسلٹیشن سے پلاننگ کمیشن مقرر کرتا ہے ۔ اس کے کچھ ممبرز ہیں ۔ میں انکار نہیں کرتا ، ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈزرونگ ضلع جو بیکورڈ ہوں چھوٹ گئے ہوں ۔ لیکن بیکورڈ ضلعوں کو طے کرنا پلاننگ کمیشن کا کام ہے جو وہ سٹیٹ گورنمنٹ سے کنسلٹ کرکے کرتا ہے ۔ البتہ یہ ہمارا کام ہے کہ جب بیکورڈ ڈسٹرکٹ ڈکلیر ہو جائے تو ہماری ساری توجہ اس کے ڈویلپمینٹ کی طرف لگ جانی چاہئے ۔ میں کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کرنا چاہتا ، بیکورڈ ڈسٹرکٹس کا ڈویلپمنٹ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے ۔ آخر وجہ تلاش کرنی پڑے گی ، سب سے پہلے ہم کو ان ڈسٹرکٹس اور ایریاز کے بیکورڈ ہونے کی ، پچھڑے رہ جانے کی وجہ کیا ہے ، یہ دیکھنا ہوگا ۔

اب ملک کی اکانامی ڈویلپ کر رہی ہے ، انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں ، تو کچھ اعتراض رہ جائیں ، بیکورڈ ایریاز ڈویلپ نہ کر پائیں تو اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی پڑے گی اور اس وجہ کو تلاش کئے بغیر اس طرف ہمیں کو حل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمال سکیل سیکٹر ہے ۔ کمپیریزن کے لئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کہنیں دو سٹیٹس کو لیں ، ایک جگہ پر لارج سکیل انڈسٹریز کافی ڈویلپ ہوئی ہوں اور دوسری سٹیٹ جہاں پر لارج سکیل سیکٹر انڈسٹریز کمپیریٹوی کم ڈویلپ ہوئی ہوں ۔ سمال سکیل سیکٹر انڈسٹریز زیادہ ڈویلپ ہوئی ہوں ، تو معلوم کیا جا سکتا ہے آسانی سے کہ وہ سٹیٹ جہاں پر لارج سکیل انڈسٹریز کا ڈویلپمینٹ زیادہ ہوا ہے وہ پچھڑی ہوئی ہے نسبتاً اس سٹیٹ کے جہاں پر سمال سکیل سیکٹر انڈسٹریز زیادہ ڈویلپ ہوئی ہیں ۔ وہاں پر ایمپلائیمینٹ زیادہ پیدا ہوا ہے اور زیادہ خوشحالی آئی ہے ۔

اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات سے کوئی بہت زیادہ مطمعین نہیں ہیں طور اس سکٹر کو زیادہ تیزی سے بڑھانا چاہتے ہیں ۔ لیکن ہماری لیمیٹیشنز ہیں اور جو توجہ اس سدن کے مانئیہ سدسیوں نے سمال سکیل سیکٹر کو طرف دکھائی ہے اس کے بھروسے پر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سمال سکیل انڈسٹریل سکٹر کے بڑھانے کو کوئی نہیں روک سکے گا اور یہ ترقی کرے گا ۔

اپادھیکش جی ، بیکورڈ ایریا کا ڈویلپمینٹ ہماری بہت بڑی پرابلم

[سری صیا الرحمان انصاری]

حتی اٹیسس بے کرنی چاهئے نہیں کر سکیے هیں ۔ انفرسٹرکچر کی کمی هے ، دوسرے برابر انٹرپرینیور شپ کا هوتا هے ، تیسرے ٹکنیکل نوهاؤ کا نه هوتا هے اور اسی طرح کے دوسرے اور بھی بہت سے فیکٹرز هیں . . . . .

سری مول چند ڈاگا ۔ جو کر ساهی کو پہلے ٹھیک کرو ۔

سری صیا الرحمان انصاری ۔ ان چیزوں کو پہلے کر لیں اس کے بعد اس کو بھی کر لیں گے ۔ یه ساری چیزیں هیں ۔ بہت آسان نہیں هیں ۔ اسی واسطے هماری ساری توجه بیکورڈ ایریاز کے ڈویلپمنٹ کی طرف هے اور اس کے لئے مختلف قسم کے اسٹیپس هم نے ڈروپوز کئے هیں تاکہ انٹر پرینورر وهاں جا کر ان تمام اسٹیپس کی وجه سے انڈسٹریز لگائیں اور وهاں کا انڈسٹریل ڈویلپمینٹ هو ۔

انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کا جہاں تک تعلق هے ۔ سمال سکیل انڈسٹریل سکٹر ایک نئے موڑ پر آ گیا هے ۔ جو اب همارا اپروچ سمال سکیل انڈسٹریز کے ڈویلپمینٹ کا رها هے اور اب نئے پانچ ساله پلان میں جو هے ، دونوں میں بہت فرق هے ۔ نئے پلان میں هم حقیقی زور سمال سکیل انڈسٹریز کے اسسٹنس پروگرام کے اوپر لگانا چاهتے هیں اور یه بات کہه دینا چاهتے هیں که یه اسسٹنس انٹگریٹڈ اسسٹنس هو ۔

منسٹر انچارج کی حیثیت سے محکمے مختلف صوبوں میں جانے کا موقع ملا هے اور میں نے پایا هے که سمال سکیل انڈسٹریز کے ڈویلپمنٹ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بادھا یه بھی هے که انٹگریٹڈ اسسٹنس هم انٹر پرینورر کو نہیں دے پا رهے هیں اور مختلف جو اسٹی ٹیوشنز جو لگی هوئی هیں سمال سکیل انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں ان کے بیچ کوآرڈینیشن کی کمی هے ۔ همارا زور اب اس بات پر هے که هم سمال سکیل انٹرپرینیور کو انٹگریٹڈ امداد دیں منیجمنٹ کنسلٹنسی اور ٹریننگ کے سلسلے میں کریڈٹ اویلبلٹی کے سلسلے میں ، ٹکنیکل سروس اور فیسلٹیز کے سلسلے میں اور ڈومسٹک اور ایکسپورٹ مارکیٹ کے امکانات کو معلوم کرنے کے سلسلے میں یه پانچویں پلان کا همارا ایک سیدھا اپروچ هے ۔ ساتھ ساتھ جو ڈفرنٹ اسٹی ٹیوشنز سمال سکیل انڈسٹریل سکٹر میں لگی هوئی هیں ان کے بیچ هم کوآرڈینیشن چاهتے هیں تاکہ سب مل کر ڈویلپمینٹ کے کام کو آگے بڑھانے میں ایک ساتھ آگے چل سکیں ۔

ایک اور اپروچ پانچویں پلان میں همارا اس سلسلے میں هے ۔ اب تک جو سمال سکیل انڈسٹریز کے ڈویلپمنٹ کا طریقه رها هے وه یه رها هے که هم کوئی ٹیکنو اکانامک سروے

پہلے سے کسی بیکورڈ ایریا کا نہیں کروایا - وہاں پر لوکلی اویلیبل را مٹریل یا انڈیجینس را میٹریل جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی اور سکیرس را مٹریل استعمال کرنے والے یونٹس کو رجسٹر کرکے ہم نے سمجھا کہ ہم اس طرح سے ان انڈسٹریز کو سیٹ اپ کرکے ان کو بڑھاوا دے سکتے ہیں - میری رائے ہے کہ سمال سکیل انڈسٹریل سکٹر میں جو لوکلی اویلیبل را مٹریل ہے -

سری راجدیو سنگھ (جونپور) : میرا ایک ویوستھا کا پرسن ہے - منتری مہودے نے کہا ہے کہ بیکورڈ ایریاز میں را مٹریل لوکلی اویلیبل ہے یا نہیں اس کی جانچ نہیں کرائی گئی - میں اسکو صاف کر دینا چاہتا ہوں - کہ بیکورڈ ایریاز کے لئے ایک پٹیل سٹڈی ٹیم اپائنٹ ہوئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ کون کون سا را مٹریل کہاں کہاں ہے -

سری ضیاالرحمان انصاری - یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ نہیں ہوا ہے - میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو مین تھرسٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں پانچویں پلان میں وہ دے رہے ہیں لوکلی اویلیبل را میٹیریل کے اوپر ، اس کے ایکسپلائیٹیشن کے اوپر انڈسٹریل ڈویلپمینٹ کے لئے -

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI Based on the locally available raw materials, I want to know, whether you would establish the industries here or you would export them outside

سری ضیاالرحمان انصاری - ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اینٹرپرونیورر کو کسی خاص جگہ ڈالکر ان کو اگا نہیں سکتے ہیں - اینٹرپرونیورر ہم کو پیدا کرنے ہونگے مقامی طور پر اور اگر مقامی طور پر اویلیبل نہیں ہیں تو پورا ہندوستان ایک ملک ہے اور اگر باہر کے اینٹرپرونیورر آ کر وہاں کے لوکل را مٹیریلز کو ایکسپلائیٹ کرکے انڈسٹری سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرسکتے - اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیجینس انٹرپرونیورر کو تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے -

پانچویں پلان میں ہم این ایس آئی سی کی نئی برانچز کھولنا چاہتے ہیں اور سٹینڈرڈ سروسز کا پرپرووژن کرنا چاہتے ہیں اور فاریسٹ بیسڈ انڈسٹریز کے لئے اینسیلری ڈویلپمنٹ کے نئے دو ہزار نئے یونٹس ایکسٹرا سکیل کے نئے کھولنا چاہیے ہیں - یہ ہمارا نئے پلان میں ایک مین تھرسٹ ہے -

اس این ایس آئی سی کے بارے میں شکایت ہوئی ہے - یہ ایک ایسا کارپوریشن ہے جو بڑی ویلیوایبل خدمت انجام دے رہا ہے - یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ورکنگ میں دقتیں اور پریشانیاں محسوس کی گئی جن کی وجہ سے ایک کمیٹی اپائنٹ ہوئی اور اس کمیٹی کی رکومنڈیشنز منسٹری کے زیر غور ہیں اور ان کی روشنی میں ہم کچھ اس کا سٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں - اس کے

[شری ضیا الرحمان انصاری]

ورکنگ کا، اس کے طریقوں کا اور مینلی نیشنل سمال سکیل انڈسٹریز کا جہاں تک ہائر پرچیز کا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کے لئے ریفائنس انسٹی ٹیوشن کے طور پر کام کرے۔ اس کو ہم سٹیجز میں کرینگے۔ فرسٹ سٹیج میں ایک لاکھ تک ریفائنس انسٹی ٹیوشن کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ این ایس آئی سی ورک کرے۔ ایک لاکھ سے اوپر ہائر پرچیز منسٹری کے لئے وہ خود کریگی۔ لیکن سیکنڈ سٹیج میں ہم سارا کام سٹیٹ گورنمینٹس کے ذریعے سے، یا سٹیٹس کے انسٹی ٹیوشنز کے ذریعے سے کرانا چاہتے ہیں۔ ہم ون مین کمیٹی کے اس پراپوزل کو کنسڈر کر رہے ہیں کہ این ایس آئی سی ریفائنس انسٹی ٹیوشن کے طور پر کام کرے۔

کچھ کھادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز کمیشن کی ایکٹیویٹیز کا بھی تذکرہ آیا۔ اس کمیشن کی ایکٹیویٹیز کوئی محض صنعتی، ادیوگک، ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہمارا سوشل اپ لفٹ کا پروگرام اور ایک فلاسفی جڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عام لوگ گھر میں تھوڑا بہت کام کرکے ملک کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، گاؤں کی لوکل ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کھادی اینڈ گرام ادیوگ کمیشن نے کافی کام کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جب کھادی اینڈ گرام ادیوگ کمیشن اس کام کو مختلف انسٹی ٹیوشنز کے ذریعے سے کرے گا۔ وہ ایک بڑا ڈی سینٹرلائزڈ سیکٹر ہے، تو اس میں کچھ انہیرینٹ ڈفکٹس ہونگے، اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان ڈفیکٹس کو دور کیا جائے۔

جہاں تک اس میں پراڈکشن بڑھانے اور موڈرنائیزیشن لانے کا سوال ہے ہم کھادی کے سلسلے میں ٹریڈیشنل چرخ سے امبر چرخ تک اور امبر چرخ سے نیو ماڈل چرخ پر آئے ہیں۔ جس سے کھادی کا پراڈکشن بھی بڑھے گا اور اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی ویجز میں بھی اضافہ ہوگا۔ لوک وستر کا ایک نیا پروگرام بھی ہمارے زیر غور ہے۔ کھادی اینڈ گرام ادیوگ کمیشن نے پروگرام بنایا ہے کہ عمومی انسان جو کپڑا استعمال کرتا ہے اس کو کس طرح سے کھادی کے ذریعے سے بنایا جا سکے، تاکہ وہ سستا بنے اور لوگ اس کو لے سکیں۔ اس میں سپننگ سیکٹر میں کچھ حد تک پاور استعمال کرکے سستا اور اچھا کپڑا بنانے کا ایک پروگرام انڈر کنسیڈریشن ہے۔

کوئر انڈسٹری کے سلسلے میں کچھ ممبروں نے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا ہے میکینائزیشن کے بارے

میں - اس نے میں اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہوں کہ کوئر انڈسٹری کو مکینائیز کرنے کے سلسلے میں گورنمنٹ کے رخ کو صفائی کے ساتھ عرض کر دوں - گورنمنٹ کوئر انڈسٹری کو اس انداز سے اور اس حد تک مکینائز کرنے کے ہرگز ہرگز حق میں نہیں ہے کہ اس سے ان ایمپلائمینٹ کی پرابلم پیدا ہو جائے - گورنمنٹ کا قطعی طور پر یہ رخ ہے کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کی پرابلم پیدا ہو - کیرل میں ۲۸۳ لوکلی فیبریکیٹڈ ممبرز، جن کے لئے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی، ریٹنگ سیکٹر میں چلنے لگی تھیں اور اس سے کافی ان ایمپلائمنٹ پیدا ہوا تھا - گورنمنٹ آف کیرل نے صحیح وقت پر قدم اٹھا کر ان ۲۸۳ ممبرز کو، جنہوں نے کافی لوگوں کو آوٹ آف ایمپلائمنٹ کر دیا تھا - ڈی آئی آر کے تحت بند کر دیا -

ہم اس طرح کے مکینائیزیشن کے حق میں نہیں ہیں، جو ان ایمپلائمنٹ لانے والا ہے، جو لوگوں کی روزی چھین لے اور ان کو ننگا اور بھوکا کر دے - لیکن اگر ایسا موڈرنائزیشن ہو، یا اس حد تک موڈرنائزیشن ہو جس سے ہماری ایمپلائمنٹ پر اثر نہ پڑے، لیکن ہم ایکسپورٹ کی اچھی مارکیٹ حاصل کر سکیں تو ہم ہمیشہ اس کے حق میں رہیں -

اس نے اس سلسلے میں گورنمنٹ کی کوشش مکینائزیشن کی پالیسی ہے -

۱۹۶۱ میں گورنمنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کوئرانڈسٹری کی ایک تہائی پراڈکشن کو میکینائز کیا جائے - تبھی سے تین میکنائیزڈ یونٹس مینو فیکچرنگ سیکٹر میں لئے تھے - ایک پبلک سیکٹر میں کوئر بورڈ کے تحت اور دو پرائیوٹ سیکٹر میں - اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یا سپننگ سیکٹر میں کوئی مزید مکینائیزیشن نہیں ہوا ہے -

ایک آنریبل ممبر نے سیریکلچر کے بارے میں کہا ہے - میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے سلک بورڈ نے اور مختلف جگہوں پر ہمارے جو سیریکلچر ریسرچ سٹیشن ہیں انہوں نے کس طرح سیریکلچر انڈسٹری کو ڈویلپ کیا ہے - میں آپ کے مادھیم سے آل انڈیا سلک بورڈ کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں اور اس میں کام کرنے والے ریسرچ آفیسرز اور ڈائریکٹرز کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے - میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈرامیٹک شفٹ میں دیکھا ہے - ملٹی وولٹین سے بائی وولٹس کی طرف شفٹ کیا ہے اور کس طرح سے وہاں کسان زیادہ سے زیادہ سلک پیدا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے -

[شری ضیا الرحمان انصاری]

سلک انڈسٹری کے سلسلے میں ایک اور مہتو پورن قدم زیر غور ہے۔ ابھی تک ہمارا زیادہ زور صرف ملبری سیڈ پر رہا ہے۔ ایک نیا پروگرام ہمارے انڈر کنسیڈریشن ہے کہ سبھالین ریجن میں آسام سے لے کر کسمیر تک جو اوک پیدا ہوتا ہے اس سے کس طرح اوک ٹسر ڈویلپ کیا جائے اور اگر اس کے لئے ضروری سمجھا جائے تو ایک اوک ٹسر ڈویلپمنٹ کارپوریشن کو وجود میں لایا جائے۔ دنیا میں ہندوستان کے سلک کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح اس انڈسٹری کو ڈویلپ کر کے فارن ایکسچینج حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی زیادہ زور دیا جانا چاہئے۔

وقت کی کمی کا احساس کرتے ہوئے جو بہت سی باتیں میں وستار کے ساتھ کہنا چاہتا تھا مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں کہہ سکا۔ میں معافی چاہتا ہوں ان آنریبل ممبرز سے جن کی کوئی بات وقت کی کمی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو۔ انہوں نے اس سیکٹر پر جو انڈسٹریل ڈویلپمینٹ کا نسبتاً ایک ویکر سیکٹر ہے جو توجہ کی ہے اس کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہر وقت ان سے گائڈینس لینا چاہتا ہوں اور ان کی اسسٹینس کے لئے اور ان کے خیالات کو حاصل کرنے کے لئے ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔]

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka) : I would like very much to understand the functions of the Industrial Development Ministry. The Report describes these, but one thing it does not make clear is what precisely is the role it plays in respect of basic utilisation, and facilities on which industrial development depends but which are not necessarily within its own control. What role, for instance, does it play in respect of shortages of steel, coal and power ? What would the Ministry do to assist industries which cannot function without an adequate supply of power, steel, coal and a host of other raw materials ? Does the Ministry of ID play the role of spokesman for all these industries which ought to be within its responsibility as against the other Ministries in the Government ?

Today, for instance, I have received a telegram from Ahmedabad pointing to the large number of industries which will virtually come to a halt because of the failure to receive adequate coal or to the Ministry of Railways, one supply. I would presume it is the Ministry of ID which would take up this matter even before this difficulty actually arose When we put a question to the Ministry responsible for coal or to the Ministry of Railways, one puts the blame on the other. But what we would very much like to know is whether the Minister of Industrial Development takes up the cudgels on behalf of these industries well in advance almost as if the industries themselves were putting forward their case and press upon those Ministries, upon Government, for an adequate and satisfactory planning for this purpose. May be—it is possible—he is doing it, but I see no mention of the fact that he is to regard this as one of his most important responsibilities

Take another point, for instance. There is the question of the increase in the price of naphtha in regard to which an announcement was made day before yesterday. Only a few few weeks earlier. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Decrease.

SHRI H M PATEL . No Only a few weeks earlier, the proce of naphtha had been raised from Rs 446 to Rs 2000 It was decreased from Rs 2 000 to Rs 1,000 But the fact remains that the increase is of the order of 250 per cent or more This may be necessary, may be unavoidable from certain points of view But the point of view from which the Minister of ID, I presume, would have taken it up is what its effect would be on the production of other industries dependent on these supplies what effect it would have on their markets, what effect it would have on the price level For instance, one of the inevitable consequence of this would be that the consumer would be paying instead of Rs 9 for a plastic Bucket Rs 21 in future What would be the effect of that ? When you are already fighting inflation, when this becomes an inevitable consequence, the inflation would become from whatever it is today a runaway inflation I would expect therefore that the Minister of Industrial Development should fight the battle within the Cabinet and Government for these industries I hope he is doing it

I would then ask him a question regarding the cement industry The report merely refers to the fact of its installed capacity, what it is actually producing and what is the intended increase of its capacity and so forth But what I would like to know is, why is it that the Government has been following a stop go policy A couple of years ago the cement production was more than enough for the requirements of this country, and indeed, there was something left over for export And then all of a sudden, there is a stop on expansion Now again after creating a shortage—and today the shortage is quite serious—the signal has been given to go ahead How does it help either the industrial development or the economy of the country ?

I notice that the report refers with considerable satisfaction to the fact that they have streamlined the procedure for sanctioning industrial approvals I would like very much to know whether, having established a procedure, it is in fact resulting in speeding up the sanctioning of industrial approvals. I know not only in regard to this but in regard to other matters also, that the Ministry of Industrial Development is not particularly expeditious in replying to references made to it I know of one reference in respect of a request for the establishment of an industry for the extraction of oil from cotton seed, about which I wrote to the Minister myself. I wrote to him only because the industrial unit concerned was not able to get a reply for several months, and to this day I have not received a reply The industrial unit may go ahead because it falls within the medium scale group, where it can do so It has, I hope, gone ahead and I am quite convinced that if it has done so it will have done so partly without fulfilling the necessary pre-requisite conditions Why does the Ministry force an industrial unit which wants to act correctly to act somewhat not so correctly ? I suggest the Ministry while it is rightly interested in streamlining the procedures should also see that having streamlined the procedures in that respect and in certain other respects—undoubtedly they are very praiseworthy efforts and praiseworthy actions—they should also be implements and enforced and all this should result in expeditious action Streamlining is for a specific purpose, it is not for itself Therefore, that is something which I hope he will be looking into

Another thing which I noticed with some interest is the fact that a Commission of Inquiry had been appointed to go into the question of large industrial houses This Commission is known, I think, as the Sarkar Commission The report says

"A Commission of Inquiry on Large Industrial Houses consisting of former Chief Justice of India, Shri A K Sarkar, was appointed on the 18th of February, 1970 to inquire into instances of irregularities, lapses or improprieties referred to in

[Shri H. M. Patil]

the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee. The Commission was required to submit its report by February 2, 1971. The term of the Commission has been extended up to 17th February, 1975..."

There is no explanation to say why the Commission has failed to submit its report by February 2, 1971. Thereafter, it sems to have dawned upon the Ministry that the work of this Commission would take four more years. Is it so certain that even by 1975 the report would be forthcoming If this inquiry was likely to take such a long time, why was it not even realised or envisaged right at the outset? I think these are pertinent questions in respect of an inquiry of some importance.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Ministry comes under attack from different corners every time. Especially, Sir, the vested interests and the monopoly houses always make this Ministry a target of attack by saying that production has come down. They also say that production is not increasing, because the Ministry is not issuing licences properly. Sir, to an extent, they create a climate in the country and put pressures on the Government. Their only slogan is, production. Then, Sir, I would like to ask....

SHRI B. V. NAIK (Kanara) · It is not a slogan. It is a purpose.

SHRI VAYALAR RAVI : He is one among them.

SHRI B. V. NAIK : I am one among you, unless you are going to disown me.

SHRI VAYALAR RAVI : My simple question is this. Production for what and by whom ? This is the only question I would like to ask. Sir, if you take production of Vanaspati and other food items, which are essential for the urban population, you will see that production in these fields is completely controlled by the private enterpreneurs.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : 75 houses.

SHRI VAYALAR RAVI : Not at all.

Naturally, it is a question of policy, whether the Government will allow these monopoly houses as well as the multi-national corporations to expand and influence the whole economic and political life of this country. The experience of Latin American, African and other developing countries is,—this is true even today—these multi-national corporations which have been operating in these countries have always collaboralted with the national vested interests, made political capital and they even tried to topple the democratic institutions of those countries. It is a fact. Nobody can deny this. In Santiago, where the UNCTAD Conference was held, the late President Allende suggested the setting up of a commission to go into the working of the multi-national corporations. In fact, India had the privilege of becoming the Chairman of this Commission. Now, the question is, are we playing the role that is expected of us ? Are we doing our duty in that respect ? Are we fulfilling the expectations of the developing nations ? What is the purpose of setting up such a commission ? It is only to prevent these multi-national corporations, operating through different international agencies, and big capitalists, from influencing the political and economic life and thereby topple—I repeat—the democratic institutions of those countries. My only appeal to the hon. Minister is, he should consider this fact and he should take into account the feelings of other developing nations in regard to these multi-national corporations. He should be careful while giving whatever little preference to these multi-national corporations.

Sir, the slogan of production has gone only to help the monopoly houses to expand more. I definitely agree that small-scale and local entrepreneurs should come up and invest more. But, unfortunately, this is not happening. In

the name of production, all these big houses are given financial assistance by the public financial institutions. Sir, on the floor of this House, the hon. Minister himself has admitted that bulk of financial assistance from Industrial Development Bank and other financial institutions, banks and even LIC, has gone to the big houses. If the Government are to finance all these big houses, then, the only simple question is, what is the purpose of these monopoly houses? They will collaborate with the vested interests and they will always try to create chaos in the country. I repeat that more and more entrepreneurs should come into the field. In this connection, I would like to ask the Minister, what is the purpose of DGTD? The Minister himself admits that it functions only in an advisory capacity. He wants to do something. I have no complaints against him. He is very eager that more industries should come up in the country. There is pressure from unemployed youth for more employment. The monopoly houses have no complaint against the functioning of the DGTD because DGTD is functioning more to protect the interest of the monopoly houses and prevent the smaller entrepreneurs from coming up. Naturally when they form an advisory committee and give a technical report, even the minister's hands are tied and he says, "This is the report of the advisory committee." When the reports of the Planning Commission and other ministries are there, what is the purpose of this advisory report? They are not even technocrats. They merely serve the purpose of the monopoly houses. So, I submit that the minister himself should process it, without depending upon this advisory report.

I had some complaints against the Small Industries Development Corporation earlier, but not now. Fortunately the Government got rid of the gentleman who was there for a long time and the minister himself took more interest in improving its functioning. But there is one point. There was a conference in Kerala in 1968. There was a big programme for giving machinery and small industrialists deposited their hard-earned money. But unfortunately they could not get the machinery nor their money back. The complaints are still there and I request the minister to look into this.

Coming to the establishment of a paper corporation in Kerala, NIDC were appointed technical advisers in collaboration with Siemens. But it seems the collaborators have backed out now and it has created a big problem. I raised this matter in the House earlier and the minister took some initiative and assured the House that the paper corporation will be established in 1976. Even though this difficulty has cropped up now, I request the minister to see that necessary steps should be taken to commission this plant in 1976 itself.

The employees of the HPC have an apprehension that the corporation may be shifted to Calcutta. I request the minister not to put more hardship on the people working in Delhi by shifting the office to Calcutta.

Coir and khadi have been mentioned. Coir is a subject about which only people from Kerala can speak. Coir industry is giving rural employment and the bulk of the rural population are earning their livelihood through this. Their wage is the lowest—Rs. 1½ or 2. Yet, we could not provide proper employment to them because of certain difficulties. Even though the exports have gone up in terms of money because of higher prices, in terms of quantity the exports have come down from 51 to 49 lakh tonnes. It means production has gone down resulting in lesser employment opportunities. That is why the Kerala Government made a proposal for restructing the industry. It has been admitted here and I quote:

> "The Government of Kerala initiated implementation of special schemes for the re-structuring of the coir industry."

[Shri Vayalar Ravi]

I know the hon. Ministery is very much interested in improving the coir industry. I would like to know from him what he proposes to do and how he is going to help the Kerala Government.

SHRI C. SUBRAMANIAM : We would like to know it from you.

SHRI VAYALAR RAVI : Our demand is that you should give at least Rs. 15 crores in a phased manner for the restructuring of the coir industry.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It is not money that is the problem, but it is something else.

SHRI VAYALAR RAVI : If money is not the problem, I would be very happy. Definitely we can help the Minister to sort out the other problem. The Kerala Minister said that even though the Planning Commission promised about Rs. 45 crores, the provision this year is only Rs. 1.5 crores, whereas we expected at least Rs. 3.5 crores. Since the Minister says that money is not a problem, I hope he will look into this because it concerns my constituency also.

Lastly, I come to the Khadi and Village Industries Commission where a lot of employees are working. There are no rules or regulations for appointment transfer and promotion and they are done mostly on the basis of favouritism or patronage. I hope the Minister will go into this.

Finally, I would say that our industrial policy should be based on socialist outlook and there should be no departure from that policy.

SHRI D. D. DESAI (Kaira): Sir, while supporting the grants, I would like to offer few constructive suggestions to the industries Minister. The industrial sector has been slipping badly during recent years. It has about 9.3 per cent growth in the early sixties and we maintained it for six years. From 1966 onwards we are on downward grade. Last year we had almost nil and this year I would not be surprised if we end with a minus figure. But I am not interested in the figure part of it; I am more interested in seeing that the industries do pick up at the earliest opportunity, because the extent of disorder or dicontent that is prevailing in the country is rather upsetting for any thinking person. We have to go back to the last decade and see what are the policies which had brought us to the present state of stagnation and also inflation in fact, if we are putting it collectively, stagflation resulting in huge unemployment. This is an explosive matter.

Individual items have been taken care by most of our friends. So, I would rather concentrate on the policy part of it. By calling a country democratic, it does not become democratic; by calling a country socialist, it does not become rich In that way, we are a poor man by name Dhanpal he does not become rich. In that way, we are only deluding ourselves There are today countries in the world which have a very high standard of democracy, human freedom and liberty, a definite amount of highest development and highest social benefits and socialism that we are aspiring for.

Here, I would like to quote from a recent book on Sweden some of the information which is no different from our economic policy goals :

> "The central goals in the management of the Swedish economy are: rapid economic growth, high and stable employment, reasonable price stability, a more even distribution of income and regional balance."

There have been the things that we have been talking about. Is this country or these people of Sweden really socialist or not? As for the amount of money that the Swedish Government and that country spend on development and social activities, I think, there is no equal in the whole of the world. Their *per capita* income is the highest in Europe; the wages are the highest in Europe; the strikes are the least; the

man-hours lost are the lowest. In each respect, the Swedish economy has done so well. Why should we not have some sort of examination, if necessary, on the lines of what Sweden is doing? We are today pursuing the examination and collaborations with so many other countries. Why don't we also find out how best we could make use of the technology, the know-how, that Sweden has developed for socialism and democracy?

There is another thing which inhibits our growth. One of the main reasons stated has been the labour problem. The labour problem is the root of it. Of course, the labour has reasons to feel dissatisfied. One of the reasons for their dissatisfaction is inflation because the wages that they receive become low. In other words, in real terms of value, the money is losing significance. This is one of the effects of scarcity and inflationary condition.

In Sweden, they have certain labour laws and, generally, the people are under the impression that labour disputes must have been left to themselves as elsewhere and they must be creating a chaos in the society. Sweden has an elaborate system of avoiding labour disputes. I quote :

> "The law provides facilities for negotiations. If preliminary negotiations fail, the employees are not allowed to strike until they have officially given a week's notice. This week is spent in efforts to avert conflict and, at this stage, negotiations are led by a Government appointed mediator or a group of mediators
>
> The right to resort to conflict measures is subject to certain limitations by law."

This is something which might interest our friends. We have uninhibited right to strike. We know the present problem of Railway, coal and steel. Steel production which was in 1965-66 is not matched in 1973-74. This is something which is unheard of with such huge investments in important core sector of the country. The same thing is about coal. There is stagnation in production. There are transport bottle-necks in the movement of articles There is the problem of power. We have put in large sums of money. We are told that a large amount of generating equipment are lying idle for want of maintenance, for want of coal, for want of this and that. This is an unfortunate situation which we have to resolve if we have to avoid unprecedented unrest which, I am afraid, has hurt us badly and we may all be the victims of the situation.

The fiscal and credit policies also require a certain amount of change. We have seen that taxation does not leave money for investment. We have seen that if at any time the development rebate is required by the country it is this time because we are short of new entrepreneurship, we are short of goods, services and so on.

15 HRS.

[SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair.*]

We have already got sick units and the way in which we are maintaining sick units is quite interesting. For example, we are quite proud of certain sick textile mills making profits.

These sick textile mills obtain from fine and superfine mills a certain lump sum amount per metre of coarse cloth quota. They are expected to manufacture coarse cloth of efficient mills quota which the cooperatives and others are disposing of after little process in the open market and are making around Rs. 40 to 50 crores. This is what is going on. I do not want t o go into the details. I only want to point out that this mechanism is going to hurt the economy of the country.

The licensing procedure has been considerably changed. I would like to say that the licensing policy also requires certain modifications to the extent that we should not be carried away merely by dogmas but want to achieve a cer-

[Shri D. D. Desai]

tain development in the country. It is said: let the cow be fettened and then milk it and do not butcher it. That is one way of looking at it. If we butcher it, we have it only for one day, but if we fatten it and milk it, it is there for all the time. The industry can give income to the State. As some economists have said, ten to twelve per cent growth is good enough to give the State Rs. 1,000 crores of additional income annually. This is how we should look at it. This is not something which is not possible in the country. The demand for goods is there; the talents are there; everything that we can hope for is there. I am not saying this just by way of criticism only; I am saying out of the sincere feelmg that we have to set right our house; and earlier we do, the better—before it is too late

We have been talking about unemployment is there. I would estimate that we have to create one crore additional jobs. One cannot get a good salary with the per capita investment of Rs. 10,000, i.e., one job for the capital investment of Rs. 10,000. That means, to create one crore additional jobs, there should be investment of Rs. 10,000 crores. Where have we got the money? From where is it going to come? Therefore, I would suggest strongly that we have to go in for handicrafts. That is an area where we need only a limited investment and improvised tools; people are used to handicrafts; the cost of dislocation and the cost of re-location is to the barest minimum; and it can generate employment opportunities and can produce consumer goods. If we have to create one crore additional jobs, we must somehow or other provide as much training as possible for undertaking handicrafts in villages. You may call it a Gandhian policy After all, ours is a large and a poor country, with practically not much of exchange resources or capital; ours is a capital-hungry country. Even if we provide huge plants, how much employment are they generating? Our experience has been that it creates more tensions between the employed and the unemployed, it creates social tensions, it has dislocation problems and so on and so forth.

Now I come to agro-industries. Our entire economy picked up during the late Sixties. The reason was good agricultural production. We had the growth rate of 7.9 per cent or about 8 per cent principally due to agro-industries. But, unfortunately, I find from the planning Commission's report that the provision for agriculture has been very limited. If the provision for inputs for agriculture is also reduced, then we will have a poor performance on the agricultural front, and with the present day economy of the world and the shortage in agricultural production in the world, we cannot look anywhere for our requirements; we cannot do without them.

With these words, I support the Demands for Grants in respect of the Ministry of Industrial Development and the Department of Science and Technology.

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi) : I rise to support the Demands of the Ministry of Industrial Development and Science and Technology.

If you go through the reports of the Department of Science & Technology for 1971-72 you will be proud to know that our scientists have done a very good and commendable job. Various researches have been made and they have been commercialised and brought into operation. Various laboratories—Chemical laboratories, physical laboratories, metallurgical laboratories, fuel research laboratories, rubber laboratories—all these laboratories are doing a splendid work and they are helping the industrial growth of this country. But the financial provision for Science and Technology, I find, is rather meager and I would request the hon Minister to review it and increase the allotments for this vital Department.

Yesterday some of the friends opposite were agitated and said that the

Minister revised and liberalised the licensing policy and shamelessly given opportunity to the monopolisits to exploit it. That is not the correct position. We have to revise and liberalise the licensing policy wherever called for. Of course, the monopolists should be curbed. They should not be allowed to use all the profits for themselves. All the capital with the monopolists or with the public sector or the private sector must be utilised to increase the production in the country. Even the foreign capital that is here now should be utilised fully. I can undertand if you would not allow any more foreign capital and domination in this country, but those who have already invested, their capital we must utilise. To day only in the Press it has appeared that Hindustan Lever, a company with major foreign shares, has been issued a licence to manufacture STPP. While doing so, the MRTP has laid down certain conditions, that more capital will be issued exclusively to Indians and no more foreign share-holders will be given any opportunity to join in this and secondly 20% of the production will be reserved for export and thirdly, the output will be utilised for not only themselves but for other people also who are manufacturing detergents. We have to save edible oil and so encourage the use of detergent in the country. In the circumstances, all the capital in the country, whether private or public or even the foreign capital that is here in the country, must be utilised to the fullest extent and we must increase the production in the country. Unless we do this, it is very difficult for us to survive as a free nation.

The licensing policy in the case of cement should have been revised earlier because it is such a heavy industry that it is not possible to attract people to make investment as its capital requirement is very large and the returns are rather low. So, only big capitalists will come in. And the public sector cement factories should be increased. But the shortage of cement could have been compensated if the licensing policy had been reviewed and revised earlier as also by issuing more licences or permitting expansion of the existing units and I hope this will be reviewed now.

Then I come to the salt industry. There are two public sector salt firms —the Hindustan Salts and Sambhar Salts. They are doing very well and are making very high profits. We should be very proud of them and we commend their performance to the other public sector concerns. Along with that, I would request that the small salt pans should also be encouraged. In the co-operative sector a big unit has come up in Palghar. The Maharashtra Co-operative Fertiliser Society has come up. Various societies have joined and started a very big salt manufacturing concern. Some thousands of acres of land have been allotted to them. This salt can be utilised to manufacture ammonium chloride from sodium chloride and this can be used as a fertiliser. One more point. You will have to review the position of the Shilotris or the small salt pan owners. They own salt pans but after their death their children are not allowed to inherit them. I don't know how this can be done. Even as per the Land Legislation after the death of a father the son inherit the lands. So, this should be looked into. I would request the Minister to review this position and remove the difficulties of the small salt pan manufacturers. At Bhayandar and round about, salt pan manufacturers have to go to Bassein to get clearance passes of permits for the disposal of salt. This causes great difficulty. This should be looked into and their difficulties must be removed.

Now, regarding the rubber industry, raw rubbish is just enough to meet our requirements of rubber manufacturers. There was a slump last year and rubber was allowed to be exported but this year the position is reversed. Now we are short of rubber because synthetic rubber production has come down considerably. From 30,000 tonnes it has come down to 20,000 tonnes. In respect of natural rubber if you allow exports like this, I

[Shri Dhamankar]

think a situation will come when we will be forced to import rubber from outside from other countries. This should be avoided and to avoid this, I request the hon. Minister to review the position and see to it that export of rubber is restricted.

The National Textile Corporation is doing commendable work. That is managed by the Industrial Development Department. The textile mills and the decentralised sector, that is, handlooms and powerlooms are with the Commerce Ministry. I feel that this position should be reviewed. The Textile mills and the decentralised sector of powerlooms and handlooms should go under the purview of the Industrial Development Department and not under the Commerce Ministry. I say this because Commerce Ministry is concerned with internal trade and foreign trade which is their main work. They are not concerned with industry and therefore I feel that this should be examined.

The definition with regard to small-scale industry stipulates that its capital limit would be 7.5 lakhs. This has been increased to some extent now but still I feel that it is very low and it should be reviewed again. The value of rupee has gone down. One lakh of rupees of licence will now fetch goods worth only Rs.25,000, because the value of the rupee has gone down. So, I request that this position should be reviewed and this amout should be increased.

My last point is regarding the Khadi and Gramodhyog Commission. The management of the Khadi and Gramodhyog Bhavans should be examined. If you go to their shops they are not prepared to go and show you the things inside. They simply sit in the chair showing utter disregard to the customers. It has become their monopoly and they behave as monopolists. They must learn how to treat the customers. If you go to a private shop you will find that they go inside and show you so many things and they persuade you to buy. But here you find that these people show utter disregard to the customers. So, this should be reviewed. This is my respectful submission. With this I have done.

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupzha) : Sir, I am told, the time allotted to each Member from these benches is drastically cut.

Therefore, Sir, I am not able to traverse the whole ground which I had contemplated to do. To my great relief Professor Dhamankar who preceded me has materially covered the grounds which I too wanted to emphasise with respect to the small-scale industries there is only one point which, due to the constraints of time, I particularly want to emphasise

The hon. Minister himself, in his speech, underlined the importance of small-scale sectors in the conditions of economy obtaining in this country.

It will be observed that there are two vital problems that we have to face—one is the rise in prices and the other is the rise in the rate of unemployment. If these two problems are not tackled, no solution will bring about stability either political or economic.

Looking forward, the position is rather dismal. The year we are facing happens to be under a synchronistic circumstance, the first year of the Fifth Five Year Plan. The current year is the taking-off stage for the Plan. The review before us, reports that the year just past has recorded zero growth. It is not able to promise that the position would be better. The Ministry's report says that the circumstances are such that they cannot promise that tomorrow is going to be better than yesterday.

The unemployment problem is rather too frightening. The Fifth Five Year Plan emphasises that an estimated addition to labour force is about 65 million. This alone is more than three and half times the present level of employment in the entire organised sector, including both public and private sectors. In addition, there is the huge back-

log of unemployment, underemployment and thin (very low productivity) employment. These 65 million people is in addition to the carryover. So, the backlog is not being reduced. This is a very frightening picture indeed. My hon. friend, Shri D. D. Desai pointed out the strategy by which we can handle this. And the Fifth Five Year Plan is fairly clear about it. And this is what it says ; I quote from the Fifth Five Year Plan the following :—

> "From the data regarding the entire factory sector for 1968, the fixed capital per employee, on an average, in small scale industrial unit was as low as about Rs. 3,170, as compared to about Rs. 22,000 in a large scale unit. Moreover, while the small scale sector accounted for about 7.5 per cent of the total fixed capital investment in the factory sector, its share in the total output was as high as nearly 28 per cent. If account is also taken of small industries below the factory level including the household units, the share of the entire small industries' sector in total industrial output would be considerably larger".

This is how they have contemplated. That being so, the question is : Is the policy sufficiently reflected or not ? The allotments made in the Fifth Five Year Plan are claimed to be more than double those allotted in the previous Plans. That makes no difference at all because taking into consideration the value of the rupee it cannot be said that it is more than double than of the previous Plan. It only means that *status quo* remains and no additional weightage is given to the small-scale sectors at all. The Report before us is certainly good intension, good evaluations and fond expectations. I do not say that the valuation made is bad. I want to ask : have we gone into the task with a real gusto ? Is there any mechanism by which we can expect that the Plan strategy will be implemented or it will be converted into practice. The Minister said that the entrepreneurs cannot be created. I would say that entrepreneurs must be created. There is no other way. Supposing you do not. The public sectors flounder. Enterpreneurs do not come in. What is the result ? Unemployment will mount; production slumps; there will be price rise to the consternation of everybody. If you want smallscale sector to flourish, you should find them out; you should help them; there should be financial help given to them when they come forward with their project reports. They should be assisted in all possible ways.

Sir, the present position in the rural areas is this. Initiative is not taken by the entrepreneurs. Each area should be put in charge of somebody. The persons put in charge for doing a thing should be judged by their performance. They should take into consideration the prevailing circumstances in each area and should evolve schemes. They will have to find the entrepreneurs and there must be a linkage of the banking and financial assistance and also the technological skills. That way alone we can solve the problem. Now the Five Year Plan says that the major part of the unemployment problem will have to be solved from the agricultural sector. We know how far that is possible. If that is not possible what is going to happen ? There will be migration to cities and in the cities there will be no solution. Socio-economic tension will develop and there will be complete breakdown. Therefore, I would appeal. let us go back to the Old Man, the Father of the Nation, who emphasised that the solution to the economic problems in this country is village industries and the small scale industries. Advertising to another point, Shri Vayalar Ravi was emphasising about monopoly. Attack on monopoly has become a fashion. Nobody is there to support the monopoly. But the question is how to develop production, how to bring more produce and how to give employment. That is the question. Let us not take negative attitude and let us not imbibe sadistic pleasure in taking negative slogans but rather put more positive emphasis.

Certainly there must be restrictions and bridles so that the national interest

[Shri C. M. Stephen]

is not in jeopardy. If the democracy which we are having is dynamic enough there is nothing to fear. But the need of the hour is higher production. That need has not been created by anybody nor is it an artificial one. That is a writing on the wall and the writing has to be taken note of and the challenge has to be answered. Therefore, there should be emphasis on production and employment. Let us go on to the small scale industries and with regard to the large-scale industry let us evolve a policy whereby the installed capacity which is available in this country does not lie idle even for an iota. Let us have a breakthrough on these two fronts, namely, production and unemployment. With these words I support the Demands of the Ministry.

डा० कैलाश—(बम्बई दक्षिण) सभापति महोदय, मैं औद्योगिक विकास, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जहां तक साइंस और टेक्नोलोजी का संबंध है, उस की रिपोर्ट में कहा गया है, प्लानिंग कमीशन भी यही कहता है और पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाते समय भी यही कहा जाता है कि हम सैल्फ रेलायंस प्राप्त करना चाहते हैं, और उस के लिये हमें साइंस और टैक्नोलोजी का पूरा सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि साइंस और टैक्नोलोजी के लिये प्लानिंग कमीशन ने कितनी रकम इस मंत्रालय को दी है, तो मुझे लगता है कि वह रकम इतनी थोड़ी है उस से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और हमारी फिजिकल लैबोरैटरीज और एन० सी० एस० टी० शायद उतना काम नहीं कर लेंगे, जितना की हम उन से आशा करते हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे नैचुरल रीसोर्सिज से-फारेस्ट्री, वृक्षों अर्थात वन-सम्पदा से और भूगर्भ में पड़े मिनरल्ज और आयल और नैचुरल गैस से हमें जो आमदनी हो सकेगी, उस विषय में एन० सी० एस० टी० ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है। रिपोर्ट में कहीं यह नहीं बताया गया है कि एन० सी० एस० टी० ने यह कार्य किया।

सभापति महोदय क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि साइंस और टेक्नोलोजी में इंडिजिनेस रिसर्च भी होनी चाहिये और केवल पश्चिम का अन्धानुकरण नहीं होना चाहिये।

डा० कैलाश आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम ने सिर्फ पश्चिम को एक आदर्श मान कर काम करना शुरू किया, तो शायद हम अपने तकनीकी विद्वानों को एक गलत रास्ते पर ले जायेंगे। इसी लिये मैं ने कहा है कि हमें वन-सम्पदा और मिनरल्ज की तरफ ध्यान देना होगा। वह भी देश की परिस्थितियों तथा मांग को ध्यान में रख कर ही यह सब कुछ करना होगा।

जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, हम देखते हैं कि हालांकि इस वर्ष अंजिया ज्यादा आई है, सरकार ने लैंटर्स आफ इनटेंट भी ज्यादा दिये हैं और लाइसेंस भी ज्यादा दिये हैं, लेकिन ग्रोथ घटता जा रहा है—वह 1 परसेंट या जीरो परसेंट की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिजली नहीं मिल रही है या वर्कर्ज के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं रहे हैं? एन० सी० एस० टी० की यह भी जिम्मेदारी हो जाती है कि देश की फ्युअल और पावर की रेक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाये, जिस से हमारा औद्योगिक निर्माण ठीक प्रकार हो सके।

मंत्री महोदय ने रिसर्च और डेवेलपमेंट की एक नई कल्पना देश के सामने रखी है। रिसर्च और डेवेलपमेंट के नाम से एक अलग से महकमा शुरू किया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि रिसर्च और डेवेलपमेंट से देश के कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कितना फायदा मिला है।

पिछले कुछ समय से बल्गारिया, यू० एस० एस० आर०, चेकोस्लवाकिया, पोलेंड और हंगरी आदि देशो के साथ हमारे साइंटिफिक रिलेशन्ज स्थापित हुए हैं। ऐसे एग्रीमेंटस पहले भी होते रहे हैं। अगर रिपोर्ट मे उन के बारे मे कुछ प्रकाश डाला जाता, तो अच्छा होता।

जहा तक औद्योगिक विकास का संबध है, हमने आर्डरली डेवेलपमेंट आफ लार्ज, मीडियम एंड स्माल-स्केल इडस्ट्रीज की बात कही है। हमने डेवेलपमेंट आफ खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज, पब्लिक सैक्टर प्राईवेट सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर की बाते की है। लेकिन लार्ज सैक्टर के बारे मे कुछ लोगो मे एक अजीब सी धारणा बनती जा रही है। देश को स्वावलम्बन की ओर ले जाने वाला जो भी व्यक्ति हो, अर्थात जिसके पास रुपये और नो-हाउ का उपयोग करने की शक्ति हो तब वह मोनोपली हाउस ही क्यो न हो उस को ऐसे क्षेत्र मे कारखाना लगाने की इजाजत देनी ही चाहिये, जो भाग पिछड़ा हुआ है, तो उस पर भी अगर टीका-टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है कि हम पैसे वालो को और पैसे वाले क्या इजाजत दी गई तो यह दुःख का विषय है।

हमने तो देखना है कि किस तरह देश मे ज्यादा धन का उत्पादन हो और किस तरह पिछडे हुए क्षेत्र आगे बढ सकें। अगर हम किसी मोनोपली हाउस को कुछ बधनो के साथ, जिन का जिक्र माननीय सभासद श्री देसाई और श्री स्टीफन ने भी किया है, एक इनसेक्टीसाइड्ज बनाने वाला कारखाना लगाने के लिये उस सस्थान को लाइसेंस दिया गया, तो मैं समझता हू कि उसके विरुद्ध कोई गडबड नही की जानी चाहिये।

लेकिन सरकार ने मीडियम स्केल और छोटी इंडस्ट्रीज के साथ बहुत अन्याय किया है। अभी हमारे डिपुटी मिनिस्टर साहब बहुत ही भावुकता मे सब बोल रहे थे। इसमे कोई शक नही है कि उनका दिल तडप रहा है। लेकिन उन पर कौन से बधन आ रहे हैं, यह समझ मे नही आता है। रिपोर्टें बनती है, लेकिन वे ताले मे बन्द पडी रहती हैं। न तो मीडियम स्केल के कारखाने बढे न ही छोटे कारखाने।

मिनिस्टर साहब ने चार्ज लेते ही कहा कि हम नब्बे दिन मे लाइसेंस दे दिया करेंगे लेकिन मेरी जानकारी है कि ऐसे लडको ने, जो इजीनियरिंग पास कर के आये हैं अर्जी दी है, लेकिन तीन-तीन महीने तक उन के लाइसेंस का पता नही चलता है। उन की स्कीम की दोहरी छनाई की जाती है। एक तो मत्रालय करता ही है और जब बैंक के पास जाते है, तो वहा पर छनाई होती है जिस से उन को न पैसा मिलता है और न लाइसेंस। क्या मत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे ?

फिर यह सब कुछ तय हो जाने के बाद भी मीडियम इडस्ट्रीज और स्माल-स्केल इडस्ट्रीज को लोहा और सीमेंट नही दिया जाता तो वे आगे नही बढ सकते। इस लिये सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि उन्हे लोहा, सीमेंट और बिजली ठीक समय पर मिल सके। जिन इजीनियर्स ने जमीन ले ली है, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उन को बिजली नही दे रहे हैं। इस लिए जब तक सब डिपार्टमेंट्स मे आपस मे समन्वय नही होगा, तब तक इस औद्योगिक प्रगति नही हो सकेगी। सीमेंट कार्पोरेशन के बारे मे मैंने आप के सामने अभी कहा है। वैसे ही हिंदुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को चलते हुए कई वर्ष हो गये लेकिन इस का कोई आगे कदम नही बढ पाया क्यो कि शायद इस कारखाने की सारी पुरानी मशीनरी चली आ रही है। उस पर कोई ध्यान नही दे रहा है। वह एक ऐसी इडस्ट्री है जो पब्लिक सैक्टर मे होते हुए भी ठीक तरह से नही चल रही है। अगर वह ठीक प्रकार से चले तो कोडक और अगफा को भी वह हटा सकती है या वह हमारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हो सकते हैं। हमारे फोटोग्राफर चाहते हैं कि उन्हे हिंदुस्तान

[डा० कैलाश]

फोटो-फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी का कागज मिले जिस को वह उपयोग में लायें लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता और उन्हें कोडक और अगफा के पास ही जाना पड़ता है । इस के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने चार जगह पल्प और कागज बनाने के कारखाने खोलने का प्लान बनाया एक मन्ड्या, दूसरा केरला पल्प ऐंड प्रोजेक्ट, तीसरा नागालैंड पल्प ऐंड पेपर प्रोजेक्ट और चौथा नौगांव पल्प ऐंड पेपर प्रोजेक्ट है । आज देश में बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों के लिये कागज नहीं है और अखबार वालों के लिये कागज नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड इस पर ध्यान क्यों नहीं देता ? इस में कहां कठिनाई आ रही है उसे देखने की आवश्यकता है । मंत्री जी बताने की कृपा करें कि ये कारखाने शुरु किये जा सकेंगे ?

खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में भी मेरा बड़ा बुरा अनुभव रहा है । इतना बड़ा सेल है पर वहां जो बेचने वाले कर्मचारी हैं उन का कोई सहकार ग्राहकों को नहीं मिलता वह शायद इस घमंड में रहते हैं कि उन का सेल इतना ज्यादा है तो क्यों किसी की चिन्ता करें ? मंत्री जी मंत्रालय खादी और विलेज इंडस्ट्रीज पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे है उन्हें देखना है कि खादी भवन और अन्य दुकानें किस प्रकार से चल रही हैं । अगर उस तरफ ध्यान दें तो अनएम्पलायमेंट का सवाल भी हल हो सकता है और देश के आगे बढ़ने में भी उससे मदद मिल सकती है क्योंकि उस में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उस की ओर अवश्य ध्यान दें ।

SHRI P. R. SHENOY (Udipi) : Though the big industrialists have continued to amass wealth, industrial production in 1973 has gone down. The reasons given for the decline in production are failure of the monsoon, shortage of power, transport bottlenecks in the movement of industrial inputs, steep rise in the prices of imported industrial raw materials such as crude oil, steel and non-ferrous metals and disturbed industrial relations. These are only some of the reasons. The reasons not disclosed by the Ministry in the Report are growing inefficiency in administration, faulty planning by the Planning Commission resulting in shortages of production of industrial inputs such as coal, pig iron, steel and cement and other essential items, non-implementation of physical targets fixed at the commencement of the Plan by the Planning Commission itself, inability to implement major projects within the prescribed time-limit, non-utilisation of capacities and irrational labour policies leading to strikes and other labour unrest.

It has been said that the licensing procedure has been simplified and licences are now issued quickly. Figures of disposal of letters of intent and licences are given in the report, but not those of pending applications in 1973. At the end of October 1973, the different applications for licenses pending with the different Ministries total 3,861. Of these, 1,692 were of 1972 and years prior to that. Therefore, unless information is collected by computer and unless some real reform is made in the licensing procedure, delay is bound to occur in the issue of letters of intent and licences.

Sir, when we formulate plans, we do not assess the actual requirements after a certain period. We simply add a certain percentage to the production in the field of every product, whether it is coal, or oilseeds or cement or steel or baby food. We simply say that it would be five per cent extra after five years or six per cent or seven per cent extra. We do not assess the real requirements after five years. Unless we make a real assessment, ultimately what we will produce will not be enough for the consumption of our people. In other words, we are not planning for

plenty but we are planning for shortages. This system should be changed while we formulate the plan.

Then again, we fix some physical targets while we formulate the plan and we also fix the financial targets, but at the end we only declare that we have reached our financial targets but we never fulfil our physical targets. This is especially so in the case of power plants. In many power plants we have declared that the installed capacity of the power plant is so much, but the real capacity is much lower than the installed capacity. In the case of major irrigation, the actual physical targets are much lower than the physical targets that are announced in the beginning.

Then the capacities of different plants are not fully utilised in our country. No doubt in the report it is said that utilisation has gone up, but what is the percentage of utilisation now? Have we reached at least 85 per cent of the capacity? We have not. In almost all the heavy industries also, as in the steel industry, for example, our utilisation is much below 85 per cent, and it is even below 75 per cent in fact. The utilisation of the capacity should be not less than 85 per cent, and we should achieve this as early as possible.

Then, we do not implement many projects within the time fixed. For instance, we have spent crores of rupees in the installation of the Vijayanagar steel plant, and I am sure at the present rate of construction this steel plant will not come up in the next 15 years. How much money we have wasted and how much interest we are losing on that? I do not think that even the steel plant proposed for Visakhapatnam will come up within the next 10 years, and as reported recently, even the small steel plant proposed for Salem will not also come up within the scheduled time. The construction of the Mangalore major harbour started in the year 1965, and even after about 10 years, it is not completed. They have spent more than Rs. 15 crores. What is the interest on this money? This interest is wasted and the prices will go up as the construction of the project is delayed.

There must be a national wage policy if there should not be any strikes. We cannot stop strikes by magic. Unless the workers in this country are satisfied, they will continue to stage strikes. The only way of stopping the strikes is to have a national wage policy. At present, the wages are different at the Central level at the State level and at the public sector level. At different levels we are having different wages. So, unless we have a national wage policy, there will be unrest among the labourers.

Another point is, bonus should be related to profit. At present, it is not related to profit. According to the famous economist, Prof. Dandeker, if bonus is related to profit the workers will stand to gain. He has analysed the profits in major factories which are well run, and has shown that if bonus is related to profit, if the labour of a worker is treated as his contribution towards the capital for that particular year, and if he is also given bonus, as the shareholder is given, he stands to gain. The production in the factories will go up.

Sir, the National Textile Corporation is managing 103 sick mills, of which 92 are in operation. It is gratifying to note that most of these units are making profits, and the Corporation, as a whole, is also making profits. But, Sir, out of the 450 million metres of cloth produced by this Corporation, only about 20% is controlled cloth. The Corporation should produce fine cloth only for the purpose of export. The remaining should be controlled cloth. The Corporation should give a lead to other textile mills in the private sector in the matter of production of controlled cloth. Sir, it is the present Minister of Industrial Development who gave the slogan 'banish poverty' to this country. But, if poverty is to be banished, there must be sufficient food and sufficient cloth. The National Textile Corpora-

[Shri P. R. Shenoy]

tion should make available controlled cloth for the use of the poor people. Similarly, for lakhs of handloom weavers in the country, who are now unemployed, the National Textile Corporation should make available adequate quantity of yarn.

Sir, the Cement Corporation of India has proposed to set up a cement factory in Himachal Pradesh, two new factories in Madhya Pradesh and two new factories in Andhra Pradesh. This is a very good proposal. The only question is, whether the Planning Commission will accept this proposal. The Minister should see to it that this is accepted and cement production in the next Plan....

SHRI C. SUBRAMANIAM : All these are accepted.

SHRI P. R. SHENOY : Then, it is very good. This is a very good proposal. Lakhs of house sites have been distributed to landless people for construction of houses.

MR. CHAIRMAN : You have got your answer. Please conclude.

SHRI P. R. SHENOY : They have to construct houses on these sites. For this, they require cement. On these small sites, they have to build houses. If the houses are built, there will be construction activity and more people will get employment. So, keeping this in view, cement production should be doubled in the Fifth Plan.

One more point. This is about big industrial houses. I am not against big industrial houses. But, I do not understand, why should we go out of the way to give them incentives. Sir, it is true that backward areas should be developed. But, backward areas can be developed only by giving incentives to small industrialists and not big industrialists. These monopoly houses or large capital, are given this subsidy. These big industrial houses do not require these incentives. They do not go to a particular area on the basis of the incentives given. For instance, the MRTP Act is not applicable to Jammu and Kashmir. But, still, no monopoly house would go to Kashmir to establish a factory there. Similarly, South Kanara District in Karnataka is treated as a backward district. Even if it is not treated as a backward district, the big industrialists will go there, because a major harbour is coming up there. Why should we give them incentives to stare industries in Managlore, where a major harbour is coming up ? These incentives should be given to small indstrialists and not to the large houses.

Lastly, the recommendation of the Bhat Commitee, in regard to small-scale industries, should be implemented as early as possible.

श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी) : सभापति जी, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी क ध्यान उत्तरी बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारे उप-मंत्री जी ने कहा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश से प्लानिंग कमीशन करता है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—बिहार के जिन 11 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, जिन में खास कर उत्तर बिहार के पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तो चुन लिये गये, लेकिन उसी तरह की स्थिति सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जिलों की है, इनको क्यों छोड़ दिया गया ? इन तीनों जिलों में कोई इण्डस्ट्री नहीं है—मुजफ्फरपुर में केवल एक शुगर मिल है, हाजीपुर जिले में कोई मिल नहीं है और सीतामढ़ी जिले के रीधा में एक मिल है, इसके अलावा वहाँ कोई इण्डस्ट्री नहीं है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं—जब फिर से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का चुनाव बिहार में हो तो इन तीनों जिलों को भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में चुनवाने की व्यवस्था शीघ्र करें ।

सभापति जी, हमारे उत्तर बिहार की आबादी तीन करोड़ है । हमारे यहां शिक्षित युवकों की हालत बड़ी दयनीय है, बेचारे पढ़ लिख कर नौकरी के लिये पटना से लेकर

दिल्ली तक दौडते हैं । अपनी स्माल-स्केल इण्डस्ट्री लगाने के लिये यदि वे कोई दरख्वास्त देते है—पटना में, जमशेदपुर में या मुजफ्फरपुर में तो उन के सामने अनेकों कठिनाइयां आती हैं । एप्लीकेशन देने के बाद महीनों उन्हें आफिस में दौडना पडता है । बैंक से लोन की आवश्यकता होती है तो बैंकों में महीनों दौडना पडता है । मन्त्री जी—अभी भी आप के डिपार्टमेंट में इन शिक्षित बेरोजगारों से परसेन्टेज मांगी जाती है । आप के वे अधिकारी जो लाइसेंस देते हैं, इन इन्जीनियर्स और शिक्षित बेरोजगारों से 5 परसेंट और 10 परसेन्ट घूस मांगते हैं । मेरा आप से निवेदन है कि जहां भी आप के लाइसेंस देने के कार्यालय हैं आप वहां एक रजिस्टर रखें एक बहुत बडा साइन-बोर्ड रखें जिस में लिखा जाय कि आवेदक ने किस तारीख को आवेदन किया और कितने दिनों में उस को लाइसेंस दिया गया । इस तरह की लिस्ट हर कार्यालय में टंगनी चाहिये । बडे इण्डस्ट्री वाले तो लाइसेंस के लिये ऐसी घूस दे सकते हैं क्योंकि उन के पास ब्लैक-मनी होती है और इसी लिये उन को लाइसेंस जल्दी मिल जाता है । लेकिन हमारे ये करोडों शिक्षित बेरोजगार घूस का पैसा कहां से लायें, उन के अन्दर असन्तोष फैलता जा रहा है । जिस का नतीजा अभी हाल में आप ने देखा है । बिहार और गुजरात के नवयुवकों ने जो किया है उप मन्त्री जी, आप के यहां उत्तर प्रदेश में भी वही हालत होने वाली है । इस लिये यदि आप अपनी गद्दी को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मन्त्री के स्थान पर आसीन रहें तो आप को भ्रष्टाचार घूसखोरी बन्द करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी । यदि आप नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से गुजरात के नवयुवकों ने किया, बिहार के नवयुवकों ने किया, आप के यहां उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है । इस लिये इस स्थिति को रोकने के लिये देश के बेरोजगार युवकों को, जिन की संख्या पूरे भारत वर्ष में एक करोड है, नौकरी दिलाने के लिये, इण्डस्ट्री दिलाने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। तभी देश में शांति हो सकती है । मैं बडे मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके विभाग में खास करके हमारे उत्तरी भारतवर्ष के जो काम करने वाले हैं उनको कम तरजीह दी जाती है लेकिन दक्षिणी भारत के लोगों की एप्लीकेशन्स होती है या उनका किसी तरह का प्रमोशन होना है तो उनको वह जल्दी मिल जाता है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने कार्यालय में बैठें, सोचें और हर एक स्टेट के जो काम करते हैं उनकी एप्लीकेशन्स निकलवायें और देखें किस स्टेट के आदमी हैं, क्यों किसी का नीचा स्थान है और क्या साउथ इंडिया के जो रहने वाले हैं आपके यहां उनको पहले तरजीह दी जाती है । मेरा आपसे निवेदन है पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट के काम करने वाले हों वह सभी लोग बराबर हैं और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके लिए आपकी तरफ से एक तरह का इन्साफ होना चाहिए ।

अब मैं आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान बिहार की ओर भी दिलाना चाहता हूं । बिहार में, खास करके उत्तरी बिहार में सीकी का एक उद्योग है जिससे डलिया और बहुत सा दूसरा सामान बनता है । उत्तरी बिहार में सीकी एक पाधे से पैदा होती है । मेरा निवेदन है कि सीकी इडस्ट्री का आप अपने विभाग में ले लें तथा जो लाग डलिया व दूसरा सामान बनावें उनको बेचने की सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए । जो गरीब किसान गांवों में रहते हैं वे यदि डलिया या बर्तन वगैरह बनाकर लावें तो उसको खरीदने की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए ।

सभापति महोदय अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव श्रीमन्, बिहार में साबे एक घास होती है जिसमें रस्सी बनाई जाती है और रस्सी से घर बनता है, मेरा निवेदन है कि साबे से जो रस्सी बनती है उसको खरीदने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होनी चाहिए ताकि जो गरीब

[श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव]

किसान इस काम में लगे हुये हैं वे अपनी जीविका चला सकें । सीमेंट, पेपर का कारखाना सरकार की ओर से सीतामढ़ी में बनना चाहिए ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव : आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद । मुझे अभी बातें रखनी तो है जो घट रहा है इन दिक्कतों को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि क्या दिक्कतें हैं इसलिए यदि दो मिनट और दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती । खैर, जो समय आपने दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Mr. Chairman, I have heard the speech of the hon. Member who preceded me and I was sorry to hear what he had said about Shri Subramaniam. From whatever experience I have had of Shri Subramaniam for the last 25 years, I can say that he is very honest and straightforward and he is an out and out nationalist and also a realist. The way in which some allegations were levelled are all false and mischievous. Mr. Subramaniam cannot tolerate any injustice or make any difference between one man and another man.

I am very glad to see that Mr. Subramaniam has presented a veary good Report to this House. He has projected all the weaknesses and defects in his Report. He has not tried to conceal or hide anything. That shows his boldness with which he is going to tackle the difficult problems of the country.

As the time at my disposal is very limited, I would like to just make a few points. If we want to have an overall growth rate of 5.5 per cent in the country, every year, the industrial output should be not less than 9 to 10 per cent. Then alone, we can maintain 5.5 per cent growth rate every year. As present the population is increasing at the rate of 2.5 per cent and the consumer goods must be produced at the rate of 10 to 11 per cent. Unless and until that is done, it is not possible to keep up with the demand. The rural rich and so many other classes of people who have never seen the good before are now demanding these goods for their use. So, the production of consumer goods should go up by 10 to 11 per cent.

Andhra Pradesh was very backward in previous years. I am very happy to say that Mr. Subramaniam has laid the foundation of industrialisation in Andhra Pradesh in the field of heavy electricals and other things. It has now come up well. I am asking for some more factories in Andhra Pradesh not because that I am selfish but because that will add to the overall growth of the country. It is in that perspective that I am demanding some factories in Andhra Pradesh.

We want a cooperative jute factory at Salur in Srikakulam district. We want a newsprint project at Bhadrachallam. As you know, we are producing newsprint only to the time of 40,000 tonnes in this country and we are importing over 2 lakh tonnes from foreign countries. If that gap is to be reduced, this newsprint factory should be immediately established in Andhra Pradesh. I request the hon. Minister that immediately all necessary arrangements may be made so that we may not depend upon foreign countries.

Then, we want two fertiliser factories, one at Kothagadam and another at Vizag. That is very essential. In this area a lot of coal is available. We are now going in for coal-based fertiliser plants. I request the hon. Minister to set up these fertiliser factories in Andhra Pradesh very soon.

There is a proposal for a steel plant at Vizag. It is, of course, during his earlier time that it was contemplated. But it is at a stage where it was before. Immediate steps should be taken to start it.

There should be a nylon filament yarn plant in Rayalaseema area. This

is a very backward area. I hope, the hon. Minister will take suitable steps to do all these things.

Besides this, Andhra Pradesh has lot of raw material for cement. Already, three cement factories have been sanctioned. But the work has not been started. These cement factories have been sanctioned with a capacity of 4 lakh tonnes each at Yerrangutta, Tandur and Adilabad. These factories also should be started early. Our Chief Minister has sent detailed notes to the Central Government. He has given a promise that he would help in establishing these factories. The way our Chief Minister is moving in the matter shows that he is very dynamic and, I hope, all these factories will be started soon.

Recently, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Padma Shri awards have been awarded to eighty persons. But not a single industrialist has been awarded any of these awards. In the whole of India, when the cement factories were producing not even 80 to 90 per cent of their capacity, one factory in Andhra Pradesh has produced 130 per cent of its capacity.

I want to know whether the Minister is going to consider giving an award to them....

16 hours.

AN HON. MEMBER : Which factory ?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Keshav Ram Cement Factory.

It is not a question of individual. Whichever factory has exceeded the target and has produced 20 or 30 per cent more, must be given some encouragement.

Regarding monopolies and other things, I want to say, whether the monopolists are paying the wages to the labourers or not, whether they are paying the taxes or not, whether they are producing goods or not, these are the only things that are to be taken into consideration and not any other thing. If somebody is making money, after paying all taxes, so long as he makes money legally, it is allright; if there is any illegal thing, then those people can be tried under the law.

SHRI K. GOPAL (Karur) : Mr. Chairman, my hon. friend, Mr. Yadav, has spoken about South Indians; he had a grouse that the South Indians were being preferred everywhere. I will tell a story. When God created man in India, He had two tins of paint, one intelligence and the other beauty. He took the tin of beauty and started painting from Kashmir. By the time He went to Kanyakumari, He finished that. Then He started with the tin of intelligence. You will excuse me, Sir, for saying this. Before He reached Bihar, He had finished with that. That is the reason why the South Indians are intelligent and are preferred.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली (टिहरी-गढ़वाल) : सभापति जी, मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । इस संदर्भ में मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर खींचना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश के औद्योगिक विकास के समन्वित रूप से कार्यान्वियन की सब से बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए कि हमारे देश के जो प्राकृतिक साधन हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करते हुए हम जन शक्ति का किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं । इन तीनों में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक औद्योगिक विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते । चूंकि जन-शक्ति साधन और साध्य दोनों हैं इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 15, 20 साल के बाद हों जिन को रोजगार देना है वे चूंकि जन्म ले चुके हैं इसलिये 15, 20 साल बाद देश का औद्योगिक विकास किस प्रकार का होना चाहिये अपनी जन-शक्ति को ध्यान में रखते हुये उस का नियोजन करना चाहिये । हमें यदि जन-शक्ति का ठीक प्रकार से उपयोग कर सके तो जो

[श्री परिपूर्णनन्द पैन्यूली]

दो करोड बरोजगार लोग हैं वे हमारे देश पर बोझा न हो कर वरदान सिद्ध होंगे ।

एक हमारे छोटे छोटे उद्योगों को बडे कारखाने दारों की प्रतिस्पर्धा में उन्हें मुकाबला करना पडता है और दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं है किन्तु शासन की नीति ऐसी है कि उन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जिसके कारण वहां का विकास नहीं होता है । 1951 से 1970 तक औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार 3 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढा जिसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन 6 प्रतिशत की दर से बढा है । इस औद्योगिक विकास से मुट्ठी भर लोगों को जहां बहुत अधिक लाभ पहुंचा है वहां उस क्षेत्र की गरीब जनता को उतनी ही क्षति उठानी पडी है । यह भी खेद का विषय है कि 15, 20 सालों में हमारा अधिक जोर विकास की अपेक्षा राजनीति पर रहा है—चाहे कुर्सी की लडाई हो और चाहे हडताल और तालाबन्दी की बात रही हो । यह दुख की बात का विषय है आज भी हम दलबन्दी से बाहर निकल कर देश के विकास की दिशा में नहीं सोचते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां चूंकि पर्सपेक्टिव प्लानिंग का अभाव रहा है इसलिये क्षेत्रीय विषमता काफी बढी है और बढ रही है । इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का एक उपाय यह हो सकता है कि जो क्षेत्र अधिक विकसित हो चुके हैं, हमारे उद्योग मंत्री जी और प्लानिंग कमीशन को एक बात तय करनी चाहिये कि, वह अपनी ग्रौस इन्कम से कम से कम 1 प्रतिशत धन जो अपेक्षाकृत पिछडे हुए क्षेत्र हैं उन के विकास के लिये रखें । यदि ऐसा नहीं होगा तो जो पिछडे हुए क्षेत्र हैं उद्योग की दृष्टि से वे सारे देश पर भार बन कर रह जायेंगे और विकसित क्षेत्रों के विकास में भी रुकावट पैदा करेंगे ।

मैं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर 60 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं और खनिज सम्पदा भी है । किन्तु खेद का विषय है कि नाम मात्र को भी कोई उद्योग धंधे वहां पर नहीं हैं । मेरे पास यहां पर एक रिपोर्ट है :

Report of the Working Group on Forest Development and Utilisation —'UP Hill Areas'.

जिस में यह स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का दो तिहाई सारा रेजिन मैदान की फैक्ट्रियों में चला जाता है, विशेषकर बरेली में जो पेपर मिल है जिस में पूंजी पतियों के शेयर्स हैं उस फैक्टरी को सारा रेजिन चला जाता है, लगभग सारा कच्चा माल मैदान के कारखानों का चला जाता है । कैम्फर कत्था और प्लाई वुड आदि जितने भी उद्योग धंधे मैदानों में वन सम्पदा के बने हैं वे पहाडों से नीचे चले जाते हैं पहाडों में चूना है, जिम्मम है उस सब को वहां से दोहन कर मैदान में भेजा जाता है ठेकेदारों, बिचौलियों के माध्यम से और पहाडों का बुरी तरह से शोषण हो रहा है । अभी देहरादून के पास विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है जो चूना पत्थर के मालिकों ने वहां पर पैदा कर दी है, वहां पीने के पानी के स्रोत सूख गए हैं, गांव उजड गये हैं और लोगों के खाने के साधन समाप्त हो गये हैं ।

अभी उपमंत्री जी ने कहा कि पिछडे हुए क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार कुछ करना चाहती है, चाहे उत्तर प्रदेश के पिछडे हुए क्षेत्र हों या जन-जाति के क्षेत्र हों । किन्तु दुर्भाग्य है कि सारी प्राकृतिक सम्पदा दूसरे लोगों के विकास में जाती है और वहां के आदमी पहले की तरह पिछडे हुए हैं और गरीब हैं । पहाडी इलाकों में काफी ऊन होती है किन्तु उस के विकास के लिये हमारे पास कोई समन्वित योजना नहीं है । मैं इस संबंध में उद्योग मंत्री जी और उन के उपमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे कागज की कमी हो, सीमेंट की कमी हो, वह चाहे हड़तालों के कारण या बिजली के अभाव के कारण हो, आवश्यकता इस बात की है कि

एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से तालमेल हो । तालमेल के अभाव में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते । हम में आपस में तालमेल होना चाहिये । पहाड़ों में ऊन है, उस के विकास की योजना है । किन्तु उत्तर-काशी की ऊन जो विशेषज्ञों के अनुसार भारत में सब से बढ़िया होती है, वह ऊन पानीपत की फैक्टरीज में चली जाती है और वहां के लोगों को मैदानों से घटिया किस्म की ऊन खरीदकर तसल्ली करनी होती है । पहाड़ों में लोग भेड़ पालन करते हैं, लेकिन उन के लिये चरागाह की व्यवस्था नहीं है । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भेड़ों के चरान चुगान के लिये पास्चर लैंड की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है । वहां जो जमीन अब तक थी भी वह भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है । पहाड़ों का जो कच्चा माल है वह चाहे सहारनपुर का प्राइवेट सेक्टर का कागज का कारखाना हो या किसी दूसरी जगह के कारखानें हों उन सब को चला जाता है । इस प्रकार से पहाड़ों का शोषण पूर्ववत जारी है । चाहे पहाड़ी इलाका हो या जन जाति क्षेत्र हो या पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो, वहां जो प्राकृतिक सम्पदा है उसका वहीं समुचित उपयोग करके वहां के लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिये । वहां जो जन शक्ति है उसका आपको इस काम में उपयोग करना चाहिये ।

इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गढ़वाल और कुमायूं से इस बार विधान सभा की सीटें, जो 21 हुआ करती थीं वे घट कर 19 ही रह गई हैं । यह इसलिए नहीं हुआ है कि फैमिली प्लानिंग का असर वहां हुआ है, बल्कि इसलिये हुआ है कि जिन दिनों में सैंसस होता है पहाड़ का आदमी रोटी रोजी की तलाश में, बरतन मलने, घरेलू काम करने के लिए मैदान में आ जाता है और ऐसा करने के लिये उनको मजबूर होना पड़ता है । रोजी-रोटी की आवश्यकता उन्हें ऐसा करने के लिए उनको मजबूर करती है । इस वास्ते उनकी गिनती नहीं हो पाई । यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वहां के आदमी को आप किस प्रकार से वहीं जिन्दा रखना चाहते हैं ? जिस आदमी ने हाई स्कूल पास किया उसके वास्ते पहाड़ पर कोई साधन नहीं होता है । शिक्षा की व्यवस्था आप इस प्रकार की करें कि वहां के साधनों का वहीं रह कर वह किसी प्रकार से उपयोग कर सके और अपने पैरों पर वहीं खड़ा हो सके, पहाड़ों पर रह कर वह कैसे जिन्दा रह सकता है ?

पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में आप से हम बड़ी बड़ी बातें जब सुनते हैं तो वे बहुत अच्छी लगती हैं और मीठी भी । लेकिन जब वस्तुस्थिति को हम देखते हैं तो बड़ी मायूसी होती है । इस सम्बन्ध में नैशनल इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं कि वह भी कर दिया जाना चाहिये । 1956 के नैशनल इंडस्ट्रियल पलिसी रेजोल्यूशन में कहा गया था :

> "Only by securing a balanced and coordinated development of the industrial and agricultural economy in each region can the entire country attain higher standard of living."

यह जो पालिसी निर्धारित हुई थी इसका यदि ठीक तरह से पालन हो जाए तो कम से कम पिछड़े हुए इलाकों का सुधार हो जाता है वहां बसे हुए गांवों के लोगों का विकास हो सकता है ।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय और फाइनेंशल इंस्टीट्यूशनज द्वारा बैकवर्ड एरियाज में सहायता की घोषणा की गई थी । किस प्रकार की सहायता की व्यवस्था है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, वहां के इलाके के लोगों को नहीं होती है, और यहां तक कि जो वहां जिला उद्योग अधिकारी काम करता है उस तक को नहीं होती है और अगर होती भी है तो वह किसी को बताता नहीं है । जो इंसेंटिव आप देना चाहते हैं उसकी जानकारी लोगों को आपको करानी चाहिये । जिला स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक आपको सैमिनार्ज आयोजित करने चाहियें । देहरादून उत्तर प्रदेश का एक एजुकेटिड इलाका है । वहां काफी छोटे बड़े उद्योगपति हैं । वे लोग शटल काक

[श्री परिपूर्णनन्द पैन्यूली]

की तरह भागते फिरते है उद्योग भवन से शास्त्री भवन और वहा से मिनिस्ट्री आदि मे। लेकिन जो चीज उनको चाहिये वह मिलती नही है। कोयला नही है या रा मैटीरियल नही है तो वह परेशान होता है। इन सब मे तालमेल बिठाने के लिये जिला स्तर पर आप कोआर्डिनेशन मशीनरी का निर्माण करे या इस तरह का वहा सैट आप कायम करे ताकि उनके समय, पैसा और शक्ति का दुरुपयोग न हो। आज होता यह है कि कोई एक योजना बनाता है इडस्ट्री लगाने की तो जब तक वह उनको कार्यान्वित करने की स्थिति मे आता है दो साल के बाद तब उसको पता चलता है कि दो लाख जो लागत आनी थी वह अब चार लाख हो गई है।

पिछडे हुये इलाको का विकास इसलिए भी नही हो पाता है कि वहा इनफ्रा स्ट्रक्चर का अभाव रहता है। इसको उप मत्री जी ने स्वीकार भी किया है। मै पूछना चाहता हू कि कब आप वहा के लिए इनफ्रा स्ट्रक्चर तैयार करेगे? क्या दिल्ली के एयरकडीशन्ड कमरो में बैठ कर या लखनऊ कलकत्ता आदि—राजधानियो मे बैठ कर विकास की स्कीमे बनाएंगे? मै कहना चाहता हू कि स्कीम्ज को कार्यान्वित करने के लिए आपको आन दी स्पाट जा कर देखना चाहिए। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट भी सही होनी चाहिए। सब से ज्यादा जरूरत बात यह है कि जो लोग उनका अध्ययन करने है उनका भी रिओरिएटेशन होना चाहिए। उनको अच्छी तरह जा कर इस बात को देखना चाहिए कि किस क्षेत्र की क्या आवश्यकताए है, वहा पुश्तैनी रूप मे क्या-क्या कारोबार हो रहे है। पुश्तैनी उद्योग धंधे तो सब जगह समाप्त हो रहे है। जो नये उद्योग धंधे वहा कायम आप करना चाहते है उनके लिए वहा पर लोगो का एप्टीच्यूड नही है और जो उद्योग आप उन्हें अपनाने को कहते हैं। लोग उनको करना नही चाहते हैं। इन सब को आप को देखना चाहिए। अब इन सब बातो को आप देखते नहीं है तो बाद में आप कह देते है वहा के लोग कुछ करते नहीं हैं।

मैं चाहता हूं कि पहाडी इलाकों मे, पिछडे इलाको मे रिसोर्स बेस्ट इंडस्ट्रीज और एम्प्लायमेंट ओरिएंटिड इंडस्ट्रीज की तरफ आप अधिक ध्यान दें। ऐसा आपने किया तभी उन इलाको का विकास होगा।

खादी ग्रामोद्योग का यहा बहुत जिक्र हुआ है। मेरा निवेदन है कि वह एक तरह का ह्वाइट एलीफैंट है। हमारे इलाके में उसका रोल नगण्य रहा है। मै एक छोटी सी मिसाल देता हू। हमारे यहा पर रेडीमेड कपडे बिकते है। वे मैदानो से अहमदाबाद आदि से बन कर आते और बिकते है। क्यो नही खादी कमीशन वही लोगो मे उनकी कोआपरेटिवज बनवा करके उन से रेडीमेड कपडे बनवाता है और वहां लोगो को अपने पैरो पर खडा करने मे मदद देता है। ईस्ट इडिया कपनी की तरह खादी कमीशन और खादी भण्डार पहाडो मे फैलता जा रहा है। खादी कमीशन को चाहिये कि शहद, लकडी, जडी बूटी आदि पर आधारित उद्योग धधो की वहा स्थापना करने के सिलसिले मे कदम उठाए। ये लोग भारी भरकम तनख्वाहे लेते है और एलाउंस भी इनको बहुत मिलते है। लेकिन उधर ये ध्यान ही नही देते है।

रेशम उद्योग का जहा तक ताल्लुक है मै आपकी तारीफ करता हू और बधाई भी देता हू कि आपने उसे उचित महत्व दिया है। आपने हिन्दुस्तान के टस्सर के कोकून और चीन के टस्सर के कोकून से, उनके सम्मिश्रण मे क्रास ब्रीड तैयार की है। पता नही भारत का नर है या चीन का मादा है। जो नया कोकून निकला है कहते है कि यह बहुत बढ़िया है, इसका रेशम बढ़ीया होता है और ससार में उसकी बिक्री करके हमें फारेन एक्सचेंज, प्राप्त हो सकती है। रेशम उद्योग का काम ऐसा है कि लोगों को उससे काफी रोजगार मिल सकता है। मेरी प्रार्थना है कि पर्वतीय इलाको में आप खास तौर से इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें।

अपनी कंस्टिट्युएंसी के बारे में एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। देहरादून में कालसी के पास सिमेंट के कारखाने की बात तीसरी योजना में कही गई थी। मुझे खशी है कि हिमाचल में पहले से एक सिमेंट का कारखाना था और वहां एक और दे दिया गया है। पिछड़े हुए इलाकों के साधन जुटाने और प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग वहीं करने और कारखाने बनाने की आपने योजना की है। मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है कि आपने तीसरी योजना में सीमेंट के कारखाने को कालसी में नहीं लगया, चौथी में नहीं लगाया, अब पांचवीं में तो लगाएं। अगर सिमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया इसको नहीं कर सकती है तो कम के कम उत्तर प्रदेश की सिमेंट कारपोरेशन को ही आप लैटर आफ इन्टेंट दे दें ताकि वहां रोजगार के साधन बढ़ें और उस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो।

SHRI JAGANNATH RAO (Chatrapur) : Mr Chairman, Sir, this ministry is in charge of the vital sector of the economy. This Ministry is in charge of an orderly development of industrialisation of this country. But, it is faced with two basic difficulties—one difficulty is the growth of monopoly houses in the country with the lopsided development and the other difficulty that it is faced with is the shortages. Unless these difficulties are solved, there cannot be any orderly development or planning of industrial development in the country.

The growth of monopoly is of historical origin because, business houses were in existence since a long time, by the time we gained Independence. There were getting licences because they had the know-how, resources and everything. Like a monster they grew and there is concentration of economic powers in their hands. We have passed the M.R.T.P. Act. But still, we are faced with the difficulties. We want more production. So, the only answer for this should be the rapid expansion of the public sector. But, then, the public sector takes time to come up. We want more production with certain restrictions being placed. What kind of restrictions can there be? You will see that under Sec. 27 of the M.R.T.P. Act, there is a provision according to which, the Central Government is empowered to direct the larger houses to shed a part of their shareholdings in industries so that their shareholdings would not be diluted. As far as public sector is concerned, I say that it should be allowed to expand in a big way, but the public sector is not doing that? In spite of our Industrial Policy Resolution 1956 the public sector is slow in expanding itself. And to-day we are faced with the difficulty of financial resources. Exerywhere we find that there are shortages—shortages of power, coal, cement, steel and everything. While I was in school, I read about the stone age—people using stone implements and later came Iron Age. When we come to Parliament, we learn about shortages of raw materials, shortage of finished products and so on and so forth. This is a world of shortages. That is all I can say. Shortage is worldwide phenomenon—not confined to this country alone.

I really wonder how the Ministry of Industrial Development will develop the industrialisation of the country.

Be that as it may, attempts are being made to increase the industrial development of the country. The Report has not given us the details as to how many medium industries have come up during the year under review and how many licences have been given to the larger houses. That would give us an idea whether the medium sector is coming up gradually which can be an answer to the monopoly houses in course of time. We would like to have the details in the Report on this aspect at least next year.

Sir, the Ministry is often criticised that the backward areas are not industrially developed. I do not see any reason why the Central Government or the Industrial Development Ministry be accused of industries not coming up in backward areas. The primary duty of

[Shri Jagannath Rao]

the State Government is to see that the areas which have been identified as gackward districts some infrastructure is prepared by them. If the infra-structure is there then it is open to the Central Government to insist on a person who applies for a licence to go to a backward district. In the absence of the infra-structure I do not see any reason why this Ministry should be blamed. Everyday we find the Minister is asked to explain as to why industries have not come up in the backward areas. The State Governments have to prepare the infra-structure. It is their responsibility. Then only we can accuse the Ministry.

The small scale sector is a redeeming feature of our economy. They are doing a good job. About 177 items have been reserved for the small scale sector. I had been dealing with this subject some years ago and I am very happy to see the progress of the small scale sector. But then the industrial estates were started in 1958 when Shri Manubhai Shah was incharge of the Industries Ministry. The industrial estates have come up in the country but all the industrial estates are in the urban areas. No industrial estate has been started in the semi-urban or rural areas. If these industrial estates are started in these areas they will serve two purposes. Firstly it will give employment potential to the man in the village. Secondly it would prevent people migrating to the urban areas and the rural economy will also be boosted. Therefore, the Ministry should take care to see that in further when industrial estates are set-up they are established in the rural areas so that it will help rural unemployment problem and also give strength to the rural economy.

Sir, it is very essential that every industry—whether a large house or a medium house—school be compelled to have a research and development wing. They should carry on research on their own so that they can improve on the processes of manufacturing these goods. USA is the first-rate power today not because of the military strength or the nuclear power but because of its advance in the field of science and technology. I am glad to know that the Government has entered into several agreements with the western and East European countries to get the technical know-how so that in course of time we should develop out own technology and utilise the same in manufacturing industrial goods. This is highly necessary because this will minimise losses and will also ensure the necessary quality control.

Finally, I would say a word about the private sector also We have no control the private sector as such, except in the matter of giving them licenecs. The private sector cannot go scot-free. Every day we have questions here about the public sector and the performance of private undertakings. but we connot put questions about the performance of private undertakings. This Ministry is implementing the Industrial policy Resolution which deals with both the sectors, and therefore, it should have a control over the performance of the private sector, and the private sector also should be made answerable to the Ministry not only regarding their performance but also about utilisation of capacity, about quality control, productivity and so many other things so that there will be proper growth. When the public sector is subject to so much of scrutiny by Parliament, the private sector also should be brought under the scrutiny of Parliament.

With these words, I support the Demands.

MR. CHAIRMAN : Three more speakers are there on the list before me, Shri Giridhar Gomango, Shri Y. P. Mandal and Shri B. N. Bhargava. So, I am afraid the hon. Minister will have to start his reply at 4.40 p.m. or so. These three speakers may kindly confine themeselves strictly to the time-Limit of five minutes each.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput) : I rise to support the Demands for Grants under the control of

the Ministry of Industrial Development as also the other Demands placed before the House. Since the time at my disposal is short, I shall make only three or four points.

Big industries are developing in the country and they contribute to the growth of economy. But when they are established in the forest areas and the tribal belts, where our trial people are living, they have a bad impact on them. The recommondation made by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission is that big industries should be established in the tribal belts, and if they are established, they should give proper chance to the tribals to work in the factories and to live in the factory areas. I would like to know from the hon. Minister what steps have been taken to give all these facilities to the tribals in this regard.

Just now, Shri Jagannath Rao has pointed out that the ministry has no control over the private sector industries which are established in the various places. These private sector units also are not looking to the welfare of the tribals and the welfare of the society in general. You know, Sir, that water pollution and air pollution have been increasing in the country posing a health hazard to the people. I woould request the hon. Minister that he should issue instructions to the private industries to look into this matter and take steps to prevent water and air pollution.

The Fifth Five Year Plan will be starting from the coming financial year. I received a letter from the Planning Minister that there would be sectoral allocation from the various Ministries. There is a proposal for sub-plan for tribal areas. I would like to know from the hon. Minister how the sectoral allocation from the Ministry of Industrial Development will flow into the tribal areas? My point is that let industries be established in the tribal areas not big industries but only small-scale industries. If big industries are established in tribal areas, then the tribal people will be deprived of the opportunity of getting employment since they have no technical skill or knowledge. So smaller industries should be started in the tribal belt, especially in the forest areas. There should be forest-based industries and agro-industries and other industries of a small nature by which my people will be benefited as a consequence of industrial development.

In conclusion, I would refer to some industries which are coming up in my constiuency, namely the calcium carbide plant in the Koraput district, the cement factory at Sunki, and the paper plant in Jeypore and the spinning mill at Rayagada. These four factories should come up in the Fifth Plan so that the employment opportunities to the people of the district will be higher than before.

I would like to know the allocation made in the Fifth Plan by the Ministry of Industrial Development to the tribal areas, and whether the State Government have submitted any report to the Ministry regarding the development of the tribal areas or not. I hope the hon. Minister will look into the matter and do the needful.

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की डिमांड्स नम्बर 157-158 तथा माइंस और टैक्नोलाजी विभाग की डिमांड्स नम्बर 100 और 101 की पूरी पूरी ताईद करता हूं । इस के साथ ही मैं मिनिस्ट्री को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने काफी नये इंसेंटिव्ज रूरल और बैकवर्ड एरियाज के लिए दिए हैं उन्होंने बहुत सुन्दर और इल्यूमिनेटिंग लिटरेचर बनाया है । मा० सदस्य डा० एल० एन० पांडेय साहब (जनसंघ) और मा० सदस्या पटेल साहब भी इस तरफ देखेंगे तो उन्हें उस से रोशनी मिलेगी । उन के दिल दिमाग में तो यह रहता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उन के दिमाग में तो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन रहता है । हमें ऐसे विद्वान लोगों से उस शब्द की आशा

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

नहीं थी जब कि वह देश में इतनी चीजें होते हुए देख रहे हैं ।

श्री के० एल० नन्जप्पा साहब जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के उन्होंने अपने फोरवर्ड में कहा है :

"During this period of 1½ decades, we have made all these things but the problem, though formidable, has been constantly engaging the attention of Government".

5 लाख गाव हैं । गांवों मे एनर्जी की कमी है और जब यह सब बातें उन्होंने कही कि फारमिडेबल है उस के बाद दूसरी पंक्ति जब उन्होंने शुरू की तो कहा :

"Industrialisation of backward areas in a country like India is admittedly a difficult task".

मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि यह बड़ा टफ टास्क है 5 लाख गांवों को ठीक करना ।

सभापति महोदय, आप ने इस संबध मे बहुत काम किया, उस के लिए सारा देश आप का आभार मानता है और आप ने जो मेमोरेंडम दिया प्राइम मिनिस्टर को मुझे इजाजत दीजिए मैं उस की कापी (प्रतिलिपि) सदन के मेज पर रखूं, उस के साथ साथ मै एक दो पैराग्राफ उस मे से पढ़ना चाहता हूं । डा० कैलास (बम्बई क्षेत्र) घबड़ाएगे नहीं, आदरणीय सदस्य धामंकर जी (महाराष्ट्र) घबड़ाएंगे नही, दो एक बातें उस में ऐसी होगी जो उन को अच्छी न लगें । पार्लियामेंट के मेम्बर्स ने कहा :

"We must lodge our strong protest against the allotment of Rs. 2,000 crores for developing the twin city of Bombay".

आप बम्बई को बढ़ाइए, कलकत्ते को बढ़ाइए, मद्रास को बढ़ाइए, मगर आखिर इन गांवों का क्या होगा? पांच लाख गांवों का क्या होगा? उन के लिए तो आप ने कहा कि हम कुछ न कुछ करेंगे ।

I shall read another portion from the memorandum submitted by MPs from all the States to the Prime Minister and shall request the Chairman to allow me to lay the document on the Table.

MR. CHAIRMAN : You may read the relevant portion, but whether it can be laid on the Table or not will have to be decided only according to the rules. I am not deciding it now.

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL : We have done this so many times with the special permission of the Chair. This is not the first time it is being asked.

MR. CHAIRMAN : Your time is short. Please go on.

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL : "It is of the utmost importance that funds be provided for the backward areas. We demand at least Rs. 10,000 crores to be allotted from plan funds..."

हमारे सुब्रह्मण्यम् साहब बड़े अनुभवी हैं और बहुत दिनों तक मद्रास जैसे बड़े राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं । ये जानते है क्या करना है । मै ने इन्हें केवल इशारा ही दे दिया ।

उस के बाद आप ने आल इंडिया बैकवर्ड कान्फरेंस किया था । मैं गोमांगो साहब से कहना चाहता हूं कि उस में हम लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए भी 16 करोड़ रुपये की मांग की थी और आप मुझे अनुमति दें तो मैं यह दोनों बहुमूल्य पत्र जो पचासी एफ० पीज के हस्ताक्षर से दिए गए हैं सदन की मेज पर रखूं*

ऐसा पहले हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है जो मैं करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : आप दें दीजिए । अध्यक्ष महोदय उस का निर्णय करेंगे ।

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the documents were not treated as laid on the Table.

श्री यमुना प्रसाद मंडल : मैं आप का बड़ा अनुग्रह मानता हूं और कृतज्ञ हूं ।

हमारे नगेन्द्र भाई ने कहा था कि उन का जिला छोड़ दिया गया है । मैं उन से कहूंगा कि वह अपेंडिक्स नम्बर 2 में देखें, उन का जिला है मगर वह तीन हिस्से में बंट गया है मुज़फ्फरपुर, इसलिए वैशाली का तो आएगा ही । मैं जैसा देखता हूं लिस्ट आफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में तो उस में दिया है :

"List of backward districts eligible for concessional finance from the financial institutions as on 31-8-1973".

अब मैं नार्थ बिहार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । यहां करीब तीन करोड़ लोग रहते हैं । आज सैकड़ों मील चले जाइए सिवाय एकाध शुगर मिल के कुछ नहीं मिलेगा । गरीबी बेहद है । वे विरोधी दल के लोग लूटने का काम कराते हैं । जो भी धान का पौधा होता है मा० रामावतार की शास्त्री जी की पार्टी के लोग उस को लूटने की कोशिश करते हैं । अब मैंने सुना है कि भूसा से 15 परसेंट एडिवल आयल निकाला जायगा । उस के संबंध में कुछ लिटरेचर दें, कुछ करें ।

अब मैं बम्बई की तरफ आता हूं । वहां खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का हेड आफिस है । मैं सारे हाउस की इजाजत से कहना चाहता हूं, जब 20 हजार गोबर गैस प्लान्ट्स आप देना चाहते हैं, 5 लाख गांवों को सुधारने का आप न व्रत लिया है तो बम्बई में भी आफिस रखिए, बंगलौर में भी रखिए, हरयाना (चंडीगढ़) में भी रखिये बिहार में भी रखिए जहां लाइव-स्टाक (गोबर देने वाले मवेशी) ज्यादा हैं । मगर सारी चीज दखिए । मैंने एक चिट्ठी लिखी थी । उस चिट्ठी के जवाब में उन्होंने लिखा कि आप बम्बई भेजिए, बम्बई वाले पटना भेजेंगे, पटना वाले मधुवनी भजेंगे ।

From pillar to post. What is the sad plight of the poor kisan ?

गोबर का मतलब है गोपाल

Everyone is a *gopal* and we have now come back to this.

गांधी जी की वाणी सत्य हुई ।

Back to villages.

एक छोटी सी बात जो मैं सुब्रमण्यम् साहब से कहा चुका हूं, अनौपचारिक रूप से, उसे फिर यहां सदन में दोहराना चाहता हूं । समस्तीपुर पेपर पल्प के बारे में पृष्ठ 53 पर लिखा है ––शार्टफाल इन पेपर प्रोडक्शन । यह बात वह मानतें हैं । एक छोटी सी मिल समस्तीपुर में है हमारें यहां 'ठाकुर पेपर मिल है । उस की सच्ची तस्वीर मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं । आई० एफ० सी० के चेयरमैन ने भी माना है कि 6-7 साल से वह बन्द है और कुछ हो नहीं रहा है । सारे बिहार के हिस्से में एक पेपर मिल है । मैं एक लाइन उस के बारे में बढ़ना चाहता हूं :

Page 53—Shortfall in paper production मुख्य मंत्री (श्री गफूर) " ...Hence, the whole matter is to be finalised in a day or two, and the IFC and BFC may also be informed." This is on the 10th November last, and today is March 27, 1974. Nothing has been done and I request the Minister to look into it. I am happy that I have brought this to the notice of one of the seniormost Ministers who had also been the Planning Minister, Mines and Mineral Minister, Food Minister, etc.

श्री बशेश्वर नाथ भार्गव (अजमेर) : सभापति महोदय, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं । देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । मैं विशेष तौर पर औद्योगिक विकास मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में जो क्षेत्रीय असन्तुलन है उस को यह मंत्रालय ठीक प्रकार के समन्वित कार्यक्रम के द्वारा प्रभावकारी ढंग से दूर कर सकता है । उन का ध्यान मैं इन ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यहां पर

सदन में बहुत से लोग कहते है कि राजस्थान के पूजीपति देश के भिन्न भिन्न दूर-दूर के भागो मे जा कर उद्योग स्थापित करते हैं। मगर क्या कभी यह ध्यान गया कि राजस्थान मे उस की पुरानी ऐतिहासिक परम्पराओ के कारण तथा अन्य कारणो से, कोई इन्फा-स्ट्रक्चर उपलब्ध नही था। इसी लिये वे सब पूजीपति देश के दूसरे हिस्सो मे जाते रहे और राजस्थान के अन्दर कोई उद्योग स्थापित नही कर पाये। वहा के रजवाडो का एक पुराना इतिहास है, उन राजे-महाराजाओ ने केवल अपने विलास की सामग्री के साधन वहा पर उपलब्ध किये लेकिन गरीबो के लिये किसी प्रकार की कोई भूमिका अदा करने की कोशिश नही की।

दूसरी ओर वहा प्रकृति का प्रकोप तो आप जानते ही है। एक साल के बाद दूसरे साल वहा भयकर अकाल पडता है। ऐसी हालत मे राजस्थान की जनता किधर देखे—"राम भी नाराज और राजा भी नाराज।" मै बडी नम्रता के साथ, परन्तु दृढता से आप से निवेदन करना चाहता हू कि राजस्थान की जो समस्याए है, खास कर पिछडे इलाको की समस्याओ पर विशेष ध्यान दे। आप ने कुछ नार्म्स के आधार पर कुछ इलाको को पिछडा इलाका घोषित किया है। आप ने बताया है कि आप के मत्रालय को पिछडा इलाका घोषित करने का अधिकार नही है। राज्य सरकार की सिफारिश पर प्लानिग कमीशन उन को पिछडा इलाका घोषित करती है। मै आप से निवेदन करना चाहता हू कि जहा तक अजमेर का सम्बन्ध है या तो राज्य सरकार मे कोई गल्ती हुई है या आप के यहा निर्णय लेने मे कोई गल्ती हुई है। अजमेर ऐसा जिला है, जहा हर एक साल के बाद दूसरे साल अकाल पडता है। यह बात जरूर है कि अग्रेजो के शासन में 1947 से पहले चूकि वहा मजदूर काफी सख्या मे उपलब्ध थे, अग्रेजो ने वहा कुछ साधन पैदा किये, जिस से उस समय कुछ कारखाने लग गये, लेकिन यदि आज आप वहा की प्रति व्यक्ति औसत आय ले तो आप पायेंगे कि वहा की औसत आय बहुत कम है, इस लिये कि वहा छोटी छोटी जोते है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा निर्णय करते समय उस स्थान की औसत आय की क्राइटेरिया मान कर चलना चाहिये और उसी के आधार पर पिछडे क्षेत्रो की घोषणा होनी चाहिये। वरना इस से आगे बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योकि ऐसे क्षेत्रो मे जहा कोई दूसरी पोटेन्यिेलिटी नही है, इस प्रकार डिस्त्रिमिनेशन होगा तो उस से विषमता की स्थिति पैदा होगी और उस के बहुत गम्भीर परिणाम होगे।

अब मै कुछ अन्य चीजो की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हू —हमारे यहा विजयनगर मे एक लाइसेस मसौदा सिन्थटिक्स को दिया गया था लेकिन बाद मे उस को बदल कर वहा से 8 मील की दूरी पर लगाने की स्वीकृति दी गई। मैने इस सम्बन्ध मे मत्री महोदय को लिखा। उन्होने जवाब दिया कि राज्य सरकार की सिफारिश पर उस को 8 मील की दूरी पर बदल दिया गया। इस का कारण क्या था-नया स्थान बैक-वर्ड डिस्ट्रिक्ट मे है, जहा आप की तरफ से बहुत सारी सुविधाए उपलब्ध होती है। जिस वक्त शुरू मे उन्होने लाइसेस प्राप्त किया—उन को मालूम था कि वहा क्या क्या सुविधाये उपलब्ध है। लेकिन जब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की घोषणा हुई तो उन्होने अनेको कारण बता कर उस लाइसेस को बैक-वार्ड एरिया मे बदलवा लिया, जिस से सरकार के 5-7 लाख रुपये का चूर्ण हो गया। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करे—जब पहले राज्य सरकार की सिफारिश पर उन को लाइसेंस दिया गया, उस समय वहा पानी भी उपलब्ध था और दूसरे साधन भी उपलब्ध थे। उन्होने बदलने के लिये जितने रीजन्ज दिये, उन के कोई मायने नही हैं—केवल बैकवर्ड एरिया का लाभ उठाने के लिये उन्होने ऐसा किया। —ऐसी चीजो की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये।

जहा मजदूर काफी होते है, बेकारी ज्यादा होती है, सरकार वहां इंडस्ट्रीयल एस्टेट

बनाती है । लेकिन मै निवेदन कर---ब्यावर के अन्दर वहा के लोगो ने अपनी प्रेरणा से "इन्दिरा गाधी रूरल इडस्ट्रीयल एस्टेट" बनाई । वहा राज्य सरकार के और दूसरे अधिकारी जाते हैं और उन के प्रयत्नो की बहुत सराहना की है, लेकिन उन को कोई सहायता या सहयोग नही मिलता है । अपने ही आधार पर वह चल रहा है । मत्री जी ने कहा कि हम लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । लेकिन मै निवेदन करू कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन को सब से पहले तो सहायता प्राप्त करने मे ही बहुत कठिनाई होती है, उस के बाद न सिमेन्ट है और न दूसरी चीजे हैं । जब तक कोई पैकेज डील नही होगा, वे फ्रस्ट्रेट होंगे, उन को ब्लैकमार्केट की कठिनाइया से गुजरना होगा और उस के बाद जब उन का उद्योग स्थापित होगा तो आप स्वय समझ सकते है कि उन के अन्दर किस प्रकार का करैक्टर होगा ।

आज कई ऐसे उद्योग है जिन को रा-मैटीरियल नही मिल रहा है । वे ऐसे उद्योगो से रा-मैटीरियल ब्लैक मे खरीद कर अपना काम चलाते हैं जिन का कोई उद्योग ही नही है । आप थोडा इस की गहराई मे जाइये । अगर आप के पास कोई खबर भेजते है तो आप लिखते है कि इस को राज्य सरकार देखेगी । मै आप से निवेदन करना चाहता हू कि जब मै वहा जाता हू तो लोग मुझ से कहते है कि हम को रा-मैटीरियल नही मिल रहा है, लेकिन जो उद्योग स्थापित नही है उन से रा-मैटीरियल खरीद कर अपना काम चलाते हैं---आप उस समस्या पर गम्भीरता से विचार कीजिये देखिये कि उन की क्या सहायता हो सकती है ।

अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर मे किशनगढ गाटा-बादला उद्योग था जो 1963 मे स्थापित हुआ था । छोटी-मोटी, टूटी-फूटी मशीनें ला कर उन्होने उस को स्थापित किया और रा-मैटीरियल प्राप्त कर लिया । 1971 में उन को इम्पोर्ट लाइसेस भी मिल गया, यद्यपि वे उस को अवेल नही कर सके । आप इस की गहराई में जाइये---यह सब क्या हो रहा है । जो एन्टरप्रैन्यार सरकारी दफतरो मे चक्कर लगा कर, भेट-पूजा कर के लाइसेस और रा-मैटीरियल प्राप्त करे, वह अपने उद्योग को अच्छी तरह से न ही चला सकता, उद्योग को चलाने के लिये तो उसे अपना पूरा समय उद्योग मे लगाना होगा । इस बात की गहराई मे जाने की जरूरत है ।

आज सीमेट की हमारे यहा इतनी कमी है । 1966 मे घोषणा की गई कि ब्यावर के आस-पास अच्छे किस्म का चूना पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है---इस काम के लिये एक लाइसेस साहू-जैन को दिया गया, लेकिन मोनोपली हाउस की वजह से उन को लाइसेन्स प्राप्त करने मे विलम्ब हुआ । उस के बाद मै निरन्तर आप को लिखता रहा हू, कभी फाइनेन्स की दिक्कत होती है, कभी दूसरी चीजो की दिक्कत होती है । आप ने सीमेट कारपोरेशन की स्थापना की है ---जब वहा चूने का बहुत अच्छे किस्म का पत्थर उपलब्ध है तो वहा पर यह उद्योग क्यो स्थापित नही हो रहा है । यदि निश्चित अवधि के अन्दर साहू-जैन अपना उद्योग वहा स्थापित नही करते है तो सीमेन्ट कारपोरेशन उस उद्योग को वहा स्थापित करे, परन्तु इस काम मे विलम्ब नही होना चाहिये ।

फौरन-कोलाबारेशन के सम्बन्ध मे सरकार की एक निश्चित नीति है । फौरन-कोलाबोरेशन उसी हालत मे एलाऊ किया जाता है जब कि देश मे उस प्रकार के तकनीकी ज्ञान की कमी हो या वह ज्ञान न हो । मै आप के ध्यान मे यह बात लाना चाहता हू---वास्तव मे यह नीति बहुत अच्छी है, लेकिन क्रियान्विति मे स्वार्थ के कारण उस नीति के पालन मे हस्ताक्षेप होता है तथा अनेको प्रकार की विषमताये पैदा हो जाती है । हमारे यहा अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम कुचील मे एक "माइक्रोनिक्स इण्डस्ट्रीज" है जो अपने यहा इलैक्ट्रोनिक्स

[श्री वशेश्वर नाथ भार्गव]

के सामान का उत्पादन करते हैं। 1973 दिसम्बर में जो यहां औद्योगिक प्रदर्शनी हुई थी उस में उन्होंने अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उस के बावजूद भी आप ने बम्बई की एक फर्म "नलिन पी० सेठ, 5, हम्माम स्ट्रीट, बम्बई-1" को अमरीका की फर्म कैम्ब्रिज थर्मानिक कारपोरेशन, 445, कान्कर्ड एवन्यू, यू० एस० ए० के साथ कोलाबोरेशन एलाऊ किया। यह फर्म भी वही चीजें बनायेगी ऐसा कालाबोरेशन आप की नीति के विपरीत है। मुझे विश्वास है कि इन चीजों को आप गहराई मे जा कर देखने और औद्योगिक क्षेत्र की सहायता करेंगे।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मै आप का आभारी हू, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): Sir, admittedly the country is passing through a very difficult period. The economy is under great strain. I am sure hon. members are aware that Government is not taking a complacent view of the situation. The *Economic Survey* presented to this House portrays the real situation in the economy and we have not tried to hide the facts. Therefore, it is nothing surprising that this situation was reflected in the debate in this House. When we are in difficulties, naturally we try to use some harsh words also. As far as I am concerned, I am not hurt by those harsh words. I take it as a spur, a whipping to me, to make greater efforts for the purpose of remedying the situation. Every member was concerned with the stagnation in industrial production, particularly since 1965-66, when a recession set in after two years of consecutive drought. We have not got out of that difficult situation, and even though there has been some spurt in industrial production in some years, the tempo of industrial production has not picked up to the extent necessary. In 1973 it has almost come down to zero per cent growth.

Very many hon. Members made, if I may say so, relevant points from their point of view. But if we have to get over the situation, we have to take an over-all view and find out what are the basic causes for the stagnation, and unless we remove those basic causes, even though we may attempt to take action here and there, ultimately we may fail to attain our objective of pushing up industrial production.

Particularly with reference to the experience we have gone through during the last two or three years, in my view the basic infra-structure which is required for industrial development and industrial growth is not adequate enough. Here when I refer to the basic infrastrucure, I mean the energy which is required for the purpose of running the industry. When I talk of energy, it is represented by two commodities, namely, coal and power. Of course, transport is also involved in it.

Unfortunately, in all these three areas we are not in a comfortable position, to put it nuldly, because one affects the other. For the pupose of power production, particularly in the thermal stations, we want coal. So, unless coal is proucced, we cannot have power production. Even if coal is produced, if it is not moved to the consuming point, the power cannot be produced. If we are not able to produce coal, we cannot run our railways. So, this becomes a vicious circle and this is where we have to concentrate The Government are trying to concentrate their attention to see that a more comfortable position is reached with regard to this basic infra-structure of coal, power and transport.

Unfortunately, it is not merely a question of technical difficulties. There are also human difficulties involved it, particualrly in the railways The problem is one of labour relations, which is a human problem. To the extent it gets deteriorated, every other section will get affected. Therefore, it is necessary for all of us, particularly Members of Parliment, to take note of this situation. I am mentioning this because just now a friend gave me a notice which has been

issued by the representatives of the employees in railways that they want to go on an all India strike. What will be the consequences of that for the country as a whole will to be realized. Of course, those who are interested in chaos and fishing in troubled waters might be happy. But this is going to create a very very difficult situation for the country as a whole and for the people, and I am sure for the poorer people all the more, because the rich people can manage any situation. So, this aspect will have to be kept in mind. It will be our continuous endeavour to see that this basic infra-structure is further improved. All possible measures are being contemplated or being worked out and their implementation will have to be done in a more effective and efficient way.

Then, on parallel with this, raw materials is important for industrial production. Steel is a general raw material, which can be considered almost a basic infra-structure for industrial production. Unfortunately, there also we are facing difficulties. In regard to non-ferrous metals, the production has fallen down and, particularly, the aluminium production has gone down. So, we have to meet the situation.

I think, a pertinent question was put by the hon. Member, Shri H. M. Patel, "Your Ministry is not concerned with all the commodities. How are you going to manage it ?" It is not possible to load all the commodities on one Ministry because it will break under the weight of it. Therefore, it has to be spread out in various Ministries. What is important is to have coordination amongst the various Ministries for the purpose of achieving results. That is why, recently, a Cabinet Committee on Industrial Trade has been constituted. On some occasions, the Prime Minister also, if necessary, presides over it. Generally, the Industrial Development Minister presides over it. There, all the various bottle-necks that arise between one Ministry and another Ministry are discussed and decisions taken in an expeditious manner. About things which would have taken months and months, because we discuss various problems across the table, we take decisions then and there.

One example before me is how a decision was taken in regard to production of steel in mini-steel plants. As regards mini-steel plants, till now, there was a restriction that they could produce only ordinary steel. They could not produce any special steel or alloy steel. We have got into difficulties particularly with reference to certain types of steel which we are not able to get from integrated steel plants because they are in small quantities and they cannot plan production of those types of steel. After a full discussion, we immediately took a decision that mini-steel plants should be allowed to diversify their production and that they could produce various types of steel according to their capacity and according to their capability also. It was possible to take a decision immediately. This decision was taken only a few weeks back.

We are trying to see that instead of the old procedure of one Ministry writing to the other Ministry and the other Ministry starting noting from down below, from the Section Officer, and finally, taking months to come to a decision, we take a decision immediately by having a discussion across the table. We are trying to get over it. I am not prepared to say that we have reached the maximum efficiency. But we are in the right direction. It is by a coordinated effort that we are trying to solve the problem.

One other factor also has come into prominence during the last three or four years that industry cannot function in isolation, that it is related to agriculture more than anything else, because many of the raw materials required for our traditional industries, particularly like, textile, jute, sugar and oil, have to be provided by agriculture. Whenever there is a failure in agriculture and the raw materials are not available, automatically, these industries get affected. In the same way, agriculture today cannot function without industrial backing because it is not subsistence agricul-

[Shri C. Subramaniam]

ture. The modernised agriculture requires various industrial inputs for the purpose of increasing production in agriculture. Therefore, it is no longer possible to look at agriculture in isolation or at an industry in isolation and take decisions on the basis of plans. "This is a completely agricultural sector; this is a completely industrial sector." On the other hand, we have to take a coordinated and a well-knit decision which will take into account all the sectors of economy as a whole.

17 HRS.

In the past, we always used to say that whenever there was failure of monsoon, the agricultural production was affected. But in the last two or three years, we have come to the position where, because of monsoon failure, industrial production has been affected. About 40 per cent of electricity is produced in the hydro-electric projects. In the past when the level of industrialisation was limited and the other uses of electricity were also limited, even during monsoon periods we were able to manage. But now when it has been stretched to the utmost limit, even when there is full production, it is not adequate. And when there is shortfall in the production of electricity, immediately it affects the inductrial production; the shortfall in the production of electricity affects not only industrial production but also agricultural production bacause a large number of pumpsets today are electricity-based. Therefore, this is the sort of situation in which we are placed today. And it is by taking a comprehensive view, by taking comprehensive decisions with regard to this, that we will be able to get out of the present situation.

Today we are faced with the problem of inflation and rising prices; whether there is justification or not, prices are rising every day. And if you look into the basic cause why this inflationary trend is so pronounced now, it is mainly because of stagnation in production whereas the money supply is increasing. When money supply is increasing, if, at the same time, production also had been increasing, perhaps this type of inflation would not have been there. Therefore, industrial stagnation and stagnation in agricultural production have contributed to the inflationary situation. They affect the economy as a whole. Therefore, today if we want to get out of this situation, we have to plan in such a way that we increase our production in all sectors, be it agricultural sector or industrial sector, again in the industrial sector, whether it is large scale sector or medium sector or small scale or village industries, whether it is public sector or private sector or joint sector. This is the position with which we are confronted today. If, for any reason, the production lags behind, to that extent, naturally, the adverse factors in the economy will get more intensified and the position will become more and more difficult.

It is in this context that we have to view our industrial policy also. I think, the hon. Member belonging to the CPM party, who initiated the discussion, made a charge that there has been shameless retreat with regard to industrial licensing. I thought I had explained in this very House the stand that the Government have taken with regard to industrial licensing. The February 1973 publication has made this position definite that larger houses and the foreign-owned companies can enter only particular areas.

AN HON. MEMBER : The core sector.

SHRI C. SUBRAMANIAM : You may call it core sector or basic sector.

As I was saying, the larger houses and foreign-owned companies can enter into those areas which are more capital-intensive, which have long gestation period and which require greater expertise for the purpose of putting up those industries. It is not as if, simply because larger houses are entitled to enter these industries, automatically they are given preference. On the other hand, if there is a competition between a medium entrepreneur and a larger

house, the medium entrepreneur is selected. It is only when the medium entrepreneur is not aailable and the production of the commodity is essential for the economy that we consider either a larger house or a foreign-owned company. I would like to illustrate this with reference to cement industry which we administer in our Ministry. I think, Mr. H. M. Patel made this point; at one stage we were surplus in cement but suddenly we have gone into a state of deficit, and he asked why this had happened It is mainly because we thought that this had now become a common technology. Anybody can adopt it and, therefore, why should this be given to the larger houses? Therefore, in my view, we rightly took the decision at the time that we may try to release this industry from the larger houses participating in it and give it to the medium enterpreneurs of others who would come into the field. But, unfortunately, for two or three years nobodyelse would come forward and, therefore, a sort of stagnation set in. Then again, we reviewed the situation. It is not a charge in the policy resolution as such. This was an *ad-hoc* decision taken by the Cabinet and, therefore, the Cabinet again reviewed it and said, 'If you want to get out of this situation. it looks as if we will have to consider applications from the large houses' Even then what did we do for the purpose of 12-13 million tonnes of cement which we have got to produce during the Fifth Plan? First we said. 'What is our capacity in the public sector Cement Corporation?' And we made a realistic assessment and, we did not stop there. We added a little more than what we thought would be the capacity of the Cement Corporation and loaded it on the Cement Corporation first. Hence, as the hon. Members mentioned, six new projects came—2 in Madhya Pradesh, 3 in Andhra and other things also were mentioned. After that we gave preference to the State Industrial Development Corporations. Proposals from them for plants in the joint sector with other private entrepreneurs were given second priority. The third priority was given to such applications which came from houses which were not considered to be larger houses but medium houses. It is only after that and when there was still a ramnant we had to take a decision. Shall we face a scarcity or shall we import cement from elsewhere or shall we ask the larger houses to produce it ? Then, we thought that a rational decision in this situation would be not to depend upon imports or to face a scarcity but to make use of the larger houses for the purpose of filling the gap with regard to cement.

The same process was gone through with regard to paper production also. Now, at the level of 40,000 tonnes we have to invest Rs. 30 to 40 crores. Here also, we have now a Paper Corporation and in the Paper Corporation we have also brought in a new management. It has been possible for us to get the best man available in the paper industry. He was functioning in the private sector and we have brought him as the Chairman of our Paper Corporation. This is a healthy development which is taking place to-day for many top-level executives whom we consider to be very efficient managers, are giving up large salaries like Rs. 7000 or Rs. 10,000 and in certain cases even Rs. 12,000 and are coming over to the public sector management, receiving only Rs. 3000 or Rs. 3500. Here also as a rule we cannot go beyond the salary of a Secretary. That is how there seems to be some sort of a sanctity that nobodyelse should get a higher salary than the Secretary. But, in spite of that, many private sector management people come, not the capitalists as such but the professional managers are coming over to the public sector and therefore, in the Paper Corporation also we loaded this Corporation also we loaded this Corporation as much as possible. It is only after that we tried to find out to whom else we should give.

In that connection, I think a mention was made about the functioning of the Nepa Mills and how by just changing one man at the top we will change the whole situation. This has happend not only in the Paper Corporation but this has happend in many other units also, provided you put the proper man at the top. The whole situation dramatically

[Shri C. Subramaniam]

changes. I can give umpteen instances in the public sector. One instance which is a very remarkable thing is the Heavy Electricals. Within two years the situation has dramatically changed. The Hardwar unit which was a lame jack is now a healthy unit going forward form strength to strength. So also is the Bhopal unit and Hyderabad unit; so also is the Trichinopoly unit and...

AN HON. MEMBER : Instrumentation Limited.

SHRI C. SUBRAMANIAM : National instruments in Calcutta. We just changed it. It is now 160 per cent increase of production in one year. What was losing at the rate 40 lakhs have broken-even already. Somebody mentioned about the Hindustan Photo Films. No doubt it is going through very difficult period but I want to assure this House that it is not a question of obsolete technology. It is a question of inefficient management till now and that is why we have changed the management and just within a few months after change of the management healthy results have started coming in.

DR. KAILAS : Cement and steel is not available in NEPA Mills. Why should the public sector also stand in the queue as the private sector ? That was our difficulty, Sir.

SHRI C. SUBRAMANIAM : We are taking care of it. To be particular, the industrial project will not suffer for want of them I will come to this aspect immediately, that is to say, with regard to the steel shortage and the cement shortage. So, this is now the picture is easing and therefore while there had been stagnation, I want to point out that because of the changes taking place in the public sector, in this dark horizon there is a silver lining particularly in respect of the functioning of the public sector projects.

During 1973 there was no growth in the general industrial production but as far as public sector projects were concerned, there was 7.6 per cent growth during 1973 as compared to 1972. But in this 50 per cent weightage is given to IOC. If you remove that then the growth is about 17 per cent. This is the sort of development that is taking place within the public sector and therefore I want to give the assurance to the hon. Members that we are giving priority to public sector projects. We have made them more efficient so that there may be more and more justification to establish further industries in the public sector. That is how we are looking at it and fortunately as far as the public sector projects are concerned, no longer can the accusations be made that they continue to make losses. They have turned the corner. They are making profits. And I want to assure the House that this profits is going on increasing from year to year

SHRI K. S. CHAVDA : By converting loans into equity the public sector has shown a profit. It is merely a book-entry.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It is not with reference to financial profits alone that I am talking I am talking with regard to utilisation in road terms, how much we are producing. Therefore it is not a question of mere juggelery, it is actual, physical production, and how much they are producing in a particular industrial unit in the past, and how much they are producing today. So, as far as the public sector projects are concerned, with this improved management as a whole and improved management personnel we will continue to make progress Of course there are certain limitations with regard to expansion of the public sector and every industrial activity because it is just not possible. Let us stabilise this increase, then you can go further.

And then the question of nationalisation comes now and then and then one asks, why don't you nationalise all the 75 or 80 industrial course. Sometimes the trouble starts as soon as you nationalise. This is the case. This cannot be done unless such conditions are created there. If you are getting rid of you troubles well and good. But what is the use of advising that you go on and nationalise more and more

and inviting more and more trouble?

This is the sort of thing, particularly, the hon. Members from this side of the House will have to take note of. If they are really interested in the nationalisation, let them make the public sector projects and other nationalised projects a success. That can be done provided they give their wholehearted cooperation with regard to the labour relations.

On the other hand they want to play politics more and more, particularly, in the public sector projects. Those persons who plead for the public sector projects are most prominent in playing politics in the public sector projects This is the position with which we are concerned. Therefore, I would request the hon. Members of my party also to make a note of this thing if they are saying that larger houses should be immediately liquidated —I wish we are in such a position—we should be in that position. Unfortunately we are not in that position. So, till then, we have got to utilise these larger houses in certain areas at least for more and more production. When we talk that others should come and take over the production of various commodities, it just does not happen overnight unless we create circumstances for the purpose of helping the new entrepreneurs, particularly, the middle and smaller men. Unfortunately, these facilities were not available to them till now. That is why we have appointed a Committee under the chairmanship of Shri Bhatt. He is the Chairman of the Investment Centre. That Committee has made recommendations with regard to the various steps to be taken in regard to new institutions, consultancy services by the financial institutions in the States. We have already circulated a list to the State Governments and we discussed the same with them at the Industries Minister's Conference. Therefore, during the Fifth Plan, we should create more and more conditions for enabling the newcomers' being introduced in the field so that they become more and more broadbased rather than getting concentrated in a few hands. That is how we are going to get over the difficulty. Ultimately we will have to have some sort of control over the private sectors, particularly, over the larger houses. In the national interest it has to be done. That is under the consideration of the Government. I am not in a position to tell you what positive steps we are going to take because, it is still in the process of consideration. That is very much in our minds. It is in that context that I want you to look into the 1974 projects. Some people accuse us of an optimistic view being taken. Optimistic view is also taken subject to certain conditions. Take for example the industrial production which is stagnating. I asked the office to make an assessment of the industries which constitute the industrial production index. You all know that this was on the basis of the industries that existed in the year 1960-61. Public sector undertakings' production did not come into the index of industrial production. We are making a new exercise to base the index on the industries that existed in 1968. Perhaps, the hon. Members might ask me as to why is it then that we are talking in terms only of traditional industries and other industries that came into existence upto 1960-61.

With regard to this, we find no imports of raw materials are required for industries which contribute to 63% of the industrial growth according to the weightage given. That all depends upon the availability of indigenous rew materials. There is no question of the raw materials becoming scarce at all because of the foreign exchange situation. If that be so, then we should be able to break the coal position, power position as also transport position which we have got to-day. Otherwise, the nation itself will break down. With the increased availability of raw materials like cotton, jute, sugar-cane and various other things, the production is bound to go up. That is why I say that taking into account the difficulties experienced in the matter of foreign exchange, about which I shall deal a little later, we have taken an optimistic view. And if we are able to manage this sector, at least, in the proper manner, we would

[Shri C. Subramaniam]

be able to show a better level of industrial production and a better industrial growth. It is on that basis we have taken an optimistic view. Some hon. Members feel we should give the most pessimistic view and make people more frustrated. We have to point out to the optimistic points of view which could be taken and the steps to be taken for implementing that. That is more important rather than saying you have taken an optimistic view. We will see that steps are taken to increase the production of coal, steel, transport and power.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara) : How can you manipulate the monsoons?

SHRI C. SUBRAMANIAM : The production of power will increase from 600MW to 1000MW.

It is a question of managing this system so that we may not further deteriorate. So, it is not a wishful thinking alone but it is based on broad facts. I agree that there will have to be a better management of the system.

Sir, mention was made about the new industrial licensing procedures and many Members complained that the old delays have continued. I am sorry to say that they have not looked into the facts. Since this new arrangement came into effect from 1st November a weekly review of the situation is made. When we say it should be disposed of within 90 days it is not just 90 days and then left the whole system to drift at the end of the 90 days. For every step we have fixed a time-limit and within the time-limit they have to—whether it is DGTD or other sister Ministries or the Textile Commissioner—send their assessment. Fortunately, during the last five months the system has been keeping to its target and about 95 per cent of the total applications have been disposed of before 90 days time-limit. The remaining five per cent will be cleared in the next few weeks. So, it is no use saying it is only a paper scheme. I am quite confident that this 90 days time-limit and 150 days time-limit for MRTP applications can be kept up and will be kept up.

I know the hon. Members are concerned about the pre-November applications. As on 1.11.1973 when we introduced this system there were 3848 pending application, and by 1.3.1974 this has been reduced to 2071. They have been disposing of 300 to 350 applications per month. This is the rate they have kept up If we go in the same way the remaining 2071 applications could be disposed of in the next 6 months. Of course, some hard cases will keep on hanging but by and large these applications would be disposed of . Then it is a routine of the new indust ial procedures keeping to this 90 days limit. It is not merely issuing a paper which is important. After all, of this paper can solve the problems, we can issue any number of letters of intent and any number of licences also and say that we have issued so many papers and therefore the problem is solved. Unfortunately till now we had not kept track of what was happening to these papers, and that was how some people were able to corner it also by getting a Letter of Intent and sitting over it for years together so that other also did not come into the picture. Now, we have made it obligatory for every Letter of Intent and licence, in fact, we have provided a form along with that where the person has to give an account of the steps taken during those six months. If they do not provide the statistics, it means that they are not taking steps; then, we would cancel the letter of intent or the licence and we give them an opportunity to explain why they have not done it. So, continuous monitoring from the time of the issue of the paper till it goes into production and becomes a production unit has been built into this new procedure. This is how we are trying to see that not merely there is expeditious disposal of applications but the applications come to fruition as producing units. This is the sort of transformation which has come about, and I am sure that there are many faults and deficiencies in the functioning of my

Ministry and I am quite conscious of them, but still not the sort of deficiencies which some Members from Bihar had talked about and regarding which he had also levelled all sorts of charges there. I wish he has a better view and he takes a more reasonable view of the steps taken within the Ministry. If he could give me instances and point out any injustice done to anybody or any wrong which is happening anywhere, I am prepared to take immediate steps.

AN HON. MEMBER : A single Member from Bihar.

SHRI C. SUBRAMANIAM : But even a single Member counts, particularly when he speaks here. Perhaps, he has been briefed by somebody else; otherwise, he cannot speak like this. Therefore, there are interested parties to brief in that way. But if he really feels that there is something wrong, I am prepared to sit down with him and discuss the matter.

SHRI DHAMANKAR : Why attribute motives to Members ?

SHRI C. SUBRAMANIAM : Various suggestions were made, particularly by my hon. friend Shri K. S. Chavda. He made a very useful suggestion from his point of view and asked why diversification should not be allowed so that everybody could be allowed to increase production by 40 per cent which according to him should not be allowed to the foreignowned companies but to everybody also including the large houses.

SHRI K. S. CHAVDA : My point was this.....

SHRI C. SUBRAMANIAM : Let him kindly hear me. After that, he can get up.

SHRI K. S. CHAVDA : There is a wrong understanding regarding the point that I had made.....

SHRI C. SUBRAMANIAM : I have understood him fully.

SHRI K. S. CHAVDA : I shall put my question after he replies.

SHRI C. SUBRAMANIAM : As a matter of fact, we have given even now 25 per cent diversification with regard to the various industries permitting them to increase their production by 25 per cent, and that is applicable particularly to select industries, as far as the larger houses and foreign companies are concerned; they are not allowed to expand in all sorts of industries they are having but only in certain specific industries, and it is only on that basis that this diversification and increase in capacity by 25 per cent has been allowed. The hon. Member seems to think that instead of 25 per cent it should be 45 per cent. So, it is only a question of degree, but in principle it has been accepted.

SHRI K. S. CHAVDA : Why has this concession been given to foreign firms and large industrial houses under press note No. 3(3/165) CS-III dated 27-7-1969 ? I have written a letter to him already. That is why I am referring to that ?

SHRI C. SUBRAMANIAM : I cannot remember these obliques and dashes off hand. I shall look into it

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : In the case of detergents, expansion has been allowed very recently to the Lever Brothers.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It is not merely the number of applications which make the position a little bit optimistic but I have got some figures also. There is no evidence from the various indicators that we have that the pace of new investments incoming up is showing an increasing trend. In the first eleven months of 1973-74, capital goods imports were approved of for Rs. 152 crores as compared to Rs. 113 crores in the corresponding period of 1972-73. In the first six months of 1973-74, 1,824 companies were registered with total authorised capital of Rs. 554 crores as against 1437 companies with an authorised capital of Rs. 176 crores in the first half of 1972-73.

[Shri C. Subramaniam]

The term-lending institutions, IDBI, ICICI and State Finance Corporations sanctioned loans for Rs. 178 crores and made disbursements for Rs. 111 crores in the first half of 1973-74 as compared to Rs. 137 crores sanctioned and Rs. 79 crores disbursed in the first half of 1972-73.

Therefore, the investment climate also has, in my view, improved, to a certain extent.

SHRI K. S. CHAVDA: You have not replied to my point.

SHRI C SUBRAMANIAM : A point was made with regard to financial institutions, that they take their own time. That is why now they are linked up with new industrial licensing procedures also. Once in a month, they come over to Delhi, sit along with our Secretariat officers and try to find out what are the capital goods clearances which have to be made and on what basis so that loans could be sanctioned on an expeditious basis. Therefore, a certain co-ordination and linkage has been brought into existence with the licensing procedure machinery particularly with regard to capital goods.

This development has got to take place keeping in view the need for bringing about regional balance. This is a well-accepted principle. But unfortunately, it has not been possible to achieve it. Particularly when we take measures for the speedy implementation of projects, we have to see that this balance is restored. We are very conscious of it, but here there is competition for the purpose of getting districts declared as backward. I wish a mere declaration of backwardness could solve the problem. The fact is that in spite of this declaration, the progress made has not been quite satisfactory.

Even though over the years I find that the number of licences/letters of intent with reference to backward areas has been increasing, it has only creepingly increased, not in a very dynamic way. Therefore, we have to take into account the factors which contribute to the hesitancy of industry to go to these backward areas. This is where the growth-centres concept is an important point.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Why not use the licensing procedure as a leverage ?

SHRI C. SUBRAMANIAM : You can. You can take the horse to the water, but cannot force him to drink. Unless some facilities are available, you cannot expect them to just go there and establish industry on virgin land. That is why the concept of growth centres has been accepted. We are working out projects in these backward areas, identifying growth centres and providing infra-structures facilities for the purpose.

In this connection, I want to make one thing quite clear. Just pushing one big industry into a backward area is not going to remove its backwardness. If that were so, Bihar should be the most developed State because we have got so many big public sector industries located there. Among the States, Bihar has the largest number of public sector units

SHRI CHIRANJIB JHA (Saharsa): South Bihar, not North Bihar.

SHRI C. SUBRAMANIAM : Take South Bihar. But is it reflected in progressiveness or advancement ? Absolutely not. Therefore, to think in terms of pushing a few industries into backward areas and making them advanced will be to indulge in an illusion. That is why more comprehensive development is required. That can happen only on the basis of area development, agricultural development, development of industries based on agricultural raw materials, processing of agricultural materials producing the various inputs required.

The finest example for us to follow—we need not go to Sweden or other foreign countries—is the pattern of Punjab. Even though there is no worthwhile big public sector industry located in Punjab today, it has the highest per

capita income which in the last ten years it has doubled.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : They are the best human material.

SHRI C. SUBRAMANIAM : We should also try to become a little better human material instead of blaming others. This is what has got to happen. While the human material may be inadequate, we can at least copy what has been done by others.

Therefore, this is how we have got to approach the subject. In that also, as I am going to speak later, we are going in for improved science and technology which will help backward areas in getting over their backwardness.

With regard to the small scale industries, Khadi and Village Industries Commission, coir industry and other such industries, my colleague has dealt with them elaborately, and therefore, I am not going into those things now. As I have already stated with regard to the public sector projects in my own Ministry, they are all picking up. No doubt there are some sick babies and we are trying to nurse them, but on the whole, as I have already stated, the public sector is projecting a much better image now.

I will now come to the other important subject, namely, science and technology. I am glad that at least a few Members took notice of this very important aspect of industrial development. I think Dr. Kailas started the process and then Shri Jagannath Rao and a few others also mentioned about it. Ultimately, it is not by getting technology imported, if necessaary in the initial stages, that any nation is going to become industrially advanced. If today there are countries which have made advance in the industrial sector and the agricultural sector also, it is a reflection of their scientific and technological competence, and as long as we continue to be scientifically and technologically incompetent, comparatively, then, to that extent, however much we may take measures, the development cannot match the requirements. That is why we have given importance to the development of science and technology, not the general development of science and technology, but science and technology for the purpose of reaching our socio-economic goals. This is the exercise which the National Committee on Science and Technology has made. I do not know how many Members had looked into it. Only yesterday I laid on the Table of the House the first and second volumes of the draft plan on science and technology. I would request the hon. Members, at least such of the Members as are interested in it to take hold of the volumes, go through them and I am sure this is the first exercise which is likely to bring out the defects and deficiencies and I would like to have the suggestions from the hon. Members with regard to this. I am circulating it to the entire scientific community also for the purpose of getting their suggestions. Nearly 2,000 scientists and technologists were involved in evolving this plan. It is not just an exercise of ten wise men. On the other hand, experts in every field were assembled and they have given us the plan with regard to each sector. Nearly 2,000 scientists and technologists were involved in it.

Today, what is important is, what priority we are going to give to the development of science and technology, because, in our difficult situation where resources are scarce, we seem to think that perhaps this is a luxury expenditure. On the other hand, it is only the application of science and technology which would enable us to utilise whatever resources we have to the maximum advantage. It is from that point of view that we have to approach the science and technology plan and it is from that aspect that the NCST draft plan. will have to be looked into.

I would like to place before the House certain high-lights with regard to this science and technology plan. What are the priorities we have given in it ? The first point is,—It is not because I was

[Shri C. Subramaniam]

the Minister of Food and Agriculture for some time that I say this—in our economy, agriculture has got a pre-eminent place, and without that, we are not going to make any progress whatsoever. Therefore, we have given importance, as far as science and technology is concerned, to agriculture as the first priority. In that, it is not merely a question of more and more production. In our country, we produce, as a matter of fact, enough. If we avoid the wastages that happen after the harvest, we will be a surplus country. Even a very optimistic estimate shows that in foodgrains we lose about 10 million tonnes by way of wastages at various points. Therefore, post-harvest technology is as important as the technology preceding it. That is the main areas to which we have given emphasis.

The second area now is fuel and energy. As you all know, a new situation has come about because of the oil crisis. In my view, this is a blessing in disguise. I told another audience, a scientist audience, that wherever we were in a position to get cheap articles from abroad, we have been lulled into sleep and later on we have come into trouble.

We had PL 480 foodgrains. Therefore, we did not attach sufficient importance to the development of agriculture because we were getting cheap food from abroad. Somebody produced it for us and we got it here. Till we took a decision that we would get out of this and launch a new programme of modernising agriculture on the basis of application of science and technology our agriculture continued to be subsistent agriculture, without the necessary

PROF. MADHU DANDAVATE: I would like to seek a clarification The total allocation for research and development has not been even .5% of the GNP. Would you insist that....

SHRI C. SUBRAMANIAM: Let me elaborate this a little bit, before I come to that point.

In the same way, in 1962-64, when I was in charge of Mines and Metals, we took up various projects in the development of production of coal and utilisation of coal by gasification, low temperature carbonisation etc. But, all that were put into cold storage because crude oil was available at 80 cents a barrel. Because crude oil was available at 80 cents a barrel, we did not attach importance to exploration of our own resources in this country We thought this will be more costlier. Now, we have been taken unawares.

Take for example Cotton. Sudanese cotton or Egyptian cotton was available at Rs. 1500 per tonne. Since we were able to get high staple cotton from abroad at a cheap price, we did not attach importance to the development of production of cotton. But, it is now Rs. 16,000 per tonne. The development in the production of cotton is much of relevance now, than ever before That is why, new varieties are coming up.

We thought that since there are other rich nations which have achieved higher levels of scientific research and development, we could just make the payment and take the knowhow. In my view, it is this attitude which has brought about—this is one of the contributing factors—industrial stagnation. As a nation, we did even have the competence to absorb the technology that we were importing. We were not able to adapt the technology for the raw materials available within the country. We always became dependent on imported components or imported raw materials. This is how, we have become more and more not self reliant, but, dependent on foreign sources. Therefore, if you think in terms of cutting foreign aid, you are not going to achieve this by just your resolution. It is only by development of science and technology that you would be able to do this.

Therefore, now, we have given importance to the development of coal technology, so that we could use coal, as much as possible, as a source of energy

and as a fuel. We have also to develop various other alternative sources of energy. For example, solar energy. It was just a toy which was being used for coooking and other purposes. The whole world is now realising that perhaps this is one of the sources of energy, which could be channelised in a very big way. We should take up this work also. Then, there is tidal energy, geothermal energy and various other developments in the field of energy and fuel.

After that, we have given importance to, what we call, in house research and development for each industrial unit for the purpose of increasing production, improving technology, adapting the technology and further developing that technology so that they are able to reach higher levels of technological efficiency. So, this is how we have planned taking into account the requirements. In this also, we are moving into collaboration with other countries. Till now, we were getting collaboration in the field of industrial development. We took knowhow and equipments from abroad and established industries here. Instead of that, we have moved into the area of collaboration in the field of science and technology and research and development. We have entered into very meaningful and extensive agreements with USSR and other socialist countries, France, West Germany, U.K. and various other countries which are in a position to help us and willing to help us. From a period of industrial collaboration, we are moving into a period of scientific and technological collaboration for development within our own country, because if we start doing everything anew, it will take perhaps another generation. Therefore, we should take advantage of the advances which have already taken place and build upon them. This is how the science and technology plan has been finalised with regard to each sector of industry. The whole area has been divided into 24 sectors, each sector having been further divided into sub-sectors. This is how it is placed before the House in two volumes. To back this up, we have got a huge amount of printed literature—a cartload of it—and only members interested in each area would get it. I am glad some of the publications are selling like hot cake. A large number of copies of the *Chemical Industry—Draft Plan* have been sold away.

Mr. Dandavate asked, what are the financial magnitudes of this and what is our target with regard to the expenditure on R & D? As a matter of fact, at Government level a policy decision has been taken with regard to the global requirements also that every country should spend at least 1% of its GNP for R & D activities. It is from that point of veiw that we identified in the NCST projects worth Rs. 1725 crores. But unfortunately the resources are not adequate and therefore, this has been pruned to Rs. 1033 crores. Fortunately, our scientists have given priorities. They have worked out, if this is the resources, these should be taken. If the resources are short, these should be left out and these should be taken up. Like that priorities A, B, C etc. have been indicated. This is how we are going forward. I am little disappointed because as against Rs. 1033 crores, only Rs. 100 and odd crores have been given for 1974-75. But I am quite confident of persuading the Planning Commission, the Finance Ministry and various other ministries that we should expand our area of scientific and research activities because that alone would save us from stagnation and dependence on foreign countries and make us a self-reliant, prosperous and dynamic nation. Ultimately it is the human material which counts. Fortunately, in the area of science and technology, we have the highest talents available not only in the country but functioning outside also. Often it is asked, why can't we get back all our scientists from abroad? As a matter of fact, it is not as if they are getting 20,000 or 30,000 dollars abroad and that is why they do not went to get back. They are not coming because there are not job oportunities for them. It is not our intention to ask every scientist abroad to return. We have to identify the talent available and see

[Shri C. Subramaniam]

in what area he can function. Then we should see whether that area is relevant to our plan. In that relevant area, it will be our endeavour to get back all our young men who are abroad to help the country to go forward. The future is hopeful not mainly because of the political complexion with which we are faced. It is mainly because of the large reservoir of scientific and technological talent which we have, which give us a new hope that we would not only be able to survive but march forward.

SHRI K. S. CHAVDA : Will you allow diversification to Indian firms with minor balancing euipment and imported raw materials to the tune of 40% of the liceqnsed capacity for conversion of obsolete items into new articles

SHRI C. SUBRAMANIAMI : We are interested in the Indian sector. It is not as if we are fond of the foreign sector and Mr. Chavda alone is interested in the Indian sector. We are giving all assistance to the Indian sector. It is not 40% but 25%. I will consider whether this can be further improved.

MR. CHAIRMAN : There are some cut motions, all in the name of Dr. Sardish Roy. I will now put cut motions Nos. 29 to 45 to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR CHAIRMAN : I will now put the demands to the vote of the House. The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 57, 58 and 59 relating to the Ministry of Industrial Development."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : I will now put the damands relating to the Department of Science and Technology to the vote of the House. The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 99, 100 and 101 relating to the Department of Science and Technology."

The motion was adopted.

[The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below-Ed.]

DEMAND No. 57—MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

"That a sum not exceeding Rs. 1,94,26,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Ministry of Industrial Development.' "

DEMAND No. 58—INDUSTRIES

"That a sum not exceeding Rs. 4,07,52,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 35,27,37,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Industries.' "

DEMAND NO. 59—VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES

"That a sum not exceeding Rs. 23,52,84,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 44,08,88,000 on Capital Account be granted to President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Village and Small Industries'"

DEMAND NO 99—DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

"That a sum not exceeding Rs 4 96,98,000 on Revenue Account and not exceeding Rs 1,10,40,000 on Capital Account be granted to the President, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975 in respect of 'Department of Science and Technology''

DEMAND NO 100—SURVEY OF INDIA

"That a sum not ecxeeding Rs 10,44,60,000 on Revenue Account be granted to the President, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Survey of India."

DEMAND NO 101—GRANTS TO COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUTRIAL RESEARCH

"That a sum not exceeding Rs. 25,10,02,000 on Revenue Account be granted to the President, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of 'Grants to Council of Scientific and Industrial Research'."

17.53 HRS.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

MR. CHAIRMAN : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 60 to 62 relating to the Ministry of Information and Broadcasting, for which six hours have been allotted.

DEMAND NO. 60—MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

'That a sum not exceeding Rs. 26,66,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of Ministry of Information and Broadcasting'."

DEMAND NO 61—INFORMATION AND PUBLICITY

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 9,98,84,000 on Revenue Account and not exceeding Rs 1,72,92,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of Information and Publicity'."

DEMAND NO. 62—BROADCASTING

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs 16,99,69,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 14,68 33,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1975, in respect of Broadcasting'."

Hon. Members present in the House who desire to move their cut motions may please do so.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : (Diamond Harbour) : I beg to move :

"That the demand under the head Ministry of Information and Broadcasting be reduced by Rs. 100."